सीएचआरआई, 2019

भारत में पुलिस संगठन

CHRI
Commonwealth Human Rights Initiative

राष्ट्रमंडल देशों में मानवाधिकारों को व्यावहारिक रूप में हासिल करने के लिए कार्यरत

dkEeuoYFk áeu jkbVl bfuf'k,fVo

राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल (सीएचआरआई) एक स्वतंत्र, गैर–पक्षपातपूर्ण, अंतर्राष्ट्रीय गैर–सरकारी संगठन है, जो राष्ट्रमंडल के देशों में मानवाधिकारों के व्यावहारिक अहसास के लिए कार्यरत है। सन् 1987 में कई कोम्मनवेल्थ पेशेवर संगठनो ने इस विचार से सी एच आर आई की स्थापना की, कि कोम्मनवेल्थ के भीतर मानवाधिकारों के मुददे पर प्रयाप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि, कोम्मनवेल्थ ने सदस्य देशों को निर्धारित मूल्यों और कानूनी सिद्धांतो का एक साझा विज्यस्त प्रदान किया है, जिसके अनुसार सदस्य कोम्मनवेल्थ देशों को काम करना था।

सीएचआरआई के उद्देश्य कोम्मनवेल्थ सिद्धांतों, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणाओ और अन्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकार उपकरणों के साथ–साथ कोम्मनवेल्थ सदस्य राज्यों में मानवाधिकारों का समर्थन करने वाले घरेलू उपकरणों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है।

अपनी रिपोर्ट और आवधिक जाँच के माध्यम से, सीआरआई लगातार कोम्मनवेल्थ देशों में मानव अधिकारों के प्रगति और असफलताओं पर ध्यान केंद्रित किये हुए हैं। मानव अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने के दृष्टिकोण और उपायों की सलाह देते हुए, सीआरआरआई कोम्मनवेल्थ सचिवालय, सदस्य सरकारों और नागरिक समाज सांगठनों को संबोधित करता है। अपने सार्वजनिक शिक्षा कार्यक्रमों, नीतिगत संवाद, तुलनात्मक शोध, वकालत और नेटवर्किंग के माध्यम से, सीआरआई का दृष्टिकोण पूरे प्राथमिक मुद्दों के आसपास उत्प्रेरक के रूप कार्य करना है।

सीएचआरआई नई दिल्ली, भारत में स्थित है, और इसके अन्य कार्यालय लंदन, ब्रिटेन और अक्क्रा, घाना में भी हैं।

vrjk"Vh; lykgdkj vk;kx% यशपाल घई– अध्यक्ष

lnL;% एलिसन डक्सबरी, वजाहत हबीबुल्लाह, विवेक मारु, एडवर्ड मोर्टिमर, सैम ओकउड़जेतु, बेरिएव के लार्ड कार्लाइल और संजोय हजारिका।

dk;dkfj.kh lfefr ¼Hkkjr½% वजाहत हबिबुदुल्लाह– अध्यक्ष

lnL;% बी के चंद्रशेखर,जयंतो चौधरी, माजा दारुवाला, नितिन देसाई, कमल कुमार, पूनम मुटरेजा, जैकब पुत्रोंसे, विनीता राय, निधि राजदान, ऐ पी शाह और संजोय हजारिका ।

dk;dkfj.kh lfefr ¼?kkuk½% सैम ओकउड़जेतु, अध्यक्ष

सदस्य – आकोटो आमपाव, यशपाल घई, वजाहत हबीबुल्लाह, बेरिएव के लार्ड कार्लाइल, कोफी क्वाशिगाह, जूलियट तुआकली और संजोय हजारिका।

dk;dkfj.kh lfefr ¼;w d½% जोआना एडवर्ट–जेम्स, अध्यक्ष

lnL;% रिचर्ड बॉर्न, प्रलब बरुआ, टोनी फोरमैन, नेविले लिंटन, सुज़ैन लैम्बर्ट और संजोय हजारिका।

vrjk"Vh; fun'kd% संजोय हज़ारिका

ISBN: 978-93-81241-63-9

Commonwealth Human Rights Initiative

lh,pvkjvkÃ gMDokVl] uÃ fnYyh
55 ऐ, थर्ड फ्लोर
सिद्धार्थ चैम्बर्स
कालू सराय, नई दिल्ली 110 017
इंटेल: +91 11 4318 0200
फैक्स: +91 11 2686 4688
ई–मेल: info@humanrightsinitiative.org

lh,pvkjvkÃ ynu
रूम न. 219, स्कूल ऑफ एडवांस्ड स्टडी
साउथ ब्लॉक, सीनेट हाउस
मलेट स्ट्रीट, लंदन WC1E
7HU, यूनाइटेड किंगडम
टेल: +44(0) 207 664 4860
फैक्स: +44(0) 207 862 8820
ई–मेल: chri.admin@sas.ac.uk

lh,pvkjvkÃ vÝhdk] vØk
हाउस नं. 9, समोरा मकेल स्ट्रीट
एसाइलम डाउन, अपोजिट बेवर्ली
हिल्स होटल नियर ट्रस्ट टावर्स,
अक्रा, घाना
टेल/फैक्स: +233 302 971170
ई–मेल: chriafrica@
humanrightsinitiative.org

Hkkjr esa iqfyl laxBu

}kjk 'kksèk vkSj fyf[kr

thih tks'kh

सीएचआरआई कमल कुमार को उनके अमूल्य योगदान के लिए
धन्यवाद देना चाहता है

fo"k; lph

çLrkouk **VIII**

1. ifjp; 1

1-1 jktuhfrd çkQkby 1

1-2 foèkku 'kfä ;k 1

1-3 vkijkfèkd U;k; ç.kkyh 2

1.3.1 संविधान के तहत नागरिक अधिकार 2

1.3.2 आपराधिक कानून 3

1.3.3 आपराधिक न्याय प्रक्रिया 4

1.3.4 न्यायालय 5

2. jkT; ifyl Qkl 6

2-1 fofoèkrk e ,drk 6

2-2 ifyl ij vèkh{k.k 6

2-3 ifyl inkuØe 7

2.3.1 रैंक संरचना 7

2.3.2 राज्य पुलिस बल में रैंक–वार ताकत 7

2.3.3 रैंक के बैज 9

2.3.4 पुलिस पदक 10

2-4 ifyl 'kfä 11

2.4.1 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में पुलिस शक्ति 11

2.4.2 पुलिस–जनसंख्या और क्षेत्र अनुपात 13

2.4.3 पुलिस जनशक्ति में वृद्धि 13

2.4.4 राज्य में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व पुलिस बल 14

2.4.5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महिला पुलिस 15

2.4.5.1 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महिला पुलिस की ताकत 15

2.4.5.2 महिला पुलिस में वृद्धि 16

2.4.5.3 बल में महिला पुलिस की ताकत में रैंक–वार वृद्धि 17

2-5 lxBukRed ljpuk 18

2.5.1 फील्ड स्थापना 18

2.5.1.1 इकाइयां 18

2.5.1.2 जिला पुलिस 19

2.5.1.2.1 जिला अधीक्षक कार्यालय में शाखाएं 19

2.5.1.2.2 पुलिस लाइन 19

2.5.1.2.3 जिला पुलिस अधिकारी 19

2.5.1.2.4 जिला पुलिस अधीक्षक के कर्तव्य 20

2.5.1.2.5 जिला स्तर पर दोहरी नियंत्रण प्रणाली 20

2.5.1.2.6 पुलिस आयुक्त प्रणाली 21

2.5.1.2.7 जिला सशस्त्र रिजर्व 23
2.5.1.2.8 पुलिस स्टेशन 24
2.5.1.2.8.1 पुलिस स्टेशनों की संख्या 24
2.5.1.2.8.2 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में महिला पुलिस स्टेशन 24
2.5.1.2.8.3 पुलिस स्टेशन की भूमिकाएं और कार्य 25
2.5.1.2.8.4 पुलिस स्टेशन कार्यकर्ताः उनकी ताकत और कर्तव्यों 25
2.5.1.2.8.5 पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड्स 28
2.5.2 पुलिस मुख्यालय 30
2.5.2.1 पुलिस मुख्यालय की भूमिका और जिम्मेदारियां 30
2.5.2.2 पुलिस बल के प्रमुख का चयन और कार्यकाल पुलिस मुख्यालय में 31
2.5.2.3 विभाग/शाखाएं 31
2.5.2.3.1 आपराधिक जांच विभाग 32
2.5.2.3.2 खुफिया विभाग 32
2.5.2.3.3 सशस्त्र पुलिस 32
2.5.2.3.4 रेलवे पुलिस 33
2.5.2.3.5 राज्य अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो 33
2.5.2.3.6 प्रशिक्षण निदेशालय 34
2.5.2.3.7 आतंकवाद विरोधी दल / सेल 34
2.5.2.3.8 पुलिस प्रतिष्ठान बोर्ड 35
2-6 ifyl dk dr0; vkj ftEenkfj;k 36
2.6.1 पुलिस अधिनियम में प्रवेश के रूप में, 1861 36
2.6.2 राष्ट्रीय पुलिस आयोग 36
2.6.3 सोराबजी कमेटी की सिफारिश 36
2.6.4 पुलिस के लिए आचरण संहिता 37
2.6.5 पुलिस अधिकारियों के लिए व्यवहार संहिता 38
2-7 Hkrê 41
2.7.1 कॉन्स्टेबल की भर्ती 41
2.7.2 पुलिस के सब–इंस्पेक्टरों की भर्ती 44
2.7.3 पुलिस के उप अधीक्षक की भर्ती 46
2.7.4 भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) की भर्ती 47
2-8 ifyl çf'k{k.k 48
2.8.1 कांस्टेबल का प्रशिक्षण 48
2.8.2 सब–इंस्पेक्टरों का प्रशिक्षण 49
2.8.3 आईपीएस अधिकारियों का प्रशिक्षण 50
2.8.4 प्री–प्रमोशन कोर्स 51
2.8.5 रिफ्रेशर / विशिष्ट पाठ्यक्रम 51
2.8.6 कुछ केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण संस्थान 52
2.8.7 पुलिस प्रशिक्षण पर व्यय 53
2-9 jkT;k vkj dæ 'kkflr çn'kk e ifyl 0;; 54
2.9.1 पुलिस बजट पर राज्य के बजट और व्यय 54
2.9.2 पुलिस व्यय में वार्षिक वृद्धि 56

3. Hkkjr esa Q,jfld foKku 57
3-1 egRoiw.kZ ,frgkfld LFkyksa 57
3-2 jkT;ksa esa Qksjsfld foKku ç;ksx'kkyk,a 57
3-3 dsaæ ds rgr Qksjsfld foKku ç;ksx'kkyk,a 58

4. iqfyÇlx esa dsaæ dh Hkwfedk 59
4-1 laoSèkkfud çkoèkku 59
4-2 x`g ea=ky; dh Hkwfedk 59
4-3 Hkkjrh; iqfyl lsok 60
4-4 dsaæh; iqfyl laxBu ¼lhihvks½ 61
4.4.1 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) 61
4.4.1.1 असम राइफल्स 62
4.4.1.2 सीमा सुरक्षा बल 63
4.4.1.3 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 65
4.4.1.4 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 66
4.4.1.5 भारत–तिब्बती सीमा पुलिस 68
4.4.1.6 राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड 69
4.4.1.7 सशत्र सीमा बाल 69
4.4.1.8 सीएपीएफ की वृद्धि 70
4.4.1.9 सीएपीएफ में महिलाएं 71
4.4.1.10 सीएपीएफ पर व्यय 71
4.4.1.11 भारत रिजर्व बटालियन की स्थापना 72
4.4.2 अन्य केंद्रीय पुलिस संगठन 72
4.4.2.1 पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो 72
4.4.2.2 केंद्रीय जांच ब्यूरो 73
4.4.2.3 समन्वय निदेशालय, पुलिस वायरलेस 75
4.4.2.4 खुफिया ब्यूरो 76
4.4.2.5 राष्ट्रीय अपराध रिकॉड्र्स ब्यूरो 77
4.4.2.6 लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय संस्थान अपराध विज्ञान और फोरेंसिक विज्ञान 78
4.4.2.7 राष्ट्रीय जांच एजेंसी 79
4.4.2.8 सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी 80

5. jkT; iqfyl Qkslsl dk vkèkqfudhdj.k djus ds fy, ;kstuk 82
5-1 ;kstuk ds mís'; 82
5-2 laf{kIr bfrgkl 82
5-3 dfe;ka 84
5-4 lkjka'k 85

6. lR; vijkèk dh igyh lwpuk fjiksVZ vuqyXud ds rgr fjiksVZ dh xÃ èkkjk 154 vkijkfèkd çfØ;k lafgrk 86

çLrkouk

हालाँकि पुलिस राज्य की सबसे ज्यादा दिखाई देने वाली बल है, तब भी जनता को भारत में विभिन्न पुलिस बलों– राज्य और केंद्र की आंतरिक संरचना और संगठन के बारे में बहुत कम जानकारी है। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि पुलिस बल का संगठन किस प्रकार किया जाता है, कर्मचारी, शासन, वित्त की व्यवस्था किस प्रकार की जाती है और इसे कैसे चलाया जाता है; या आकार, दायरे और जनादेश के सदंर्भ में विभिन्न पुलिस संगठनों में क्या अंतर है। जानकारी की यह कमी न केवल जनता और पुलिस के बीच की खाई को बढ़ाती है, बल्कि यह सामान्य नागरिकों के लिए इस बात को और भी मुश्किल बना देती है कि वह पुलिस को उसके कार्य के लिए जिम्मेदार ठहरा सके।

इस सूचना अंतराल को भरने के लिए कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (सीएचआरआई) ने इस पुस्तिका का पहला संस्करण 'भारत में पुलिस संगठनः कुछ मौलिक जानकारी 2002' प्रकाशित किया। हमारा उद्देश्य अन्य बातों के साथ–साथ राज्य और केन्द्रीय बल, दोनों की पुलिस संरचना और संगठन के सभी पहलूओं जैसे कि रैंक संरचना और कर्तव्य, आंतरिक पदानुक्रम, भर्ती, प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण को स्पष्ट करने के लिए एक सुलभ और व्यापक संसाधन प्रदान करना था।

2002 से, पुलिस बलों में इनमें से अधिकांश क्षेत्रों में कई नए विकास और बदलाव आए हैं। तेरह साल बाद, सीएचआरआई ने इस बदलाव को दर्शाने के लिए पुस्तिका को अद्यतन किया है। हालांकि इसका पहले संस्करण पर बड़े पैमाने पर मॉडलिंग किया गया था, भारत में पुलिस संगठन के इस नए 2015 संस्करण में एक समृद्ध और यहां तक कि अधिक व्यापक संसाधन प्रदान करने के लिए अतिरिक्त जानकारी दी गई।

निःसन्देह उपलब्ध जानकारी में भी 2002 से अब तक काफी सुधार हुआ है। पारदर्शिता अब आदर्श है। 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम के पारित होने के साथ, सभी सार्वजनिक प्राधिकरण ों पर उनकी संरचना, कार्यकरण और निर्णय लेने के संबंध में प्रामाणिक, उपयोगी और प्रासंगिक जानकारी को नियमित रूप से और सक्रिय रूप से प्रकाशित करना एक वैधानिक कर्तव्य हो गया है। पुलिस से भी यह अपेक्षा है कि वह इस जानकारी को विभिन्न माध्यमों और स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराए। हालांकि इसने निश्चित रूप से पुलिस विभागों को प्रेरित किया है कि वह संगठन और संरचना पर बुनियादी जानकारी ज्यादा से ज्यादा सुलभ कराए, फिर भी इस सूचना का अभाव है और इसकी बहुत आवश्यकता है।

अच्छी पुलिस व्यवस्था इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता और इतनी आवश्यक है कि उसमें विलम्ब नहीं किया जा सकता। पुलिस व्यवस्था के बारे में नियमित और सक्रिय रूप से जानकारी सुलभ कराना ही जनता में पुलिस के प्रति विश्वास जगाने और जागरूकता पैदा करने और पुलिस विभाग द्वारा पारदर्शिता दर्शाने का एक निश्चित माध्यम है।

ek;k nk#okyk
वरिष्ठ सलाहकार
सीएचआरआई

I. ifjp;

1.1 jk tuhfrd çkQkby

भारत, 32, 87, 782 वर्ग किमी क्षेत्रफल और लगभग 1.28 अरब की आबादी के साथ, शासन की संसदीय प्रणाली वाला एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है।

इसकी राजनीति संरचना संघीय है। भारत 29 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित सात केंद्र शासित प्रदेशों[1] का एक संघ है।

केंद्र की सरकार में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रियों की एक परिषद होती है, जो संसद में लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। राज्यों में, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रियों की परिषद राज्य की विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होती है।

1.2 foèkku 'kfä;k

संघ और राज्यों की शक्तियां, कार्य और जिम्मेदारियां भारत के संविधान में निर्धारित हैं। संविधान में संसद और राज्य विधायिकाओं[2] के बीच विधायी शक्तियां विभाजित है। संविधान में विषयों की तीन सूचियों निर्धारित है, जिन्हें संविधान की सातवीं अनुसूची में शामिल किया गया है।

सूची–1 – संघ सूची है, जो उन विषयों को बताती है जिन पर केवल संसद के पास कानून बनाने की शक्ति है। सूची–2– राज्य सूची है जो उन विषयों को निर्दिष्ट करती है जिन पर राज्य विधायिका के पास कानून बनाने के लिए विशेष शक्ति है। सूची–3 – समवर्ती सूची है जिनमें वे विषय शामिल हैं जिन पर संसद और राज्य विधायिका दोनों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है।

संसद को राज्य या समवर्ती सूची में उल्लिखित किसी भी विषय के संबंध में कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं है। यदि राज्य विधायिका द्वारा पारित कानून का कोई प्रावधान संसद द्वारा बनाए गए कानून के किसी भी प्रावधान के प्रति प्रतिकूल है, तो उत्तरार्द्ध प्रचलित है।

संसद को उन विषयों के संबंध में भी कानून बनाने का अधिकार है जिनका राज्य या समवर्ती सूची में उल्लेख नहीं है।[3] यदि राज्य विधायिका द्वारा पारित कानून का कोई प्रावधान संसद द्वारा बनाए गए कानून के किसी भी प्रावधान के प्रति प्रतिकूल है, तो

---

1 राज्यः आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिल नाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पाश्चिम बंगाल। केंद्र शासित प्रदेशः अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश ऐसे क्षेत्र हैं, जो राज्य क्षेत्राधिकारों का हिस्सा नहीं बनते हैं और केंद्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं।

2 भारतीय संविधान (1949), अनुच्छेद, 246

3 इबिड, अनुच्छेद 248 (1)

संसद द्वारा बनाया कानून प्रभावी होगा।[4] सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में "पुलिस "और "लोक व्यवस्था" शामिल है।

हालांकि संविधान में कुछ प्रावधान हैं जो केन्द्रीय सरकार को राज्यों में लोक व्यवस्था बनाए रखने पर असर डालने वाली कुछ स्थितियों में पुलिस संगठन स्थापित करने और हस्तक्षेप करने के लिए सशक्त करते हैं। संघ सूची संसद को अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित विषयों पर कानून बनाने के लिए अधिकृत करती है, जो पुलिस कार्य पर असर डालती हैं:

- "नागरिक शक्ति की सहायता के लिए किसी भी राज्य में.....संघ की किसी भी सशस्त्र बल[5] की तैनाती" और "ऐसी चुनौतियों के दौरान ऐसे बलों के सदस्यों की शक्तियां, क्षेत्राधिकार, विशेषाधिकार और दायित्व"[6]
- केन्द्रीय सूचना और अन्वेषण ब्यूरो[7]
- केंद्रीय एजेंसियां और संस्थाएं जो (क) व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए है, जिसमें पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण; या (ख) अनुसंधान को बढ़ावा देने; या (ग) अपराध की जांच या पहचान में वैज्ञानिक या तकनीकी सहायता के लिए है।[8]
- अखिल भारतीय सेवा, जिसमें भारतीय पुलिस सेवा[9] शामिल है

पुलिस और लोक व्यवस्था के अलावा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 में न्याय के प्रशासन, जिसमें सभी अदालतों (सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को छोड़कर), जेल, सुधार, बोरस्टल और राज्य में अन्य संबद्ध संस्थानों के गठन और व्यवस्था को राज्य सूची में शामिल किया गया है। आपराधिक कानून और आपराधिक प्रक्रिया समवर्ती सूची में शामिल हैं। राज्यों के पास इन विषयों पर कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार के बराबर अधिकार हैं। राज्य सरकारों ने आपराधिक न्याय प्रणाली की विभिन्न एजेंसियों के प्रशासन और कार्यकरण को शासित करने के लिए नियम और विनियम तैयार किए हैं।

1.3 vkijkfèkd U;k; ç.kkyh

आपराधिक न्याय प्रणाली का व्यापक दर्शन भारत के संविधान में निर्धारित है। यह सभी नागरिकों को कई मौलिक अधिकार प्रदान करके प्रारम्भ होता है।

1.3.1 lfoèkku dh rgr ukxfjd dh vfèkdkj

इनमें से कुछ अधिकार हैं:

- राज्य किसी भी व्यक्ति को भारत क्षेत्र के भीतर कानून के आगे समानता या समान सुरक्षा से वंचित नहीं कर सकता है। (अनुच्छेद 14)
- कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है जब तक कि उसके अपराध करते समय लागू कानून का उल्लंघन न किया हो और

---

4 इबिड, अनुच्छेद 251

5 भारत सरकार के गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को शामिल करता है।

6 भारत का संविधान, सातवीं अनुसूची, सूची ए प्रविष्टि 2 ए

7 इबिड, प्रवेश 8

8 इबिड, प्रवेश 65

9 इबिड प्रवेश 70, भारतीय पुलिस सेवा केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित तीन अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है।

किसी भी व्यक्ति को उसी अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जा सकता है तथा किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। (अनुच्छेद 20)

- किसी भी व्यक्ति को केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। (अनुच्छेद 21)
- गिरफ्तारी के कारण को सूचित किये बिना किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को हिरासत में नहीं रखा जा सकता है और न ही उसे परामर्श करने या अपने बचाव के लिए अपनी पसंद के किसी वकील की सलाह के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को इस तरह की गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए और मजिस्ट्रेट (अनुच्छेद 22) के आदेश के बिना इस अवधि से परे हिरासत में नहीं रखा जा सकता है।
- कानून के अधिकार को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। (अनुच्छेद 31)

1.3.2 vkijkfèkd dkuu

आपराधिक कानून में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में निहित कानून, विभिन्न अवसरों पर केंद्रीय और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए विभिन्न विशेष और स्थानीय कानून और मुख्य रूप से आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में निर्धारित प्रक्रियात्मक कानून शामिल है।

ये तीन प्रमुख अधिनियम अर्थात आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान अंग्रेजों द्वारा अधिनियमित किए गए थे। इनमें से, एकमात्र प्रमुख कानून जिसे स्वतंत्रता के बाद व्यापक रूप से संशोधित किया गया है – वह सीआरपीसी है। कुछ संशोधनों को छोड़कर अन्य दो कानून, ज्यादातर अपरिवर्तित रहे हैं।

आईपीसी विभिन्न प्रकार के अपराधों को परिभाषित करता है और इन अपराधों के लिए दंड निर्धारित करता है। आईपीसी के अलावा, स्थानीय और विशेष कानून (एसएलएल)[10] में दंड प्रावधान भी शामिल हैं। इन कानूनों को समय–समय पर विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरे नए प्रकार के अपराधों और समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए अधिनियमित किया गया था।

सीआरपीसी आपराधिक मामलों में शिकायत के पंजीकरण से लेकर जांच और अंतिम परीक्षण तक के लिए एक प्रक्रिया को निर्धारित करता है। राज्य पुलिस बल ने मुख्य रूप से इस कानून से ही पुलिस की अपनी शक्तियां प्राप्त की हैं। यह उन सीमाओं को भी निर्धारित करता है जिनमें पुलिस को गिरफ्तारी, खोज, जब्त, गवाहों की जांच आदि की शक्तियों का उपयोग करते समय संचालित करना होता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 कानून की अदालतों में साक्ष्य देने के लिए सिद्धांतों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है और न्यायिक कार्यवाही में सबूत की स्वीकार्यता को नियंत्रित करने वाले नियमों को बताता है।

---

10 स्थानीय कानून किसी विशिष्ट क्षेत्राधिकार पर लागू होता है और विशेष कानून किसी विशेष विषय पर लागू होता है।

आपराधिक कानून अपराधों की दो श्रेणियों – संज्ञेय और गैर–संज्ञेय[11] के बीच अंतर बताता है। संज्ञेय अपराधों में पुलिस को सीधे जांच करने और वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया जाता है, जबकि गैर–संज्ञेय अपराधों में, वे मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना जांच नहीं कर सकते हैं, न ही वारंट के बिना किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं।

1.3.3 vkijkfèkd U;k; çfØ;k

एक संज्ञेय अपराध के होने के बारे में पुलिस द्वारा शिकायत के पंजीकरण के साथ आपराधिक न्याय की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जहां तक पुलिस का सवाल है, प्रक्रिया में कुछ प्रमुख कदम हैं:

चरण –1: पुलिस द्वारा एक संज्ञेय अपराध होने के बारे में शिकायत का पंजीकरण, जिसे पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) कहा जाता है। एक संज्ञेय अपराध होने की जानकारी, चाहे वह मौखिक या लिखित हो, जो सबसे पहले पुलिस तक पहुंच जाती है, उसको पहली सूचना कहा जाता है। शिकायतकर्ता या सूचनार्थी कानूनी तौर पर एफआईआर की एक मुफ्त प्रतिलिपि के हकदार हैं।

चरण –2: पुलिस अधिकारी अपराध के स्थान पर जाता है और मामले के तथ्यों की जांच करता है। जांच की प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल हैं:

- अपराध के स्थान पर सबूतों का संरक्षण, परीक्षण और रिकॉर्डिंग।
- गवाहों और संदिग्धों की जांच।
- बयानों की रिकॉर्डिंग।
- तलाशी करना।
- संपत्ति जब्त करना और अन्य सबूत इकट्ठा करना।
- रिकॉर्ड की जांच करना और निर्धारित रिकॉर्ड में प्रविष्टियां शामिल करना, जैसे कि स्टेशन डायरी।
- विशेष साक्ष्य की तलाश।
- गिरफ्तारियां और हिरासत।
- आरोपी की पूछताछ।

चरण 3: जांच पूरी करने के बाद, पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी क्षेत्र मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट भेजता है। यदि मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, तो जांच अधिकारी द्वारा भेजी गई रिपोर्ट चार्जशीट के रूप में होती है। यदि पर्याप्त सबूत उपलब्ध नहीं हैं, तो रिपोर्ट को अंतिम रिपोर्ट कहा जाता है।

चरण 4: चार्जशीट प्राप्त करने पर, अदालत मामलों का संज्ञान लेती है और मामले की सुनवाई शुरू करती है।

---

11 सीआरपीसी की पहली अनुसूची आईपीसी में सभी अपराधों को सूचीबद्ध करती है और उल्लेख करती है कि वे संज्ञेय या गैर–संज्ञेय हैं या नहीं।

जमानती और गैर–जमानती अपराधों के बीच एक अंतर बनाया गया है। जमानती अपराधों में, जमानत एक अधिकार है और पुलिस को गिरफ्तार किए गए लोगों को जमानत पर रिहा करना होता है। गैर–जमानती अपराधों में, जमानत देना न्यायिक विवेकाधिकार का मामला है।

अगर पुलिस कुछ अपराधों के संबंध में 60दिनों के भीतर जांच पूरी करने में असमर्थ होती है और दूसरे अपराधों के संबंध में 90 दिनों के भीतर, तो आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है।

1.3.4 U;k;ky;

देश में अदालत प्रणाली भारत के संविधान में निहित प्रावधानों पर आधारित है। मूल, अपीलीय और सलाहकार क्षेत्राधिकार के साथ उच्चतम न्यायालय शीर्ष न्यायालय है। इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय हैं, इसके बाद जिलों में अधीनस्थ अदालतें हैं:

- भारत के उच्चतम न्यायालय (शीर्ष न्यायालय)
- उच्च न्यायालय (राज्य स्तर पर उच्चतम न्यायालय)
- सत्र/जिला न्यायालय[12]
- प्रथम श्रेणी/मेट्रोपॉलिटन अदालत के न्यायिक मजिस्ट्रेट
- दूसरी क्लास के न्यायिक मजिस्ट्रेट
- कार्यकारी मजिस्ट्रेट्स

कानून आरोपी को तब तक निर्दोष मानता है जब तक कि उसके अपराध को कानून की अधिकृत अदालत द्वारा आयोजित पूर्ण और उचित परीक्षण के माध्यम से स्थापित नहीं किया जाता है। अभियोजन पक्ष को संदेह से परे आरोपी के खिलाफ मामला साबित करने की आवश्यकता होती है। आरोपी को खुद को बचाने का पूरा मौका दिया जाता है। पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज इकबालिया बयान सबूत के रूप में स्वीकार्य नहीं होता है।

12 सत्र की अदालतें मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती हैं। सत्र अदालत के नीचे एक अदालत में हत्या, डकैती, डाकू और बलात्कार जैसे प्रमुख अपराधों की कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

2. jkT; ifyl cy

पुलिस एक राज्य विषय है और 29 राज्यों और सात केंद्र शासित प्रदेशों में से प्रत्येक का अपना पुलिस बल है। पुलिस के संगठन और कार्य राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों द्वारा शासित होते हैं। इन्हें राज्य पुलिस बलों के पुलिस मैनुअल में लिखा गया है।[13]

2.1 vudrk e ,drk

कई राज्य पुलिस बलों के अस्तित्व के बावजूद, उनकी संरचना और कार्यप्रणाली में काफी समानता है। यह चार मुख्य कारणों से है:

1. राज्य पुलिस बल की संरचना और कार्य पुलिस एक्ट, 1861 या मुख्यतया 1861 के कानून पर आधारित राज्य पुलिस एक्ट जिसे उच्चतम न्यायालय द्वारा 22 सितम्बर 2006 को दिए गए निर्देशों के अनुसार कुछ हद तक किये गए संशोधन द्वारा शासित है।[14]
2. आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे प्रमुख आपराधिक कानून देश के लगभग सभी हिस्सों में समान रूप से लागू हैं।
3. एक अखिल भारतीय सेवा है, भारतीय पुलिस सेवा, जिसे केंद्र सरकार द्वारा भर्ती, प्रशिक्षित और प्रबंधित किया जाता है और जो राज्य पुलिस बलों को वरिष्ठ अधिकारी प्रदान करता है।
4. भारतीय राजनीति का अर्ध–संघीय स्वरूप पुलिस मामलों में केंद्र के लिए एक समन्वय और परामर्श भूमिका की अनुमति देता है और यहां तक कि कुछ केंद्रीय पुलिस संगठनों को स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है।

2.2 ifyl ij vèkh{k.k

पुलिस अधिनियम, 1861 के अनुसार राज्य सरकार को पुलिस पर अधीक्षण[15] निहित है। 15 सितंबर 2006 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद हाल ही में कुछ नए राज्य पुलिस अधिनियमों ने लगभग एक समान प्रावधान किए हैं।

जबकि अधीक्षण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, पुलिस कानून, राज्य पुलिस बल के प्रशासन की ज़िम्मेदारी पुलिस प्रमुख, पुलिस महानिदेशक को देती है।[16]

हालांकि, "अधीक्षण" और "प्रशासन" शब्द को किसी भी कानून में पर्याप्त रूप से स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से परिभाषित नहीं किया गया है ताकि राज्य सरकारों को उनकी

---

13 ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा किए गए शोध से पता चला है कि इनमें से कुछ मैनुअल "पुरानी, पुरातन और पुरानी" हैं क्योंकि उन्हें "दशकों तक संशोधित नहीं किया गया है"। कुछ राज्यों में अपने स्वयं के मैनुअल नहीं होते हैं और पड़ोसी राज्यों को अपनाया जाता है। कुछ के पास न तो अपने स्वयं के मैनुअल हैं और न ही उन्होंने अन्य राज्यों से किसी को अपनाया है।

14 प्रकाश सिंह और अन्य वी यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य (2006) 8 एससीसी 1. और भारत बनाम ओआरएस बनाम।

15 खंड 3, पुलिस अधिनियम, 1861

16 धारा 4, पुलिस अधिनियम, 1861. उस समय राज्य पुलिस का मुख्य पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर जनरल हुआ करता था।

पुलिस बलों पर कुल, निर्विवाद नियंत्रण का उपयोग करने से रोका जा सके। कई मामलों में यह नियंत्रण परिचालन मामलों में भी लागू है।

2.3 ifyl inkuØe

प्रत्येक राज्य पुलिस बल में एक पदानुक्रमिक संरचना होती है, जो सभी राज्यों में थोड़ी बहुत सामान ही होती है।

2.3.1 jid lajpuk

राज्य पुलिस बलों का रैंक संरचना हैः

1. पुलिस महानिदेशक (डीजीपी)
2. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीएल डीजीपी)
3. पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी)
4. पुलिस उप–महानिरीक्षक (डेप्यूटी आईजीपी)
5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी)
6. पुलिस अधीक्षक (एसपी)
7. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एडीएल एसपी)
8. सहायक/उप–पुलिस अधीक्षक (एएसपी/डीईपी एसपी)
9. पुलिस निरीक्षक
10. पुलिस सब–इंस्पेक्टर (एसआई)
11. सहायक पुलिस सब–इंस्पेक्टर (एएसआई)
12. हेड कांस्टेबल (एचसी)
13. पुलिस कांस्टेबल (पीसी)

सीरियल नंबर 1–8 अधिकारी का रैंक है, जो ज्यादातर भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) से संबंधित हैं। कुछ, जैसे सीरियल नंबर 6–8 पर, राज्य पुलिस सेवा से भी हो सकते हैं। सीरियल नंबर 9–13 सबोर्डिनेट रैंक हैं। कुछ राज्यों में, वे फिर से दो श्रेणियों में विभाजित हैं। एएसआई से इंस्पेक्टरों को अप्पर सबोर्डिनेट्स कहा जाता है और कॉन्स्टबुलरी (हेड–कांस्टेबल और कॉन्सटेबल्स) को लोअर सबोर्डिनेट्स कहा जाता है। इन पुलिस रैंकों के अलावा पुलिस संगठनों में लिपिकीय, यांत्रिकी और तकनीकी कर्मचारी भी होते हैं।

2.3.2 jkT; ifyl cyksa esa jid&okj deZpkfj;ksa dh la[;k

1 जनवरी 2017 को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस बलों में विभिन्न रैंकों में स्वीकृत संख्या निम्नलिखित थीः

rkfydk 1% jid&okj Loh—r ifyl 'kfä ¼1 tuojh 2017 dk½[17]

Øekd	jid	'kfä
1	डीजीपी	131
2	अपर डीजीपी	372
3	आईजीपी	580
4	उप आईजीपी	395
5	एआईजीपी / एसएसपी / एसपी / कॉमड	2,808
6	अपर एसपी	2,089
7	एएसपी / उप। एसपी / डीई कॉमड	10,096
8	इंस्पेक्ट	33,852
9	एसआई	99,057
10	एएसआई	1,19,559
11	एचसी	4,25,559
12	कांस्टेबल	12,31,749
	dy	19]26]247

भारत में पुलिस संरचना पिरामिड के आकार का है। कॉन्स्टेबुलारी (कॉन्सटेबल और पुलिस के हेड कांस्टेबल) के पिरामिड का आधार बहुत व्यापक है। मध्यम स्तर को अपर सबोर्डिनेट (इंस्पेक्टर, सब–इंस्पेक्टर और पुलिस के सहायक उप–निरीक्षक) द्व ारा परिभाषित किया जाता है। शीर्ष पर अधिकारी (डीपु/अधीक्षक/सहायक पुलिस अधीक्षक से पुलिस महानिदेशक तक) बहुत अल्प संख्या में होते हैं।

इन आंकड़ों से पता चलता है कि कुल पुलिस संख्या का लगभग 86.04% कॉन्सटेबलरी है। पुलिस निरीक्षक, सब–इंस्पेक्टर और पुलिस के सहायक उप–निरीक्षक लगभग 13. 11% हैं और अधिकारी पुलिस की संख्या के 1% (0.86) से कम हैं। इस प्रकार यह वरिष्ठ अधिकारियों का एक बहुत छोटा समूह है, जो पुलिस मामलों पर राज्य सरकारों को सलाह देते हैं; संगठन की नीतियों पर निर्णय लेते हैं; शेष बल के लिए निर्देश जारी करते हैं; और सबोर्डिनेट्स के काम की निगरानी करते हैं।

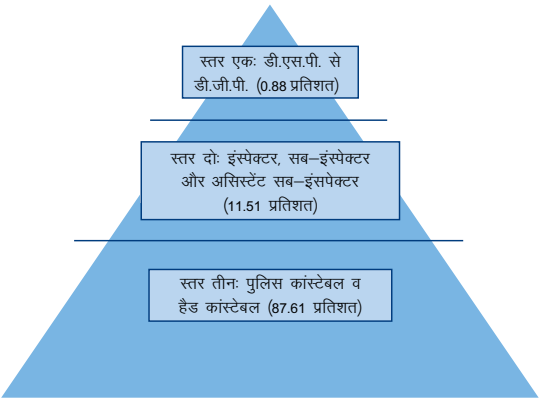

17 1 जनवरी, 2017 तक तालिका में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, भारत में पुलिस संगठनों पर डेटा, तालिका 3.6

2.3.3 jSd dk cSt

पुलिस अधिकारी को अपनी वर्दी के साथ अपना नाम टैग पहनना होता है। उनके रैंक को उनके बैज द्वारा पहचाना जा सकता है। रैंक के बैज नीचे दो भागों में दिखाए गए हैं: आईपीएस से संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों और जूनियर रैंक द्वारा पहने गए बैज:

Hkkjrh; iqfyl lsok vf/kdkfj;ksa dk jSd&cSt										
jSd&cSt										
jSd	funs'kd] vklpuk C;jks क्रास तलवार, बैटन, एक स्टार और राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न	iqfyl egk& funs'kd क्रास तलवार, बैटन और राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न	iqfyl egk& fujh{kd क्रास तलवार, बैटन और एक स्टार	iqfyl mi&egk& fujh{kd राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न और तीन स्टार	ofj"B iqfyl v/kh{kd (सलेक्शन ग्रेड) राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न और दो स्टार	iqfyl v/kh{kd राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न और एक स्टार	vij iqfyl v/kh{kd राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न	lgk;d mi& iqfyl v/kh{kd तीन स्टार	lgk;d mi& iqfyl v/kh{kd (प्रोबेशनरी रैंक दो साल की सेवा तक) दो स्टार	lgk;d mi& iqfyl v/kh{kd (प्रोबेशनरी रैंक दो साल से कम की सेवा तक) एक स्टार

रैंक के बैज रजत पदक के हैं, लेकिन कढ़ाई वाले बैज, गहरे नीले रेशम धागे में बने हुए बैज, अनौपचारिक कामकाजी पोशाक के साथ भी पहने जाते हैं।

भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी कंधे के पट्टा के आधार पर आधा इंच के ब्लॉक अक्षरों में एक चांदी का विभागीय बैज जिस पर "आईपीएस" लिखा होता है उसे पहनते हैं। उपरोक्त कुछ रैंक वाले राज्य पुलिस सेवा अधिकारी ऐसा ही बैज पहनते हैं लेकिन "आईपीएस" का उपयोग नहीं करते हैं। वे उन अक्षरों का उपयोग करते हैं जो अपने राज्य पुलिस बल में हैं।

पुलिस के वरिष्ठ अधीक्षक (चयन ग्रेड एसपी) और उप महानिरीक्षक के पद के अधिकारी अपने शर्ट के कॉलर पर केंद्रीय चांदी के पट्टी के साथ गहरे नीले ऊनी सामग्री के गर्जेट पैच पहनने के लिए अधिकृत हैं। आईजीपी के पद के अधिकारी और उपरोक्त अपने कॉलर पैच पर एक साधारण चांदी की अस्तर की बजाय लंबे पत्ते के चांदी के डिजाइन पहनते हैं।

dkyj Vc lerj onh esa ,d vf/kdkjh

jkT; iqfyl dk jSad&cSt						
jSad&cSt						
jSad	fujh{kd तीन स्टार, आधा इंच चौड़ी आधी लाल और आधी नीले रंग की समतल पट्टी जिसमें लाल पट्टी स्टार की तरफ हो	mi&fujh{kd दो स्टार, आधा इंच चौड़ी आधी लाल और आधी नीले रंग की समतल पट्टी जिसमें लाल पट्टी स्टार की तरफ हो	lgk;d mi&fujh{kd एक स्टार, आधा इंच चौड़ी आधी लाल और आधी नीले रंग की समतल पट्टी जिसमें लाल पट्टी स्टार की तरफ हो	gsM dkaLVscy कंधे के उपरी भाग पर तीन पट्टी	ofj"B iqfyl dkaLVscy ;k iqfyl uk;d कंधे के उपरी भाग पर दो पट्टी	कांस्टेबल कोई रैंक–बैज़ नहीं

2.3.4 iqfyl ind

कभी–कभी, औपचारिक अवसरों पर, पुलिस कर्मी उनको मिले पदकों को अपनी वर्दी पर पहनते हैं। भारत सरकार द्वारा दिए गए चार तरह के पदक निम्नलिखित हैं:

ifyl ind	
	1- ohjrk dk fy, jk"Vifr ind % यह पदक जीवन और संपत्ति को बचाने, अपराध को रोकने या अपराधियों को गिरफ्तार करने में विशिष्ट वीरता के लिए प्रदान किया जाता है। किसी भी पद और सेवा–अवधि वाले देश के सभी पुलिस कर्मचारी इस पुरस्कार के लिए पात्र हैं। इसके तहत प्राप्तकर्ताओं को मासिक भत्ता प्रदान किया जाता है, जो सेवानिवृत्ति के बाद भी देय होता है। प्राप्तकर्ता की मृत्यु के बाद, उसकी विधवा को इसके लिए उसी दर से भुगतान किया जाता है। इस पुरस्कार के प्राप्तकर्ता एक सहयोगी के साथ पूरे भारत में ट्रेन से मुफ्त यात्रा करने का पात्र होते हैं।
	2- ohjrk dk fy, ifyl ind % यह पदक विशिष्ट वीरता के लिए प्रदान किया जाता है। किसी भी पद और सेवा–अवधि वाले देश के सभी पुलिस कर्मचारी इस पुरस्कार के लिए पात्र हैं। इसके तहत प्राप्तकर्ताओं को मासिक भत्ता प्रदान किया जाता है, जो सेवानिवृत्ति के बाद भी देय होता है। प्राप्तकर्ता की मृत्यु के बाद, उसकी विधवा को इसके लिए उसी दर से भुगतान किया जाता है। इस पुरस्कार के प्राप्तकर्ता एक सहयोगी के साथ पूरे भारत में ट्रेन से मुफ्त यात्रा करने का पात्र होते हैं।
	3- fof'k"V lok dk fy, jk"Vifr dk ind % यह पदक प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसी पुलिस अधिकारी को उसके द्वारा की गई सेवा के विशेष रूप से सम्मानित रिकॉर्ड के लिए प्रदान किया जाता है। न्यूनतम 21 साल की सेवा वाले सभी पुलिस कर्मचारी पुरस्कार के लिए पात्र हैं।
	4- ljkguh; lok dk fy, ifyl ind % यह पदक प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसी पुलिस अधिकारी को उसके द्वारा की गई सराहनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। न्यूनतम 15 साल की सेवा वाले सभी पुलिस कर्मचारी पुरस्कार के लिए पात्र हैं।

2.4 ifyl dh l[;k

2.4.1 jkT;k vkj dæ 'kkfl r çn'kk e ifyl dh l[;k

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस बलों की संख्या के बारे में जानकारी नीचे दी गई है।

rkfydk 2% 1-1-2017 jkT;k@dæ 'kkfl r çn'kk e ifyl dh Loh—r vkj okLrfod 'kfä[18]

Øekd	jkT;	l[;k cy		
		Loh—fr	okLrfod	fjfä ;k
1.	आंध्र प्रदेश	61,048	49,452	11,596
2.	अरुणांचल प्रदेश	13,160	11,612	1,548

18 1 जनवरी, 2017 को भारत में पुलिस संगठनों पर डेटा, तालिका 3.1

3.	असम	65,611	55,403	10,208
4.	बिहार	1,12,687	78,203	34,484
5.	छत्तीसगढ़	70,300	59,596	10,704
6.	गोवा	8,312	7,017	1,295
7.	गुजरात	1,06,831	76,036	30,795
8.	हरियाणा	63,746	45,667	18,079
9.	हिमाचल प्रदेश	16,932	16,067	865
10	जम्मू और कश्मीर	84,954	78,348	6,606
11.	झारखण्ड	85,268	59,341	25,927
12	कर्नाटक	1,14,912	91,002	23,910
13.	केरला	63,785	62,476	1,309
14.	मध्य प्रदेश	1,15,726	98,466	17,260
15.	महाराष्ट्र	2,40,224	2,25,475	14,749
16.	मनिपुर	32,677	25,118	7,559
17.	मेधालय	15,335	12,360	2,975
18.	मिज़ोरम	9,807	7,513	2,294
19.	नागालैंड	21,573	23,131	(1558)
20.	ओडीशा	66,439	56,709	9,730
21.	पंजाब	87,672	80,486	7,186
22	राजस्थान	1,04,451	89,500	14,951
23.	सिक्किम	6,081	5,355	726
24.	तमिलनाडु	1,36,002	1,28,197	7,805
25.	तेलंगाना	63,064	47,020	16,044
26.	त्रिपुरा	27,421	23,864	3,557
27.	उत्तर प्रदेश	4,13,254	1,98,919	2,14,335
28.	उत्तराखण्ड	21,096	19,957	1,139
29.	पश्चिम बंगाल	1,34,867	96,287	38,580
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4,468	3,925	543
31.	चंडीगड़	6,721	5,912	809
32.	दादरा और नागर हवेली	354	338	16
33.	दमन और दीव	500	384	116
34.	दिल्ली	84,417	82,979	1,438
35.	लक्षद्वीप	562	404	116
36.	पुडूचेरी	4,227	3,728	499
	VkVy	**24,64,484**	**19,26,247**	**5,38,237**

1 जनवरी 2017 को, राज्य पुलिस बलों की कुल स्वीकृत संख्या थीः– 24.64 लाख[19] (2.464 मिलियन) थी। इनमें से सिविल पुलिस की स्वीकृत संख्या 19.89 लाख (1.989 मिलियन) थी और सशस्त्र पुलिस की संख्या 4.75 लाख (0.475 मिलियन) थी। हालांकि, वास्तविक संख्या बहुत कम थी। यह केवल 19.26 लाख (1.93 मिलियन) था। इस प्रकार 2017 की शुरुआत में 5.38 लाख (0.54 मिलियन) रिक्तियां थीं। दूसरे शब्दों में, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस की कुल स्वीकृत संख्या का एक–पांचवां (21.84%) हिस्सा खाली था।

19 एक लाख एक सौ हजार के बराबर है।

पुलिस की संख्या प्रत्येक राज्य में भिन्न होती है। 1 जनवरी 2017 को, नौ राज्य पुलिस बलों में एक लाख से अधिक की संख्या थी। इनमें से उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी स्वीकृत पुलिस संख्या (4.13 लाख) थी, इसके बाद महाराष्ट्र (2.40 लाख), तमिलनाडु (1.36 लाख), पश्चिम बंगाल (1.35 लाख), मध्य प्रदेश (1.16 लाख), कर्नाटक (1.15 लाख), बिहार (1.13 लाख), गुजरात (1.07 लाख), और राजस्थान (1.04 लाख) थी। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली की सबसे बड़ी स्वीकृत पुलिस संख्या (84,417 हजार) थी, जबकि दादर और नगर हवेली के पास सबसे छोटा दल (354)[20] था।

2.4.2 ifyl&tul[;k vkj {k= vuikr

पुलिस आबादी और क्षेत्र अनुपात के बारे में विवरण नीचे दिए गए हैं।

rkfydk 3% ifyl&tul[;k vkj {k= vuikr ¼1 tuojh 2017 dk½[21]

Øeakd	en	Loh—fr	okLrfod	fjfä
1.	ifyl cy	24,64,484	19,26,247	5,38,237
2.	पुलिस प्रति लाख जनसंख्या सिविल पुलिस प्रति लाख जनसंख्या	192.87 155.68	150.75 120.97	
3.	पुलिस प्रति 100 किमी क्षेत्रफल सिविल पुलिस प्रति 100 किमी क्षेत्रफल	77.83 62.82	60.83 48.82	

1 जनवरी 2017 को प्रति लाख आबादी पर स्वीकृत पुलिस कर्मियों की संख्या 192.87 थी, लेकिन जमीन पर केवल 150.75 उपलब्ध थे। पुलिस प्रति आबादी का अनुपात असल में काफी काम था।[22] प्रति लाख आबादी के लिए सिविल पुलिस कर्मियों की संख्या 155.68 थी, लेकिन जमीन पर यही संख्या बहुत कम थी। एक लाख आबादी के लिए केवल 120.97 सिविल पुलिसकर्मी उपलब्ध थे।

यद्यपि प्रति सौ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए 77.83 पुलिस कर्मियों की मंजूरी तय की गई थी, वास्तविक संख्या केवल 60.83 थी। प्रति सौ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सिविल पुलिस की स्वीकृत और वास्तविक संख्या क्रमशः 62.82 और 48.82 थी।

2.4.3 ifyl tu'kfä eas of)

आजादी के बाद पुलिस जनशक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:[23]

---

20 यह आंकड़ा क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट से संकलित किया गया है जो एनएसआरबी द्वारा हर साल प्रकाशित किया जाता है। मुसलमानों के प्रतिनिधित्व पर 2014 से आंकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं।

21 जनवरी 2016 को भारत में पुलिस संगठनों पर डेटा,

22 ऐसा करना प्रासंगिक है क्योंकि जनता सशस्त्र पुलिस की तुलना में नागरिकों के साथ अपने दिन–प्रतिदिन सौदे में अधिक बातचीत करती है।

23 राष्ट्रीय रिपोर्ट रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी), बीपीआरडी द्वारा प्रकाशित भारत में पुलिस संगठनों पर डेटा और राष्ट्रीय पुलिस आयोग के रिकॉर्ड द्वारा प्रकाशित अपराध सहित भारत में अपराध सहित वार्षिक रिपोर्टों से संकलित किया गया है।

rkfydk 4% vktknh ds ckn ls iqfyl tu'kfä esa o`f)

o"kZ	flfoy iqfyl	l'kä cy	iw.kZ cy
1947	2,38,368	1,42,550	3,80,918
1951	2,72,156	1,95,584	4,67,740
1961	2,99,750	2,26,399	5,26,149
1971	5,34,236	1,72,659	7,06,895
1981	6,92,132	2,05,698	8,97,830
1991	9,03,849	2,48,747	11,52,596
2001	10,77,415	3,72,346	14,49,761
2011	16,40,342	4,24,028	20,64,370
2014	18,38,616	4,45,030	22,83,646
2015	18,22,358	4,40,864	22,63,222
2016	18,30,131	4,50,560	22,80,691
2017	19,89,295	4,75,189	24,64,484

1947 में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस की कुल स्वीकृत संख्या लगभग 3.81 लाख थी। 2017 तक, यह संख्या बढ़कर 24.64 लाख हो गई।

1947—2017 की अवधि के दौरान, सिविल पुलिस में लगभग 835: की वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि के दौरान सशस्त्र पुलिस में केवल 333: की वृद्धि हुई। आजादी के बाद कुल पुलिस संख्या ने 650: से थोड़ी ही कम वृद्धि दर्ज की।

2.4.4 jkT; iqfyl cy esa vuqlwfpr tkfr;ksa] vuqlwfpr tutkfr;ksa vkSj eqfLyeksa dk çfrfuf/kRo

गृह मंत्रालय में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा सालाना प्रकाशित ''भारत में अपराध'' राज्य पुलिस बलों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व पर जानकारी प्रदान करता है। 2000 से 2013 की अवधि के लिए यह आंकड़े नीचे प्रस्तुत किये गए है:

rkfydk 5% iqfyl cy esa ,llh] ,lVh vkSj eqlyekuksa dk çfrfuf/kRo ¼2001&2013½[24]

o"kZ	vuqlwfpr tkfr	vuqlwfpr tu&tkfr	eqfLye
2001	1,65,187	99,377	1,03,545
2002	1,58,740	93,872	97,928
2003	1,69,428	1,00,518	94,556
2004	1,75,215	1,06,738	93,691
2005	1,73,944	1,08,331	1,00,634
2006	1,80,964	1,09,519	69,365
2007	1,84,354	1,16,907	1,01,843
2008	1,85,548	1,27,513	98,462
2009	1,96,412	1,33,519	1,03,226
2010	2,11,385	1,53,385	1,09,262
2011	2,27,057	1,66,114	1,08,389
2012	2,34,796	1,73,852	1,08,975
2013	2,54,644	1,87,324	1,08,602

24 यह आंकड़े एनसीआरबी द्वारा सालाना प्रकाशित अपराध में भारत में अपराध से संकलित किया गया है। 2014 से मुस्लिम प्रतिनिधित्व पर डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।

2001 में, पुलिस बल में अनुसूचित जातियों के 1,65,187 व्यक्ति, अनुसूचित जनजातियों से 99,377 और 1,03,545 मुसलमान थे। 2013 में, अनुसूचित जातियों के सदस्यों की संख्या बढ़कर 2,54,644 हो गई (वृद्धि – 89,457); जबकि अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों का हिस्सा बढ़ गया 1,87,324 (87,947 की वृद्धि)। दूसरी तरफ, मुस्लिमों की संख्या में केवल 1,08,602 (5,057 की वृद्धि) बढ़ी। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, मुसलमानों ने 2011 में देश की आबादी का 13.43: गठित किया था, लेकिन पुलिस में उनका प्रतिनिधित्व केवल 6.52: था।

2.4.5 jkT;k vkj dæ 'kkflr çn'kk e efgyk ifyl

2.4.5.1 jkT;k vkj dæ 'kkflr çn'kk e efgyk ifyl dh l[;k

महिला पुलिस सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस बलों का एक हिस्सा हैं। उनकी संख्या के बारे में जानकारी निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

rkfydk 6 & jkT; ifyl@l?k jkT;{k= okj efgyk ifyl dh l[;k vkj dy çfr'kr ifyl l[;k ¼1 tuojh] 2017 dk½[25]

Øekd	jkT;@dUæ 'kkflr çn'k	okLrfod l[;k		efgyk ifyl ¼% çfr'kr e½
		jkT;@dUæ 'kkflr çn'k ¼flfoy$ l'kä cy½	jkT;@dUæ 'kkflr çn'k e efgyk ifyl	
1.	यूनिकोड यहां आंध्र प्रदेश	49,542	2,064	4.17%
2.	अरुणाचंल	11,612	787	6.78%
3.	असम	55,403	3,033	5.47%
4.	बिहार	78,203	6,912	8.84%
5.	छत्तीसगढ़	59,596	2,791	4.68%
6.	गोवा	7,017	758	10.80%
7.	गुजरात	76,036	5,496	7.23%
8.	हरियाणा	45,667	4,166	9.12%
9.	हिमाचल प्रदेश	16,067	1,968	12.25%
10	जम्मू और कश्मीर	78,348	2,386	3.05%
11.	झारखण्ड	59,341	3,258	5.49%
12	कर्नाटक	91,002	4,895	5.38%
13.	केरल	62,476	3,949	6.32%
14.	मध्य प्रदेश	98,466	4,352	4.42%
15.	महाराष्ट्र	2,25,475	26,208	11.62%
16.	मनिपुर	25,118	2,036	8.11%
17.	मेघालय	12,360	537	4.34%
18.	मिजोरम	7,513	580	7.72%
19.	नागालैंड	23,131	1,464	6.33%

25 1 जनवरी 2016 को भारत में पुलिस संगठनों पर डेटा, तालिका 12.4

20.	ओडीशा	56,709	5,143	9.07%
21.	पंजाब	80,486	4,233	5.26%
22.	राजस्थान	89,500	8,308	9.28%
23.	सिक्किम	5,355	369	6.89%
24.	तमिलनाडू	1,28,197	16,553	12.91%
25.	तेलंगाना	47,020	1,160	2.47%
26.	त्रिपुरा	23,864	1,201	5.03%
27.	उत्तर प्रदेश	1,98,919	7,583	3.81%
28.	उत्तराखण्ड	19,957	1,530	7.67%
29.	पश्चिम बंगाल	96,287	7,356	7.64%
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप	3,925	478	12.18%
31.	चंडीगढ़	5,912	1,067	18.05%
32.	दादरा और नागर हवेली	338	50	14.79%
33.	दमन और दीव	384	46	11.98%
34.	दिल्ली	82,979	7,167	8.64%
35.	लक्षद्वीप	404	32	7.92%
36.	पुडूचेरी	3,728	268	7.19%
	Total	**19,26,247**	**1,40,184**	**7.28%**

महिला पुलिस देश में कुल पुलिस बल का 7.28: है। राज्यों में, महिला पुलिस का उच्चतम प्रतिशत तमिलनाडु (12.91) में मिलता है, इसके बाद हिमाचल प्रदेश (12.25), महाराष्ट्र (11.62), गोवा (10.80), हरियाणा (9.12), राजस्थान (9.28), और ओडिशा (9. 07))। शेष राज्यों में से बिहार, मणिपुर, मिजोरम, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल देश के औसत प्रतिशत 7.28: से अधिक है और शेष राज्यों में सीमा उस सीमा से नीचे है। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ शीर्ष स्थान पर है, इसकी महिला पुलिस बल 18.05: है।

2.4.5.2 efgyk ifyl dh l[;k esa of)

पिछले कुछ वर्षों में, देश में महिला पुलिस की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सत्रह वर्ष की अवधि के दौरान ताकत में वार्षिक वृद्धि नीचे दिखाई गई है:

rkfydk 7% 2000 ls 2017 rd efgyk ifyl esa okf"kd of)[26]

o"kZ	l[;k cy
2000	24,713
2001	26,018
2002	31,446
2003	32,481
2004	NA
2005	39,954
2006	45,886
2007	52,723
2008	57,466
2009	56,667
2010	66,153

26 बीपीआर और डी द्वारा सालाना प्रकाशित पुलिस संगठनों पर डेटा में निहित जानकारी से संकलित।

2011	71,756
2012	84,479
2013	97,518
2014	1,05,325
2015	1,10,872
2016	1,22,912
2017	1,40,184

इस प्रकार 2000 में महिला पुलिस की संख्या 24719 से बढ़कर 2017 में 1,40,184 हो गई। हालांकि इस अवधि के दौरान महिला पुलिस बल में 567.25ः की वृद्धि हुई है, 2017 में अभी भी उनका कुल पुलिस बल में प्रतिशत 7.28 ही है, उनकी संख्या कुल पुलिस बल का 1.67 ही है।

2.4.5.3 efgyk ifyl dh rkdr e jid&okj of)

हालांकि अब भी वे पुलिस बल का एक बहुत ही छोटा प्रतिशत हैं, यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक रैंक में उनकी संख्या बढ़ रही है। वरिष्ठ रैंकों में कई महिला पुलिस अधिकारी काम कर रही हैं। निम्नलिखित तालिका में महिला पुलिस के रैंक–वार विकास को देखा सकता हैः

rkfydk 8% 2001[27] ls 2017[28] rd efgyk ifyl e jid&okj of)

in	2001	2017
डीजीपी/एडीस्नल/स्पेशल डीजीपी	Nil	28
आईजी	2	41
डीआईजी	7	27
एसएसपी/एसपी/सेनानायक	29	274
एडीस्नल एसपी / डिप्टी सेनानायक.	-	189
एएसपी/डीएसपी / सहायक सेनानायक	79	641
निरिक्षक (इंस्पेक्टर)	255	2,372
एसआई	1,343	7,482
एएसआई	777	3,838
हेड कॉस्टेबल	2,649	24,709
कांस्टेबल	20,877	1,00,583
टोटल	26,018	1,40,184

2000 में कोई भी महिला शीर्ष रैंक पर नहीं आ पाई थी, 2017 तक 28 महलिा पुलिस अधिकारी डीजीपी/एडीएल डीजीपी के रैंक तक पहुंच गई थी। इस अवधि के दौरान महिला आईजीपी की संख्या 2 से 41 हो गई; डीआईजी 7 से 27 तक; एसएसपी/एसपी 29 से 274 तक; और इस अवधि के दौरान एएसपी/डीवाई एसपी 79 से 641 तक पहुँच गई हैं।

27 1 जनवरी, 2001 को भारत में पुलिस संगठनों पर डेटा

28 1 जनवरी, 2016 को भारत में पुलिस संगठनों पर डेटा।

2.5 lxBukRed lajpuk

राज्य पुलिस की संगठनात्मक संरचना को दो भागों में सबसे अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। एक क्षेत्रीय स्थापना है जो दिन–प्रतिदिन की वास्तविक पुलिसिंग करता है और दूसरा मुख्यालय स्थापना है, जो नीतियों को तैयार करता है, निर्देश जारी करता है, सरकार के साथ संपर्क करता है और पुलिस बल का प्रबंधन करता है।

2.5.1 QhYM LFkkiuk

2.5.1.1 bdkbZ;k

राज्यों को जिलों नामक प्रशासनिक इकाइयों में क्षेत्रीय रूप से विभाजित किया गया है। जिलों का एक समूह एक रेंज का निर्माण करता है, जो कि पुलिस उप–महानिरीक्षक के प्रभार में होता है। कुछ राज्यों में, पुलिस रेंज का नेतृत्व पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) भी करते हैं। आम तौर पर, आईजीपी पुलिस क्षेत्र के प्रभारी होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में दो या दो से अधिक रेंज होती हैं।

एक पुलिस अधीक्षक (एसपी) जिला पुलिस बल का नेतृत्व करता है। कुछ बड़े या महत्वपूर्ण जिलों में, एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को जिला पुलिस बल के प्रमुख के रूप में तैनात किया जाता है।

एक जिला सब–डिवीजन में बांटा जाता है। एक सब–डिवीजन पुलिस के सहायक अधीक्षक / उप पुलिस अधीक्षक के पद के अधिकारी के प्रभार में होता है। प्रत्येक सब–डिविजन को इसके क्षेत्र, आबादी और अपराध की मात्रा के आधार पर कई पुलिस स्टेशनों में विभाजित किया गया है। पुलिस स्टेशन और सब–डिवीजन के बीच, कई राज्यों में पुलिस सर्किल हैं दृ प्रत्येक सर्किल आमतौर पर पुलिस अध्यक्ष द्वारा शासित किया जाता है। कुछ राज्यों में, उनके पास पुलिस सब–डिवीजनों के स्थान पर पुलिस सर्किल हैं।

1 जनवरी, 2016 को देश के विभिन्न स्तरों पर फील्ड इकाइयों की संख्या नीचे दिखाई गई है:

rkfydk 9% QhYM LFkkiuk bdkbZ;k dh lajpuk ¼1 tuojh 2017 dks½[29]

Øekad	;qfuV	lajpuk
1	पुलिस जोन	97
2	पुलिस रेंजस	186
3	जिला पुलिस	758
4	पुलिस सब–डिवीजन	2,473
5	पुलिस सर्कल्स	2,422
6	पुलिस स्टेशन	15,579
7	पुलिस पोस्ट	9,087

29 बीपीआर और डी, 1 जनवरी 2017 को भारत में पुलिस संगठनों पर डेटा, तालिका 1.10, पृष्ठ 139

पुलिस रेंज और क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी मुख्य रूप से पर्यवेक्षी कार्य करते हैं। देश में क्षेत्र इकाइयों में, पुलिस प्रतिष्ठान का सबसे महत्वपूर्ण घटक जिला पुलिस है और इसका प्रमुख क्षेत्र की पुलिस व्यवस्था या पुलिसिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

2.5.1.2 ftyk ifyl

कानून राज्य सरकार को राज्य के किसी भी क्षेत्र को पुलिस जिला होने की अधिसूचना द्वारा घोषित करने का अधिकार देता है। पुलिस कानून, पुलिस के अधीक्षक में इस तरह के जिले में पुलिस के प्रशासन निहित करता है जिसकी सहायता के लिए अतिरिक्त, सहायक या उप पुलिस अधीक्षक होते हैं।[30]

2.5.1.2.1 ftyk ifyl vèkh{kd dk;kZy; e 'kk[kk,

जिला पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में आमतौर पर निम्नलिखित शाखाएं होती हैं:

- प्रशासन / स्थापना शाखा
- अपराध शाखा
- विशेष शाखा
- सामान्य शाखा
- लेखा शाखा
- गोपनीय शाखा
- शिकायतें / भ्रष्टाचार निरोधक या सतर्कता कक्ष
- यातायात पुलिस शाखा
- पुलिस नियंत्रण कक्ष

2.5.1.2.2 ifyl ykbUl

जिला पुलिस की अपनी पुलिस लाइनें हैं, जो परेड ग्राउंड और अन्य शाखाओं से लैस हैं, जैसे मोटर परिवहन (एमटी); कैंटीन और स्टोर; कुत्ते की टीम; घुड़सवार पुलिस; हथियार और गोला बारूद स्टोर (कोट); बम निरोधक दस्ता; आदि।

एक पुलिस लाइन पुलिस निरीक्षक के प्रभार में होता है, जिसे रिजर्व इंस्पेक्टर (आरआई) के नाम से जाना जाता है। वह पुलिस लाइन में तैनात सिपाहियों के रोस्टर को बनाए रखता है; सुनिश्चित करता है कि दैनिक रोल कॉल की जाए है; विभिन्न कर्तव्यों के लिए आवश्यक सभी गार्ड और एस्कॉर्ट्स की व्यवस्था करता है; परेड आयोजित करता है; और कपड़ों, हथियार, तंबू और अन्य ज़रूरत की चीज़ों की दुकानों जैसे विभिन्न वस्तुओं की अभिरक्षा और आपूर्ति की देखरेख करता है।

2.5.1.2.3 ftyk ifyl vfèkdkjh

एक पुलिस जिले में निम्नलिखित रैंकों के पुलिस अधिकारी हैं:

1. पुलिस अधीक्षक
2. पुलिस के अतिरिक्त अधीक्षक

---

30 धारा 9, असम पुलिस अधिनियम, 2007

3. पुलिस के सहायक/उप अधीक्षक
4. पुलिस के निरीक्षक
5. पुलिस के सब–इंस्पेक्टर
6. पुलिस के सहायक सब–इंस्पेक्टर
7. पुलिस का हेड कांस्टेबल
8. पुलिस कांस्टेबल

इनके अलावा, हर पुलिस जिले में अपनी विभिन्न शाखाओं/इकाइयों के लिए आवश्यक कार्यालय, तकनीकी और सहायक कर्मचारी होते हैं।

2.5.1.2.4 ftyk vèkh{kd ifyl d dr0;

जिला अधीक्षक (एसपी) जिले में पुलिस बल का प्रमुख है। एसपी सुनिश्चित करता है कि जिले में पुलिस बल जनता को एक कुशल और ईमानदार पुलिस कवर प्रदान करे। राज्य पुलिस मैनुअल[31] में एसपी के लिए निर्धारित कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्य इस प्रकार हैं:

- जिले में शांति, कानून और व्यवस्था बनाए रखना
- अपराधों को तेज़ी से और कुशलता से रोकना और जांचना
- सभी वर्गों के लोगों के जीवन की स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा के लिए उपाय करना
- अधिकारियों के काम का पर्यवेक्षण करना और ज़िले की पुलिस के विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करना
- अच्छे पुलिस–जनसंपर्क को बढ़ावा देना और बरकरार रखना
- बल को अनुशासित, प्रेरित, उचित ढंग से प्रशिक्षित, व्यावसायिक रूप से सहानुभूतिपूर्ण, ईमानदार और सेवा–उन्मुख बनाए रखना
- समय–समय पर जिले में सभी पुलिस इकाइयों और लाइनों का निरीक्षण करना
- जब जब गंभीर प्रकृति की घटनाएं जीवन और संपत्ति को खतरे में डालती हों तो व्यक्तिगत रूप से परिस्थितियों का दौरा और संचालन करना
- व्यक्तिगत अखंडता, निष्पक्षता, कर्तव्य के प्रति और न्याय की उच्च भावना द्वारा अधीनस्थों का आत्मविश्वास और निष्ठा प्राप्त करना
- अधीनस्थ अधिकारियों की ईमानदारी और अखंडता सुनिश्चित करें
- गावों और जिले के अन्य हिस्सों का भ्रमण करना, समस्याग्रस्त इलाकों में अधिक समय बिताना
- सुनिश्चित करना कि वाहनों, हथियारों और गोला बारूद, भंडारों और विभाग की इमारतों को अच्छी स्थिति में रखे।

2. 5.1.2.5 ftyk Lrj ij nkgjh fu;=.k ç.kkyh

पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 3, राज्य पुलिस के अधीक्षण की पुष्टि करता है

पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 3, राज्य सरकार में राज्य पुलिस बल का अधीक्षण

31 यह जानकारी मुख्य रूप से बीपीआर और डी मॉडल मैनुअल और कर्नाटक पुलिस मैनुअल से ली गई है।

निहित करना है। 1861 के इसी अधिनियम के धारा 4 ने जिला स्तर पर दोहरी नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की। इसने पुलिस बल को जिला अधीक्षक पुलिस के तहत रखा, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) के "सामान्य नियंत्रण और निर्देश" के अधीन। यह जानबूझकर किया गया था क्योंकि जिला मजिस्ट्रेट को जिले के मुख्य अधिकारी के रूप में भारत में ब्रिटिश शासन बनाए रखने के लिए आवश्यक माना।

1861 के पुलिस अधिनियम ने जिला अधिकारी के "सामान्य नियंत्रण और निर्देश" वाक्यांश को परिभाषित नहीं किया, जिस पर जिला पुलिस बल का अधिकार था। इसका अर्थ सीधा सीधा जिला पुलिस संगठन पर पूर्ण नियंत्रण था, जिसकी वजह से अक्सर जिला कलेक्टर और जिला अधीक्षक पुलिस के बीच टालने वाले नोक–झोंक होती थी।

आजादी के बाद भी यह प्रणाली जारी रही। जिला पुलिस और कार्यकारी मजिस्ट्रेट के बीच संबंधों की जांच का अध्ययन राष्ट्रीय पुलिस आयोग (एनपीसी) ने विस्तार से किया। एनपीसी ने निष्कर्ष निकाला कि "मौजूदा परिस्थितियों में जिला पुलिस प्रशासन को विभागीय पदानुक्रम में अधिकारियों द्वारा नियंत्रित किए जाने के अलावा किसी अन्य के नियंत्रण के अधीन करने का कोई कारण नहीं है।"[32] हालांकि, आयोग ने जिला प्रशासन में जिला मजिस्ट्रेट के लिए एक समन्वय भूमिका को मान्यता दी, खासतौर से भूमि विवादों, कानून और व्यवस्था में गड़बड़ी, चुनाव संचालन, प्राकृतिक आपदाओं का संचालन आदि से संबंधित मामलों में।

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, कुछ राज्यों ने पुलिस अधिनियम, 1861 को बदलने के लिए नए कानून पारित किए हैं। जिला पुलिस पर दोहरी नियंत्रण प्रणाली से निपटने के नए कानूनों में कोई समानता नहीं है। समस्या को तीन अलग–अलग तरीकों से संभाला गया है। एक, कुछ राज्यों ने कुछ शब्दों में बदलाव के बाद 1861 अधिनियम की धारा 4 में निहित प्रावधान बरकरार रखा है[33] दो, कुछ राज्यों में, प्रशासन जिला पुलिस अधीक्षक के अधीन है, जो पुलिस महानिदेशक के नियंत्रण के अधीन है[34], तीन, कुछ राज्यों ने एनपीसी की सलाह का पालन किया है और पुलिस का नियंत्रण जिला पुलिस–अधीक्षक को सौंप दिया है, साथ ही जिला मजिस्ट्रेट की समन्वयक की भूमिका को स्वीकार कर लिया है।[35]

2.5.1.2.6 ifyl vk;ä ç.kkyh

जिला स्तर पर दोहरी नियंत्रण प्रणाली को लेकर काफी विरोध हुआ था, यह विरोध इसकी शुरूआत के समय से ही था। दरअसल, यहां तक कि सरकार ने महसूस किया था कि पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 4 द्वारा निर्धारित जिला प्रणाली मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों में कुशलता से काम नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ जटिल पुलिस समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसलिए, कुछ मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों जैसे बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में, उन्होंने एक और प्रणाली पेश की– पुलिस की कमीशन प्रणाली।

---

32 राष्ट्रीय पुलिस आयोग, पांचवीं रिपोर्ट, नवंबर, 1980, प 39

33 धारा 14, असम पुलिस अधिनियम, 2007; बिहार पुलिस अधिनियम, 2007; धारा 5, छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007; और धारा 5, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम, 2007

34 धारा 16, राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 और धारा 4, त्रिपुरा पुलिस अधिनियम, 2007

35 धारा 10 और 14, हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007; धारा 10 और 16, पंजाब पुलिस अधिनियम, 2007; और धारा 8 और 13, सिक्किम पुलिस अधिनियम, 2008

इस प्रणाली को 1864 में बम्बई में 1866 के कलकत्ता उपनगरीय पुलिस अधिनियम द्वारा मद्रास में 1888 के मद्रास सिटी पुलिस अधिनियम और हैदराबाद में हैदराबाद सिटी पुलिस एक्ट (1348 एफ के अधिनियम प्) के माध्यम से निजाम की सरकार द्वारा हैदराबाद में शुरू किया गया था। स्वतंत्रता के बाद से इस प्रणाली को कई नए शहरों में शुरू किया गया है। उन क्षेत्रों के बारे में जानकारी जहां वर्तमान में यह प्रणाली मौजूद है, निम्न तालिका में दी गई है:

rkfydk 10% iqfyl vk;qä ç.kkyh okys 'kgj ¼1 tuojh 2017 dk½[36]

Øekad	;wfuV	la[;k	'kgjksa ds uke
1	आंध्र प्रदेश	2	विशाखापतनम, विजयवाड़ा, हैदराबाद, सायराबाद
2	असम	1	बड़ोदा, अहमदाबाद, राजकोट, सूरत
3	गुजरात	4	गुड़गांव, फरीदाबाद, अम्बाला–पंचकुला
4	हरियाणा	3	बेंगलुरू, मैसूर, हुबली–धारवाड़, मैंगलोर,
5	कर्नाटक	5	तिरुअन्नतपुरम, कोच्वी, कोझीकोड़, कोल्लम, त्रिचुर,
6.	केरल	5	मुम्बई, नाशिक, औरगांबाद, सोलापुर, पूना, थाने, नवी मुम्बई, नागपुर, अमरावती और आर. मुम्बई
7	महाराष्ट्र	10	भुवनेश्वर, कटक
8	नागालैंड	1	अमृतसर, जालाधंर, लुधियाना
9	ओडिसा	1	जयपुर, जोधपुर
10	पंजाब	3	ग्रेटर चेन्नई, सलेम, कोयम्बटूर, मदूराई, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली, तिरुपूर
11	राजस्थान	2	असनसोल,–दूर्गापुर, बैरकपूर, बिधाननगर, हावड़ा, कोलकाता, सिलिगुरी
12	तमिलनाडू	7	चेन्नई, सलेम, कोयम्बटूर, मदूराई, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली, तिरुपूर, त्रिची
13	तेलगांना	9	सायराबाद, हैदराबाद, करीमनगर, खम्मम, निजामाबाद, रचाकोडां, सिध्दीपेट, वारागंल,
14	पश्चिम बंगाल	6	असनसोल,–दूर्गापुर, बैरकपूर, बिधाननगर, हावड़ा
15	एनसीटी दिल्ली	1	दिल्ली
	VksVy	**60**	

इन शहरों में ऑफिसरिंग पैटर्न समान नहीं है। दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े महानगरीय शहरों में, पुलिस आयुक्त ही पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) का पद होता है, जबकि कुछ शहरों में वे एडिशनल डीजीपी/आईजीपी/डीआईजी का पद धारण करते हैं।

36 1 जनवरी 2017 को भारत में पुलिस संगठनों पर डेटा, तालिका 2.6, पृष्ठ 31

इस प्रणाली में पुलिस अधिकारियों की रैंक संरचना अलग–अलग है, हालांकि अधीनस्थ पुलिस कर्मियों का रैंक जिला पुलिस के समान है। पुलिस आयुक्त प्रणाली में रैंक संरचना निम्नानुसार हैः

- पुलिस आयुक्त
- पुलिस के विशेष आयुक्त
- संयुक्त पुलिस आयुक्त (जेसीपी)
- पुलिस के एडिशनल आयुक्त (ऐड सीपी)
- पुलिस उपायुक्त (डीसीपी)
- सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी)
- पुलिस के निरीक्षक
- पुलिस के सब–इंस्पेक्टर
- पुलिस के सहायक सब–इंस्पेक्टर
- हेड कांस्टेबल
- कांस्टेबल

पुलिस के आयुक्त और जिला सिस्टम के बीच दो मुख्य अंतर हैंः

1. पुलिस आयुक्त संगठन और सरकार में उनके विभागीय प्रमुखों के अलावा किसी अन्य कार्यकर्ता के अधीन काम नहीं करता है, जबकि जिला अधीक्षक पुलिस जिला मजिस्ट्रेट के सामान्य नियंत्रण और निर्देश के अधीन भी काम करता है। कोलकाता और मुंबई में, पुलिस कमिश्नर सीधे राज्य सरकारों के अधीन काम करते हैं।
2. जिला या राज्य पुलिस बल के प्रमुख के विपरीत, पुलिस आयुक्त में नियमित पुलिस शक्तियों के अतिरिक्त विनियमन, नियंत्रण, लाइसेंसिंग आदि की मजिस्ट्रेट शक्तियों भी निहित है।

2.5.1.2.7 ftyk l'kL= fjtoZ

जिला सशस्त्र रिजर्व, जिला पुलिस की वह सशस्त्र शाखा है जो ज़िले में उभरती कानून व्यवस्था में सिविल पुलिस की सहायता करती है और सुरक्षा गार्ड, एस्कॉर्ट्स और अन्य समान निर्धारित कर्तव्यों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। जैसे सशस्त्र पुलिस बटालियन राज्य स्तर के रिजर्व हैं, यह रिजर्व जिला पुलिस और जिला पुलिस अधीक्षक के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत कार्य करती है।

इस रिजर्व की संगठनात्मक संरचना प्रत्येक ज़िले में भिन्न हो सकती है, लेकिन कई राज्यों में, पुलिस निरीक्षक के पद के अधिकारी रिज़र्व के प्रभारी हैं। सशस्त्र पुलिस इकाइयों की तरह, यह रिजर्व प्लाट्स और खंडों में बांटा गया है, प्रत्येक का नेतृत्व क्रमशः उप–निरीक्षक और हेड कांस्टेबल ऑफ पुलिस द्वारा किया जाता है।

2.5.1.2.8 iqfyl LVs'ku

जिला संरचना में, पुलिस स्टेशन का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सभी पुलिस कार्यों की मूल इकाई है। सीआरपीसी के तहत, सभी अपराध एक पुलिस स्टेशन में दर्ज किए जाते हैं और सभी निवारक, जांच और कानून व्यवस्था का कार्य वहां से किया जाता है। यह जिले में पुलिस और जनता के बीच संपर्क और बातचीत का प्रमुख बिंदु है।

पुलिस अधिनियम राज्य सरकारों को पुलिस महानिदेशक के परामर्श से और अधिसूचना द्वारा, ज़िले में जनसंख्या, क्षेत्र, अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति और पुलिस स्टेशन तक पहुंचने के लिए कितनी दुरी तय करनी होगी तथा अन्य आवश्यकता के अनुसार कई पुलिस स्टेशनों के निर्माण के लिए प्राधिकृत करती हैं।

2.5.1.2.8.1 iqfyl LVs'kuksa dh la[;k

वर्ष 2017 की शुरुआत में देश में पुलिस स्टेशनों की संख्या निम्नलिखित तालिका में दिखाई गई है:

rkfydk 11% ns'k esa Loh—r vkSj okLrfod iqfyl LVs'kuksa dh la[;k ¼1 tuojh 2017 rd½[37]

Loh—r				okLrfod			
'kgjh	xzkeh.k	jsyos	laiw.kZ	'kgjh	xzkeh.k	jsyos	laiw.kZ
4,998	10,052	529	15,579	5,036	9,932	520	15,488

1 जनवरी 2017 को देश में स्वीकृत पुलिस स्टेशनों की संख्या 15,579 थी, जिनमें से 10,052 (64.52%) ग्रामीण इलाकों में थे, जबकि 4,998 (32.08%) शहरी स्थानों में थे। शेष 529 (3.40%) सरकारी रेलवे पुलिस स्टेशन (जीआरपी) थे। हालांकि, सभी स्वीकृत पुलिस स्टेशन 2016 के अंत तक स्थापित नहीं किए गए थे। वास्तविक संख्या 15,488 थी। इस प्रकार जमीन पर 91 पुलिस स्टेशनों की कमी थी।

पिछले कुछ वर्षों में पुलिस स्टेशनों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 1 जनवरी 2003 को 12,476 पुलिस स्टेशनों से, यह 1 जनवरी 2017 को 15579 हो गया, इस प्रकार 24.87% की वृद्धि दर्ज की गई।

2.5.1.2.8.2 jkT;ksa@la?k 'kkflr çns'kksa esa efgyk iqfyl LVs'ku

कुछ राज्यों / शहरों ने भी महिला पुलिस कर्मियों द्वारा प्रबंधित और संचालित पुलिस स्टेशनों की स्थापना का प्रयोग किया है। 4 सितंबर, 2009 को, केंद्र ने सभी राज्य सरकारों को प्रत्येक पुलिस स्टेशन, विशेष महिला पुलिस सेल और सभी महिला पुलिस स्टेशनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए समर्पित डेस्क स्थापित करने के लिए एक विस्तृत सलाह जारी की थी।

37 1 जनवरी 2017 को भारत में पुलिस संगठनों पर डेटा, तालिका 2.2।, पृष्ठ। 26।

जनवरी, 2017 की शुरुआत में, देश में 613 सभी महिला पुलिस स्टेशन थे।[38] सबसे बड़ी संख्या अर्थात 203 (33.11:) अकेले तमिलनाडु में काम कर रही थीं। उत्तर प्रदेश में 71. पश्चिम बंगाल, राजस्थान और बिहार प्रत्येक में 40, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम ने वर्ष 2016 के अंत तक ऐसा कोई पुलिस स्टेशन स्थापित नहीं किया था।

2.5.1.2.8.3 iqfyl LVs'ku& Hkwfedk vkSj dk;Z

लोग न केवल अपराध या कानून और व्यवस्था में अशांति की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं, बल्कि संकट की परिस्थितियों में सहायता और राहत भी चाहते हैं। वे शिकायत दर्ज कराने और समाधान खोजने के लिए वहां जाते हैं।

कानून और पुलिस मैनुअल के आधार पर पुलिस स्टेशन पर काम का चार्टर बहुत व्यापक है। पुलिस स्टेशन में किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में से हैं:[39]

1. प्रभावी अपराध निवारण उपायों का उपयोग कर अपराध की रोकथाम
2. प्राप्त जानकारी पर संज्ञेय अपराधों का पंजीकरण
3. शीघ्र, निष्पक्ष और कुशल जांच
4. क्षेत्र में शांति बनाए रखना
5. नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनकी संपत्ति की रक्षा करना
6. पुलिस स्टेशन पर प्राप्त शिकायतों का समुचित निपटान
7. मदद के लिए आने वाले लोगों की परेशानी का निदान करना और संकट की स्थिति में सहायता करना
8. समाज के विभिन्न हिस्सों के साथ दोस्ताना और सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना
9. कुशल और ईमानदार पुलिस के काम के लिए आवश्यक खुफिया जानकारी इकठ्ठा करना
10. नियामक कर्तव्यों और भीड़ प्रबंधन में भाग लेना।

2.5.1.2.8.4 iqfyl LVs'ku dk;Zdrk% mudh rkdr vkSj drZO;

सीआरपीसी, जिससे पुलिस अपराध और कानून व्यवस्था की समस्याओं से निपटने के लिए अपनी शक्तियां प्राप्त करती है, केवल एक पुलिस रैंक को पहचानती है– पुलिस स्टेशन के अधिकारी–प्रभारी। राज्य पुलिस अधिनियम के अनुसार, यह अधिकारी पुलिस के सब–इंस्पेक्टर के पद से नीचे नहीं हो सकता है।[40] सीआरपीसी पुलिस अधिकारी के अनुपस्थित होने पर प्रभारी अधिकारी से ठीक नीचे रैंक के अधिकारी को थाने का प्रभार लेने की अनुमति देता है।[41]

---

38 महिला पुलिस स्टेशनों की पूरी सूची के लिए, 1 जनवरी 2017 को भारत में पुलिस संगठनों पर डेटा देखें, तालिका 12.1, पृष्ठ 151

39 मॉडल पुलिस मैनुअल, वॉल्यूम 1, अध्याय 10।

40 धारा 2 (ओ), आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973,

41 इबिड, धारा 36, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973

पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी रैंक से उच्चतर अधिकारियों को उन्हीं अधिकारों का उपयोग करने की अनुमति दिया गया है, जो ऐसे ही अधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्र में किये जाते हैं।

इन दिनों, अधिकांश शहरों और महानगरों में, पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी पुलिस इंस्पेक्टर होता है।[42] यहां तक कि अन्य स्थानों पर, जहां क्षेत्र, आबादी, अपराध या कानून और व्यवस्था की समस्याओं के मामले में पुलिस स्टेशन बड़े होते हैं, प्रभारी अधिकारी पुलिस इंस्पेक्टर होता है। ग्रामीण क्षेत्रों या छोटे पुलिस स्टेशनों में, प्रभारी अधिकारी आमतौर पर पुलिस सब–इंस्पेक्टर होता है।

एक औसत पुलिस स्टेशन में आमतौर पर निम्नलिखित रैंक के अधिकारी होते हैं:

- पुलिस इंस्पेक्टर
- पुलिस के सब–इंस्पेक्टर
- पुलिस के सहायक सब–इंस्पेक्टर
- हेड कांस्टेबल
- कांस्टेबल

देश में पुलिस स्टेशनों के स्टाफिंग पैटर्न में काफी असमानताएं हैं। कुछ पुलिस स्टेशनों, विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में औसत पुलिस की संख्या शहरी या महानगरीय क्षेत्रों की तुलना में काफी कम होती है। एक मानक ग्रामीण और शहरी पुलिस स्टेशन की औसत रैंक–वार संख्या नीचे दिखाई गई है:[42]

rkfydk 12½ xkeh.k vkj 'kgjh ifyl LV'ku dh vklr Loh—r l[;k ¼1 tuojh 2009 rd½

ifyl LV'ku	bLiDVj	,l vkÃ	vfll- ,l vkÃ	gM d,LVcy	d,LVcy
शहरी	1	5	5	11	49
ग्रामीण	0	2	2	5	21

इनमें से प्रत्येक रैंक के कर्तव्यों पर नीचे चर्चा की गई है।

ifyl bLiDVj

पुलिस इंस्पेक्टर या तो पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी अर्थात स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) या पुलिस सर्किल इंस्पेक्टर के रूप में कार्य करता है।

,l,pvk

एसएचओ पुलिस का इंस्पेक्टर या सब–इंस्पेक्टर हो सकता है। पुलिस स्टेशन के प्रमुख के रूप में, वह मुख्य रूप से इसके प्रभावी कामकाज और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। यह सुनिश्चित करना उसकी ज़िम्मेदारी है कि पुलिस स्टेशन दक्षता और ईमानदारी के साथ ऊपर सूचीबद्ध आदर्शों के अनुसार अपने कार्यों को निष्पादित करता रहे; संक्षेप

42 बीपीआरडी, राष्ट्रीय ब्लूप्रिंट ऑन पॉलिसींग इश्यूज, 2010, पीपी 251–252

में, अपराधों को रोकने, शिकायत दर्ज करने, अपराधों की जांच करना, शांति संरक्षित रखना, अपराधियों को पकड़ना और अदालत में कार्रवाई करवाना, सब उसका कर्तव्य है। अपने अधिकार क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को सुरक्षा और संरक्षण की भावना प्रदान करना अनिवार्य रूप से उसका कार्य है।

कर्मचारियों का प्रशासन करना, उनके काम पर निगरानी रखना, उनकी गतिविधियों पर पैनी नजर रखना और संसाधनों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करना उसका कर्तव्य है। वह अपने अधीन कर्मचारियों को कार्य देता है और यह भी देखता है कि ये कार्य ईमानदारी से किए जाएं । क्षेत्र का पूर्ण ज्ञान एकत्र करना और अपने क्षेत्र में लोगों की समस्याओं की पूरी जानकारी हासिल करना उसकी ज़िम्मेदारी है।

जनता के साथ अच्छे संबंधों को बनाना उसके चार्टर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

l dly bLiDVj

कुछ राज्यों में पुलिस का एक इंस्पेक्टर, सर्किल इंस्पेक्टर के रूप में भी काम करता है। एक सर्कल में आम तौर पर दो या दो से अधिक पुलिस स्टेशन होते हैं, जहां प्रभारी अधिकारी पुलिस सब–इंस्पेक्टर होता है।

सर्किल इंस्पेक्टर के प्रमुख कर्तव्य हैं गंभीर मामलों की जांच करना, अपनी सर्किल के पुलिस कार्य की सभी शाखाओं में पर्यवेक्षण करना, उनके अधीनस्थों के बीच अनुशासन बनाए रखना, उनके कल्याण की देखभाल करना, हथियार और अन्य सरकारी संपत्ति का रखरखाव देखना और जिला सुपरिटेंडेंट और सब–डिवीजनल पुलिस ऑफिसर (एसडीपीओ) को सर्कल की पुलिस व्यवस्था की समस्याओं के बारे में सूचित करना है।[43] जिला एसपी या एसडीपीओ अक्सर जनता से प्राप्त शिकायतों की जांच करने का काम उसे सौंपता है।

ifyl d lc&bLiDVj

पुलिस स्टेशन (एसएचओ) के प्रभारी अधिकारी के रूप में काम कर रहे सब–इंस्पेक्टर उन्हीं कर्तव्यों का पालन करता है जो उस शाखा में पुलिस इंस्पेक्टर करता है। एसएचओ के रूप में काम का चार्टर बिल्कुल उन्हीं चिन्हों पर है।

पुलिस स्टेशनों में तैनात पुलिस के अधिकांश सब–इंस्पेक्टर जांच कार्य करते हैं। ज़रूरत पड़ने पर उन्हें कानून और व्यवस्था का काम भी सौंपा जा सकता है।

ifyl d lgk;d lc&bLiDVj

पुलिस के सहायक सब–इंस्पेक्टर के कर्तव्य हैं:[44]

- एसएचओ द्वारा निर्देशित सरल मामलों की जांच
- याचिका संबंधी पूछताछ
- सत्यापन भूमिका में पूछताछ की जांच
- प्रक्रिया कार्य का पर्यवेक्षण (सम्मन और वारंट देने का कार्य)
- बीट्स और गश्ती की जांच

---

43 कर्नाटक पुलिस मैनुअल, खंड 1, अध्याय 6

44 इबिड

- स्टेशन लेखन कार्य का पर्यवेक्षण
- सब–इंस्पेक्टर की अनुपस्थिति के दौरान कर्मचारियों को कार्यों का विवरण करना और उन पर पर्यवेक्षण करना
- हथियार, गोला बारूद और इसके साथ जुड़े रजिस्टरों (गणनापत्रों) का रखरखाव
- ऐसे अन्य काम जिन्हें उन्हें सौंपा जा सकता है।

ifyl d çe[k dkLVcy

पुलिस के हेड कांस्टेबल आम तौर पर तीन तरीकों से नियोजित किये जाते हैं: पुलिस स्टेशनों पर सामान्य कार्य पर; स्टेशन लेखक के रूप में; और चौकी के प्रभारी।

एसएचओ के अनुपस्थित होने पर सीआरपीसी की धारा 2 (ओ) के सिवाय एक हेड कांस्टेबल को पुलिस स्टेशन का प्रभार नहीं दिया जा सकता है।

एक पुलिस स्टेशन में सामान्य कर्तव्य पर एक हेड कांस्टेबल के प्राथमिक कर्तव्य हैं:

- कॉन्स्टेबल के काम की निगरानी करें, उनके ड्रिल को देखें और निर्देश प्रदान करें
- स्टेशन हाउस ऑफिसर द्वारा दिए गए कर्तव्यों का पालन करें
- जांच कार्य पर एसएचओ या जांच अधिकारी के साथ उपस्थिति, जब भी आवश्यक हो, रहना।
- गार्ड या अनुरक्षण का कर्त्तव्य सौंपे जाने पर उसका प्रभारी होना
- तिमाही में कम से कम एक बार स्टेशन क्षेत्राधिकार में गांवों का भ्रमण करें
- बीट/इलाके के काम की जांच और पर्यवेक्षण करें
- स्टेशन हाउस ऑफिसर के आदेश के तहत अदालत के काम में भाग लें
- छोटी शिकायतों में पूछताछ करना और
- एसएचओ द्वारा ऐसा करने के लिए कहे जाने पर सरल मामलों में जांच करना

एक स्टेशन लेखक के रूप में, उसका मुख्य कर्तव्य एसएचओ के निर्देश के अनुसार स्टेशन के दफ्तर के कार्य को निष्पादित करना है। वह पुलिस स्टेशन में सभी रिकॉर्ड और रजिस्टरों को बनाए रखता है।

पुलिस चौकी के प्रभारी के रूप में, हेड कांस्टेबल का कर्तव्य है कि चौकी में तैनात सिपाहियों के काम की निगरानी करना, निर्धारित रिकॉर्ड बनाए रखना और पुलिस स्टेशन को समय पर रिपोर्ट भेजना ।

एक चौकी के प्रभारी हेड कांस्टेबल को एफआईआर दर्ज करने का अधिकार नहीं है। यदि चौकी पर किसी संज्ञेय अपराध की जानकारी प्राप्त होती है, तो उसे चौकी की डायरी में मामले के तथ्यों को रिकॉर्ड करने के बाद इसे तुरंत पुलिस स्टेशन में भेजना होगा। घटना के स्थल पर एक बार जाना होगा, सबूतों को संरक्षित करना, मामले के बारे में जानकारी एकत्र करना और आरोपी को गिरफ्तार करने जैसी आवश्यक कार्रवाई करना उसका कर्तव्य है।

ifyl dkLVcy

एक कॉन्स्टेबल के मुख्य कर्तव्य निम्नलिखित हैं:

1. गश्ती और निगरानी कार्य

2. अपराध और अपराधियों के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करें और संबंधित अधिकारियों को इसकी सुचना दें
3. गिरफ्तारी, पुनः प्राप्ति, खोज और दौरे करने में जांच अधिकारी की सहायता करें
4. प्रक्रियाओं का पालन करें
5. कैदियों की निगरानी और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का कार्य
6. घायलों को अस्पताल पहुँचाना
7. भीड़ को नियंत्रित करने और आपात स्थिति में राहत प्रदान करने में मदद
8. ऐसा कार्य सौंपे जाने पर यातायात को नियंत्रित करें
9. स्थानीय विवादों और विवाद संघर्ष की पूरी जानकारी रखना और
10. अन्य सौंपे हुए कार्य पूर्ण करना

2.5.1.2.8.5 iqfyl LVs'ku fjdkMZl

पुलिस स्टेशनों पर विभिन्न प्रकार के रिकॉर्ड रखे जाते है। इनमें से कुछ निम्नानुसार हैंः

1. पहली सूचना रिपोर्ट रजिस्टर
2. दैनिक डायरी / स्टेशन सामान्य डायरी
3. अपराध रजिस्टर
4. गिरफ्तारी रजिस्टर
5. फरार कैदी रजिस्टर
6. ग्राम अपराध नोट बुक
7. निगरानी रजिस्टर
8. छोटे मामलों संबंधी रजिस्टर
9. प्रक्रिया रजिस्टर
10. गोपनीय रजिस्टर
11. लाइसेंस का रजिस्टर
12. पत्राचार का रजिस्टर
13. स्थायी आदेश और परिपत्र पुस्तक
14. राजपत्रित अधिकारियों के लिए मिनट बुक

सार्वजनिक दृष्टिकोण से, इनमें से दो रिकॉर्ड महत्वपूर्ण हैंः पहली सूचना रिपोर्ट पुस्तिका और दैनिक डायरी रजिस्टर।

पहली सूचना रिपोर्ट पुस्तिका किसी दिए गए वर्ष के दौरान पंजीकृत सभी एफआईआर का रिकॉर्ड रखती है। मामले प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में प्रत्येक पुलिस स्टेशन में वार्षिक सीरियल नंबर के साथ होते हैं। रिपोर्ट में शिकायतकर्ता के नाम और निवास के बारे में जानकारी शामिल होती है; अपराध का एक संक्षिप्त विवरण; घटना की तारीख और समय; पुलिस स्टेशन से घटना, स्थान की दूरी और; जांच के संबंध में उठाए गए कदम; रिकॉर्डिंग जानकारी में देरी के लिए स्पष्टीकरण, यदि कोई हो; और पुलिस स्टेशन से प्राथमिकी के प्रेषण की तारीख और समय।

डेली डायरी रजिस्टर दिन के दौरान की गई मुख्य गतिविधियों का पुलिस स्टेशन का लॉग है। इसमें एफआईआर के साथ–साथ गैर–संज्ञेय केस रिपोर्ट का एक सारांश भी शामिल है; गिरफ्तारी के बारे में जानकारी; हिरासत में लिए गए व्यक्ति; जांच अधिकारी (आईओ) द्वारा जब्त संपत्ति के मामले की जानकारी और पुलिस थाना से इसकी प्रेषण; सम्मन और वारंट की प्राप्ति; मालखाने में रखे हुए नकदी समेत संपत्तियों की जांच[45]

खराब चरित्र के व्यक्तियों के बारे में जानकारी; जांचकर्ता अधिकारियों द्वारा उन्हें दिए गए मामलों में उठाए गए कदम आदि। दैनिक डायरी का एक और हिस्सा नियमित रूप से बरक़रार रखा जाता है जैसे पुलिस कर्मियों के आगमन और प्रस्थान, गश्ती कर्मचारियों का प्रेषण, पहरे पर तैनाती, अलग–अलग कर्तब्यों पर तैनात पुलिसकर्मियों के पुलिस स्टेशन से आगमन और प्रस्थान की जानकारी।

2.5.2 ifyl e[;ky; LFkkiuk

फील्ड इकाइयों के अलावा, हर राज्य पुलिस के मुख्यालय की स्थापना होती है। राज्य पुलिस बल जिसमें अपनी फील्ड इकाइयों और मुख्यालयों की स्थापना शामिल है, की अध्यक्षता पुलिस महानिदेशक के पद के अधिकारी द्वारा होती है। मुख्यालय में महानिदेशक, इंस्पेक्टर जनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल और सहायक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पद के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, जो उनके काम में उनकी सहायता करते हैं।

स्थापना विभिन्न शाखाओं / विभागों में विभाजित होती है, जो सामान्य रूप से एडिशनल डीजी या आईजीपी के पद के अधिकारियों की अध्यक्षता में होती हैं। कुछ राज्यों में, डीजीपी के पद के अधिकारियों (लेकिन राज्य पुलिस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त नहीं) को कभी–कभी इन विभागों का प्रभार दिया जाता है।

2.5.2.1 ifyl e[;ky; dh Hkfedk vkj ftEenkfj;k

पुलिस कानून के अनुसार राज्य पुलिस बल का प्रशासन पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) में निहित है।

पुलिस मुख्यालय राज्य पुलिस बल के समग्र कार्य और प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस भूमिका के कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं:

1. पुलिस के प्रशासन और दक्षता से संबंधित सभी मामलों पर बल के प्रमुख के रूप में डीजीपी राज्य सरकार का मुख्य सलाहकार है।
2. डीजीपी पुलिस में सभी शाखाओं, हेडक्वॉर्टर के साथ–साथ फील्ड इकाइयों के कामकाज की निगरानी और समन्वय करता है।
3. बल के प्रमुख के रूप में, संगठन के सदस्यों को प्रेरित करना संगठन की विभिन्न इकाइयों और विभागों का प्रभावी संचार और मूल्यांकन सुनिश्चित करना डीजीपी का काम है,
4. मुख्यालय प्रशासनिक नियंत्रण और पर्यवेक्षण करता है और आवश्यक दिशा और मार्गदर्शन प्रदान करता है।
5. यह नीतियों के निर्माण, नियोजन और विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन और आदेशों के कार्यान्वयन के लिए ज़िम्मेदार है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पुलिस

45 कमरा जहां मामले से जुडी संपत्ति रखी जाती है

कुशल, प्रभावी और ईमानदार रहे। यह बल के लिए उद्देश्यों को निर्धारित करता है और सभी महत्वपूर्ण मामलों पर दिशानिर्देश प्रदान करता है।

6. मुख्यालय की ज़िम्मेदारी यह देखने की है कि पुलिस बल को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त ताकत, उपकरण, बजट और अन्य संसाधन मिलते रहे।
7. मुख्यालय की ज़िम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की है कि फील्ड इकाइयां जनता के साथ गलत व्यवहार न करें।

2.5.2.2 ifyl cy d çe[k dk p;u vkj dk;dky

सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह के मामले[46] में अपने फैसले में निर्देश दिया कि राज्य के पुलिस महानिरीक्षक को राज्य सरकार द्वारा विभाग के तीन वरिष्ठ अधिकारियों में से चुना जाना चाहिए जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उस पद के लिए सूचीबद्ध किया गया है। सुपरन्यूएशन (पेंशन) की तारीख के बावजूद उनके पास कम से कम दो साल का न्यूनतम कार्यकाल होना चाहिए।

राज्य सरकारों द्वारा तैयार पुलिस अधिनियिम में प्रावधान न्यायालय के निर्देश से भिन्न होते हैं। अधिकांश राज्य सरकारों ने कानून बना दिया है कि राज्य पुलिस बल के प्रमुख का चयन उन अधिकारियों में से किया जाना चाहिए जो डीजीपी रैंक धारण करते हैं या डीजीपी पद के पदोन्नति के पात्र हैं। इसी प्रकार, कार्यकाल की सुरक्षा पर, कुछ ने दो साल का न्यूनतम कार्यकाल निर्धारित किया है, जबकि अन्य डीजीपी को एक वर्ष से अधिक कार्यकाल प्रदान करने के इच्छुक नहीं हैं।

2.5.2.3 ifyl e[;ky; e foHkkx@'kk[kk,a

इसे अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में सक्षम बनाने के लिए, राज्य पुलिस मुख्यालय को विभिन्न शाखाओं / विभागों में बांटा गया है। राज्यों में कुछ मामूली अंतर हो सकते हैं, लेकिन व्यापक रूप से राज्य पुलिस बल के मुख्यालय में मुख्य विभाग निम्नलिखित हैं:

1. प्रशासन/स्थापना शाखा
2. आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी)
3. खुफिया विभाग
4. सशस्त्र पुलिस
5. रेलवे पुलिस
6. यातायात पुलिस
7. आतंकवाद विरोधी दल / सेल
8. प्रशिक्षण निदेशालय
9. राज्य अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो
10. पुलिस प्रतिष्ठान बोर्ड
11. नागरिक अधिकार कक्ष की सुरक्षा
12. मोटर परिवहन इकाई

---

46 प्रकाश सिंह और अन्य वी संघ और अन्य (2006), 8 एससीसी 1

13. पुलिस दूरसंचार शाखा

14. सूचना का अधिकार (आरटीआई) सेल।

इनमें से कुछ विभागों के संबंध में जानकारी नीचे दी गई है:

2.5.2.3.1 vkijkfèkd tkp foHkkx ¼lhvkÃMh½

सीआईडी राज्य पुलिस की सबसे महत्वपूर्ण जांच एजेंसी है। यह कुछ विशेष अपराधों की जांच करती है जैसे कि नकली नोट, पेशेवर धोखाधड़ी, गिरोह के मामले, अंतर–जिला या अंतर–राज्य सहत्व आदि के गंभीर अपराध आदि। कभी–कभी, जब कुछ प्रमुख अपराध अनसुलझे रहते हैं या जांच के लिए सार्वजनिक मांग होती है कि राज्य पुलिस के अतिरिक्त किसी और एजेंसी के द्वारा भी जाँच होनी चाहिए, सरकार या राज्य पुलिस बल के प्रमुख स्थानीय पुलिस से सीआईडी द्वारा जांच के लिए मामलों को स्थानांतरित करती है। कभी–कभी अदालतें सरकार को सीआईडी की जांच करने के लिए निर्देशित करती हैं। नागरिक द्वारा शिकायत सीधे सीआईडी द्वारा स्वीकार नहीं की जाती।

विशेष अपराधों जैसे कि हत्या, संपत्ति संबंधी अपराध फ्राड/धोखाधड़ी, आर्थिक अपराध, जालसाज़ी से निपटने के लिए सीआईडी के पास विशेष शाखाएं होती हैं।

2.5.2.3.2 [kfQ;k foHkkx

यह विभाग अपराध, कानून और व्यवस्था में गड़बड़ी और सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण मुद्दों पर आसूचना संग्रह, संयोजन, विश्लेषण और खुफिया जानकारी के प्रसार के लिए ज़िम्मेदार है। यह व्यक्तियों, पार्टियों और संगठनों की विध्वंसक गतिविधियों पर नजर रखती है और सभी को इस तरह की गतिविधियों के बारे में सूचित करती है। यह विदेशियों और पासपोर्ट से संबंधित मामलों से भी संबंधित है। आतंकवाद, सांप्रदायिकता, राजनीतिक दलों, श्रमिक संघों, छात्रों के मोर्चों आदि से निपटने के लिए इसमें अलग–अलग इकाइयां हैं। यह केंद्रीय और राज्य स्तर पर अन्य पुलिस बलों की खुफिया एजेंसियों के समन्वय में काम करती है। अधिकांश राज्य खुफिया विभागों के पास अपने कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए अपने स्वयं के प्रशिक्षण स्कूल होते हैं।

2.5.2.3.3 l'kL= ifyl

एक राज्य पुलिस बल में दो मुख्य घटक हैं – सिविल पुलिस और सशस्त्र पुलिस। सिविल पुलिस का प्राथमिक कार्य अपराध को नियंत्रित करना है, जबकि सशस्त्र पुलिस, कानून और व्यवस्था की स्थितियों से निपटने में सिविल पुलिस की सहायता करती है। सिविल पुलिस में जिला पुलिस बल, सीमा, क्षेत्र और राज्य पुलिस मुख्यालयों में पर्यवेक्षी संरचनाएं और अपराध, खुफिया और प्रशिक्षण समस्याओं से निपटने के लिए विशेष शाखाएं शामिल हैं। सशस्त्र पुलिस आपातकालीन स्थितियों से निपटने में सिविल पुलिस की सहायता के लिए बटालियनों के रूप में उपयोग की जाती है।

लगभग सभी राज्यों में अपनी सशस्त्र पुलिस बलों होती है। एडिशनल डीजी या आईजी पद के अधिकारी राज्य सशस्त्र पुलिस के काम की देखरेख करते है। सशस्त्र पुलिस उन क्षेत्रों में तैनात होने के लिए आरक्षित बल के रूप में कार्य करने के लिए है जहां जिला पुलिस परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से सामना करने में असमर्थ होती है।

राज्य सशस्त्र पुलिस की स्वीकृत और वास्तविक ताकत पर डेटा ऊपर दिया गया है। यह शक्ति बटालियनों के रूप में फैली हुई है।

1 जनवरी 2017 को 470राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियन और पांच कम्पनियां थीं।[47]

एक राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियन कंपनियों में बांटा गया है। आम तौर पर, बटालियन में छह सेवा कंपनियां होती हैं। एक कंपनी को प्लाटूनों और प्लाटूनों को खण्डों में विभाजित किया जाता है। आम तौर पर तीन खंड एक प्लाटून बनाते हैं और तीन प्लाटून एक कंपनी बनाते हैं। एक सशस्त्र पुलिस बटालियन की ताकत 800 से 1000 कर्मियों तक है।

एक सशस्त्र पुलिस बटालियन की रैंक संरचना सिविल पुलिस से अलग है। बटालियन के मुखिया को कमांडिंग ऑफिसर या कमांडेंट कहा जाता है, जो पुलिस अधीक्षक रैंक के बराबर है। आमतौर पर उसके पास कमांड में दूसरा स्थान होता है, जिसे डिप्टी कमांडेंट कहा जाता है, जो एडिशनल एसपी रैंक के समान होता है। ज्यादातर मामलों में एक कंपनी को सहायक कमांडेंट नामक एक अधिकारी द्वारा आदेश दिया जाता है, जो पुलिस अधीक्षक के बराबर होता है। कुछ राज्यों में, एक कंपनी को सुबेदार द्वारा आदेश दिया जा सकता है, जो पुलिस के इंस्पेक्टर रैंक के बराबर है। एक प्लैटून को सब–इंस्पेक्टर द्वारा आदेश दिया जाता है और एक अनुभाग हेड कांस्टेबल का प्रभारी होता है। एक हेड कांस्टेबल के बाद कमांड में दूसरा स्थान नाइक का होता है। कुछ मामलों में, नाइक और कॉन्स्टेबल के बीच, एक और रैंक लांस नाइक के नाम से जाना जाता है।

2.5.2.3.4 jyo ifyl

अधिकांश राज्यों में रेलवे लाइनें अपने अधिकार क्षेत्र से गुज़रती हैं। रेलवे पर पुलिसिंग सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) द्वारा की जाती है। रेलवे में अपराध नियंत्रित करना इस संगठन की मुख्य जिम्मेदारी है। हालांकि जीआरपी राज्य पुलिस बल का हिस्सा है, इस प्रतिष्ठान पर व्यय राज्य सरकार और रेलवे के बीच साझा किया जाता है। एडिशनल डीजी या आईजीपी जीआरपी के काम की देखरेख करता है। एक रेलवे पुलिस जिले के अधीक्षक का अधिकार क्षेत्र कई जिलों की सीमाओं में फैला होता है।

रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के साथ जीआरपी को भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, जिसे रेलवे संपत्ति की रक्षा के लिए अनिवार्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है। आरपीएफ रेल मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रण में काम करता है, जबकि जीआरपी राज्य पुलिस बल का हिस्सा है।

2.5.2.3.5 jkT; vijkèk fjd,Ml C;jk

स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एससीआरबी) का मुख्य कार्य विभिन्न अपराधों जैसे विशेष रूप से धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक विश्वास उल्लंघन डकैती, चोरी, हत्या, अपहरण या फिरौती के लिए अपहरण, विरूपण, विस्फोटक, तबाही, राज्य के खिलाफ अपराध, आतंकवादी कृत्यों और नशीले पदार्थों से सम्बंधित अपराध पर डेटा एकत्र करना, विश्लेषण करना और प्रसार करना है। । अपराधों के अलावा, यह गिरफ्तार किए

47 1 जनवरी 2017को भारत में पुलिस संगठनों पर डेटा, 2017, प 18

गए लोगों और अंतर–ज़िले के अपराधियों, फरार व्यक्तियों, लापता लोगों और अज्ञात मृत निकायों में दोषी लोगों के बारे में जानकारी एकत्र करता है। यह संपत्ति चोरी और पुनर्प्राप्त संपत्ति का ब्योरा रखता है। यह विभिन्न प्रकार के अपराधों में अपराधियों द्वारा इस्तेमाल तरीकों पर नज़र रखता है।

यह काम अपराध और आपराधिक सूचना प्रणाली जैसे विभिन्न प्रणालियों के माध्यम से किया जाता है जैसे कि फिंगरप्रिंट सिस्टम; आर्थिक अपराध, नशीले पदार्थों और दवाओं पर सूचना प्रणाली; संपत्ति समन्वय प्रणाली; नकली मुद्रा प्रणाली; गिरफ्तार / वांछित व्यक्ति सूचना प्रणाली; आतंकवादी सूचना प्रणाली; कर्मियों की सूचना प्रणाली; चित्र निर्माण प्रणाली, आदि।

एससीआरबी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो के साथ लगातार संपर्क में रहता है और इसके साथ–साथ राज्य में जिला अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के साथ डेटा का आदान–प्रदान करता है। यह राज्य पुलिस बल में कम्प्यूटरीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है।

2.5.2.3.6 çf'k{k.k fun'kky;

प्रशिक्षण निदेशालय का नेतृत्व आमतौर पर एक एडिशनल महानिदेशक पुलिस द्वारा होता है। इसका मुख्य कार्य है उत्कृष्ट प्रशिक्षण द्वारा विभिन्न रैंकों के कुशल, प्रभावी और ईमानदार पुलिस अधिकारी तैयार करना। निदेशालय के कुछ विशिष्ट कार्य हैं:

1. पुलिस प्रशिक्षण की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण नीतियों को तैयार करने के लिए पुलिस प्रशिक्षण के लिए समय–समय पर व्यवस्था की समीक्षा करना
2. मौजूदा पाठ्यक्रम की समीक्षा करना और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में बदलाव का सुझाव देना
3. विभिन्न रैंकों के लिए आवश्यक नए रिफ्रेशर, प्री–प्रमोशन, विशेषज्ञ और अभिविन्यास पाठ्यक्रम तैयार करना
4. राज्य और पुलिस गतिविधियों में पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों की निगरानी और पर्यवेक्षण करना
5. राज्य पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार करना
6. पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के लिए मानक शिक्षण साहित्य तैयार करना
7. प्रशिक्षण संस्थानों को उत्पादन और आपूर्ति के लिए प्रशिक्षण उपकरण और सहायक उपकरण मानकीकृत करना

2.5.2.3.7 vkradokn fojks/kh ny@ly

सभी राज्यों में आतंकवाद से निपटने के लिए एक अलग विभाग मौजूद नहीं है। आतंकवादी गतिविधियों के फैलाव के कारण कुछ राज्यों ने ऐसे विभाग स्थापित किए हैं। विभाग मुख्य रूप से आतंकवादी संगठनों और उनकी गतिविधियों का ट्रैक रखने और ऐसी गैर–राष्ट्रीय ताकतों को बेअसर करने के लिए आवश्यक कदम उठाता है। यह आईबी, सीबीआई, एनआईए आदि जैसे केंद्रीय खुफिया और जांच एजेंसियों के साथ

घनिष्ठ समन्वय में काम करता है और अन्य राज्यों में भी इसी तरह की एजेंसियों के साथ भी काम करता है।

2.5.2.3.8 ifyl çfr"Bku ckM

राज्य पुलिस मुख्यालय में इस बोर्ड की स्थापना एक नई पहल है। इस तरह के बोर्ड की आवश्यकता पहली बार रिबेरो कमेटी द्वारा पुलिस सुधार के लिए पेश की गई थी।[48]

दिनांक 25 मई, 1998

समिति ने सिफारिश की कि एक पुलिस प्रतिष्ठान बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए, जिसमे चेयरमैन के रूप में पुलिस महानिदेशक और चार वरिष्ठ अधिकारी जो पुलिस पदानुक्रम में उनके तुरंत जूनियर होने चाहिए। पुलिस उपायुक्त के पद उससे नीचे पद के अधिकारियों की पदोन्नति और स्थानान्तरण से संबंधित मामलों की निगरानी और देखरेख कर सके।[49]

प्रकाश सिंह के मामले में अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। न्यायालय ने निर्देश दिया कि प्रत्येक राज्य में पुलिस प्रतिष्ठान बोर्ड होना चाहिए जिसका कार्य होगा पुलिस के उप अधीक्षक के पद और उसके नीचे के पद के अधिकारियों के सभी पोस्टिंग, पदोन्नति और अन्य सेवा संबंधित मामलों की निगरानी".[50]

प्रतिष्ठान बोर्ड एक विभागीय निकाय होना चाहिए जिसमें पुलिस महानिदेशक और विभाग के चार अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। न्यायालय का मानना था कि राज्य सरकार बोर्ड के फैसले में हस्तक्षेप कर सकती है, लेकिन केवल असाधारण मामलों में ही और वह भी ऐसा करने के कारणों को रिकॉर्ड करने के बाद। प्रतिष्ठान बोर्ड को पुलिस–अधीक्षक के पद और ऊपर पद के अधिकारियों की तैनाती और स्थानांतरण के संबंध में राज्य सरकार को उचित सिफारिशें करने के लिए भी अधिकृत किया जाना चाहिए। सरकार को आमतौर पर ऐसी सिफारिशों को स्वीकार करना चाहिए।

न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि इस बोर्ड को पुलिस अधीक्षक के पद और उससे ऊपर पद के अधिकारियों की पदोन्नति / स्थानांतरण / अनुशासनात्मक कार्यवाही या उनके अवैध या अनियमित आदेशों के अध्यधीन होने से संबंधित अभ्यावेदनों का निपटान करने के लिए अपील के मंच के रूप में कार्य करना चाहिए। और साथ ही राज्य में पुलिस का कामकाज का निरीक्षण भी करना चाहिए।

कई राज्यों में जहां पुराने पुलिस अधिनियम, 1861 को बदलने के लिए नए पुलिस कानून लागू किए गए हैं, पुलिस प्रतिष्ठान बोर्ड स्थापित किए गए हैं। कुछ राज्यों में, यह कार्यकारी आदेशों के माध्यम से किया गया है। हालांकि, इस तरह के अधिकांश बोर्डों के कार्यों की संरचना और चार्टर सर्वोच्च न्यायालय के मत से अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 में केवल इस विषय पर निम्नलिखित प्रावधान हैः 1"राज्य सरकार एक पुलिस प्रतिष्ठान समिति का गठन कर सकती है पुलिस महानिदेशक के रूप में इसके अध्यक्ष और दो अन्य वरिष्ठ अधिकारी पुलिस, इंस्पेक्टर

48 गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित, कार्यालय ज्ञापन सं 11018/1/98–पीएमए के माध्यम से

49 इबिड

50 प्रकाश सिंह और अन्य वी संघ भारत और अन्य (20016) 8 एससीसी 1

जनरल के पद से नीचे नहीं होने चाहिए प्रशासनिक मामलों के लिए सदस्य (2) स्थापना समिति इन कार्यों के लिए योजना तैयार कर सकती है जैसे बुनियादी सुविधाएं, व्यावसायिकता, सेवा में सामान्य अनुशासन, आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण, पुलिस कर्मियों के कल्याण और राज्य सरकार द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।"[51]

2.6 ifyl d drO; vkj ftEenkfj;k

2.6.1 ifyl vfèkfu;e] 1861 e tl i'k fd; x, Fk

पुलिस अधिनियम, 1861 में पुलिस के लिए बहुत सीमित भूमिका प्रदान की गई। अधिनियम के धारा 23 में पुलिस अधिकारियों के लिए केवल निम्नलिखित कर्तव्यों को निर्धारित किया गया हैः

1. किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा कानूनी रूप से जारी किए गए सभी आदेशों और वारंट का पालन करें और निष्पादित करें
2. सार्वजनिक शांति को बनाए रखने के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और सूचना देना
3. अपराधों और सार्वजनिक उपद्रव को होने से रोकना
4. अपराधियो को पहचानना और कानून के आगे लाना
5. उन सभी लोगों को पकड़ना जिन्हें कानूनी रूप से पकड़ने के लिए अधिकृत किया गया है और जिनके खिलाफ पर्याप्त आशंका मौजूद है।

2.6.2 jk"Vh; ifyl vk;kx dk pkVj

एनपीसी द्वारा पेश किया चार्टर[52], 1861 के चार्टर के परे जाकर इस बात पर ज़ोर देता है की संविधान, कानून और लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं की आवश्यकताओं के अनुसार ही पुलिस के सर्वोच्च दायित्व और कर्तव्य है। इसके लिए पुलिस को पेशेवर, सेवा–उन्मुख, किसी भी प्रभाव से मुक्त होना चाहिए और साथ ही लोगों के लिए उत्तरदायी भी होना चाहिए। एनपीसी ने अपने मॉडल में एक विस्तृत चार्टर निर्धारित किया है।

2.6.3 lkjkcth deVh dh flQkfj'k

2006 में, एनपीसी के विधेयक पर निर्भर सोली सोराबजी कमेटी ने पुलिस चार्टर को दो श्रेणियों में विभाजित किया – सामान्य कर्तव्यों और सामाजिक जिम्मेदारियां। उच्च न्यायलय के 22 सितम्बर, 2006 के निर्णय के बाद राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए ज़्यादातर पुलिस अधिनियम सोली सरबजी कमेटी द्वारा प्रभावित है।

सोराबजी कमेटी के मॉडल के अनुसार, पुलिस की भूमिका और कार्य व्यापक रूप से निम्नलिखित होंगेः 1. कानून को निष्पक्ष रूप से बनाए रखने और लागू करना और नागरिकों की जिंदगी, स्वतंत्रता, संपत्ति, मानवाधिकार और गरिमा की रक्षा करना

2. सार्वजनिक व्यवस्था को बढ़ावा देना और संरक्षित करना
3. आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना

---

51 धारा 34, हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007

52 राष्ट्रीय पुलिस आयोग, आठ और निष्कर्ष रिपोर्ट, मई 1981

4. सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करना
5. अपराधों को रोकना
6. सभी शिकायतों को सटीक रूप से पंजीकृत करने के लिए और तत्काल अनुवर्ती कार्रवाई करना
7. अपराधियों को पकड़ने के लिए, और अपराधियों के अभियोजन पक्ष में आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए सभी संज्ञेय अपराधों की पंजीकरण और जांच करना
8. समुदाय में सुरक्षा की भावना सृजत करना और बनाए रखना
9. प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं से उत्पन्न होने वाली स्थितियों में लोगों को सभी संभव सहायता प्रदान करना
10. संकट की परिस्थितियों में लोगों को आवश्यक सहायता प्रदान करना और राहत प्रदान करना
11. लोगों और वाहनों के आवागमन को सुविधाजनक बनाने और सड़कों और राजमार्गों पर यातायात को नियंत्रित करना
12. सार्वजनिक शांति को प्रभावित करने वाले मामलों से संबंधित खुफिया जानकारी एकत्र करना और सभी संबंधित एजेंसियों को इसके द्वारा वितरित करना
13. सभी अनाधिकृत संपत्ति का प्रभार लेना और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपनी सुरक्षित हिरासत में लेने और निपटान के लिए कार्रवाई करना

सोराबजी कमेटी के मॉडल पुलिस अधिनियम, 2006 में निर्धारित पुलिस की अधिकांश सामाजिक ज़िम्मेदारियां देश में पुलिस के लिए निर्धारित आचरण संहिता और व्यवहार संहिता में दी गई हैं।

2.6.4 ifyl dh fy, vkpkj lfgrk

देश में पुलिस के लिए आचरण संहिता 1960 में पुलिस महानिरीक्षक के सम्मेलन में अपनाई गई थी। इसे बाद में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया और सभी राज्य सरकारों को प्रसारित किया गया। सरकार द्वारा अनुमोदित यह कोड, नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

1. पुलिस को भारत के संविधान के प्रति वफादार और निष्ठावान होना चाहिए और इसके द्वारा गारंटीकृत नागरिकों के अधिकारों का सम्मान और समर्थन करना चाहिए।
2. पुलिस को लागू कानून के औचित्य या आवश्यकता पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। उन्हें डर या पक्षपात, दुर्भाव या निंदा के बिना दृढ़ता से और निष्पक्षता से कानून लागू करना चाहिए।
3. पुलिस को अपनी शक्तियों और कार्यों की सीमाओं को पहचानना और उनका सम्मान करना चाहिए। उन्हें न्यायपालिका के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और फैसले के अनुसार अपराधी को दण्डित करने में फैसले का सहयोग करना चाहिए।
4. कानून के पालन को बनाए रखने या आदेश को बनाए रखने में, पुलिस को यथासंभव व्यावहारिक होना चाहिए, दृढ़ता, सलाह और चेतावनी के तरीकों का उपयोग करना चाहिए। जब बल का उपयोग अपरिहार्य हो जाता है, तो इन परिस्थितियों में केवल आवश्यक न्यूनतम बल का उपयोग किया जाना चाहिए।

5. पुलिस का मुख्य कर्तव्य अपराध और अव्यवस्था को रोकना है और पुलिस को यह समझना चाहिए कि दोनों का न होना ही उनकी दक्षता का परीक्षण है न कि उसने निपटने के लिए दिखने वाला पुलिस बल।

6. पुलिस को यह समझना चाहिए कि वे जनता के सदस्य हैं, केवल एक ही अंतर के साथ कि समाज के हित में और उनकी ओर से वे उन कर्तव्यों पर पूर्णकालिक ध्यान देने के लिए ही उन्हे नियोजित किया गया हैं ।

7. पुलिस को यह महसूस करना चाहिए कि उनके कर्तव्यों का कुशल प्रदर्शन जनता से प्राप्त होने वाले सहयोग पर निर्भर करेगा। इसके बदले में, उनके आचरण और कार्यों की सार्वजनिक स्वीकृति को सुरक्षित करने और सार्वजनिक सम्मान और आत्मविश्वास को बनाने और उसे बनाए रखने की उनकी क्षमता पर निर्भर करेगा।

8. पुलिस को हमेशा लोगों के कल्याण को ध्यान में रखना चाहिए और उनके प्रति सह. ानुभूतिपूर्ण और विचारशील होना चाहिए। उन्हें हमेशा व्यक्तिगत सेवा और दोस्ती देने के लिए तैयार रहना चाहिए और उनकी संपत्ति और / या उनकी सामाजिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना सभी को आवश्यक सहायता प्रदान करना चाहिए।

9. पुलिस को हमेशा स्वयं से पहले कर्तव्य रखना चाहिए, खतरे, घृणा या उपहास के रूप में शांत रहना चाहिए और दूसरों की सुरक्षा में अपने जीवन के बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए।

10. पुलिस हमेशा विनम्र और शिष्ट होना चाहिए; भरोसेमंद और निष्पक्ष; गरिमा और साहस उनके गुण है; और लोगों के विश्वास को जीतना चाहिए।

11. उच्चतम ईमानदारी पुलिस की प्रतिष्ठा का मौलिक आधार है। इसे पहचानते हुए, पुलिस को अपने निजी जीवन को सावधानी से स्वच्छ रखना चाहिए, आत्म–संयम विकसित करना और व्यक्तिगत और आधिकारिक जीवन दोनों में विचार और कार्य में सच्चे और ईमानदार होना चाहिए, ताकि जनता उन्हें अनुकरणीय नागरिक मान सके।

12. पुलिस को यह समझना चाहिए कि राज्य के लिए उनकी पूर्ण उपयोगिता केवल उच्च स्तर के अनुशासन को बनाकर रखने, कानून के अनुसार कर्तव्यों का वफादार प्रदर्शन और कमांडिंग रैंकों के वैध निर्देशों और बल के प्रति पूर्ण वफादारी, पूर्ण आज्ञाकारिता, निरंतर प्रशिक्षण और तैयारी की स्थिति में खुद को रखकर ही सुनिश्चित किया जा सकता है।

13. धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक राज्य के सदस्यों के रूप में पुलिस को व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से ऊपर उठने और धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या वर्गीय विविधताओं से परे भारत के सभी लोगों के बीच समान भाईचारे के सद्भाव और भावना को बढ़ावा देने और महिलाओं की गरिमा और समाज के वंचित खण्डों के प्रति हो रही लगातार अपमानजनक प्रथाओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए।

2.6.5 iqfyl vfèkdkfj;ksa ds fy, O;ogkj lafgrk

एनपीसी ने महसूस किया कि, आचार संहिता के अलावा जो पूरी तरह से पुलिस संगठन के लिए लागू होगी, नियमों का एक समूह होना चाहिए जो संगठन के व्यक्तिगत सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करेगा। सरकार द्वारा अनुमोदित और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रसारित, व्यवहार संहिता नीचे संक्षेप में दी गई हैः

1- dr0; dh mi{kk

आवश्यक और पर्याप्त कारण के बिना कोई पुलिस अधिकारी :

(ए) उचित दृढ़ता और परिश्रम के साथ अपने कर्तव्यों में भाग लेने या निष्पादित करने की उपेक्षा नहीं कर सकता या छोड़ नहीं सकता

(बी) आदेशों के अनुसार अपनी बीट या इलाके का काम करने में विफल रह सकता है, या उस कर्तव्य की जगह छोड़ सकता है जिसका उसे आदेश दिया गया है, या

(सी) छुट्टी लिए बिना अनुपस्थित रहें या किसी भी कर्तव्य के लिए देर से पहुंचे, या

(डी) अपने कार्य के दौरान प्राप्त किसी भी धन या संपत्ति के लिए उचित विवरण देने में असमर्थ रह सकता है

2- vkns'kk dh voKk

कोई पुलिस अधिकारी, बिना किसी आवश्यक और पर्याप्त कारण के, किसी भी वैध आदेश या पुलिस विनियमों के किसी भी प्रावधान की अवज्ञा या उसे अस्वीकार नही कर सकता।

3- vLohdk;l vkpj.k

किसी भी पुलिस अधिकारी को ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जो अनुशासन के प्रतिकूल हो और उससे पुलिस फ़ोर्स की प्रतिष्ठा में कमी आए।

4- ,d iqfyl cy dk fdlh vU; lnL; ds lkFk n0;ogkj ugh djuk pkfg,

एक पुलिस अधिकारी को किसी पुलिस बल के सदस्य के प्रति दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसे

(ए) दमनकारी या अपमानजनक व्यवहार, या

(बी) उसके साथ हमला या दुर्व्यवहार ।

5- >B ;k iokxg

किसी भी पुलिस अधिकारी को ऐसा नहीं करना चाहिए:

(क) जानबूझकर या गैर–ज़िम्मेदारी से किसी भी पुलिस रिकॉर्ड में किसी भी झूठी, भ्रामक या गलत मौखिक या लिखित बयान या प्रवेश करना, या

(ख) जानबूझकर या उचित प्राधिकारी की कमी या उचित देखभाल की कमी की वजह से किसी भी पुलिस रिकॉर्ड या दस्तावेज को नष्ट करना, या

(ग) आवश्यक और पर्याप्त कारण के बिना रिकॉर्ड या दस्तावेज में किसी भी प्रविष्टि को बदलना या मिटाना, या

(घ) जानबूझकर या गलती से पुलिस बल में नियुक्ति के संबंध में कोई झूठा, भ्रामक या गलत बयान देना या शामिल करना ।

6- Hk"V ;k vuqfpr vH;kl

किसी भी पुलिस अधिकारी को ऐसा नहीं करना चाहिए–

(क) बल के सदस्य के रूप में अपनी ड्यूटी में, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, किसी भी ग्रैच्युइटी, तोहफे या सदस्यता की प्राप्ति, या

(ख) स्वयं को किसी व्यक्ति के सामने किसी आर्थिक दायित्व के तहत पेश करना जिससे स्वयं के कर्तव्य में कोई बाधा उत्पन्न हो

(ग) अपने निजी लाभ के लिए बल के सदस्य के रूप में अपनी स्थिति का अनुचित रूप से उपयोग, या उपयोग करने का प्रयास, या

(डी) किसी भी व्यक्ति के लिए रोजगार प्राप्त या किसी भी प्रकार के लाइसेंस के अनुदान के लिए आवेदन करने के उद्देश्य से हस्ताक्षर या अन्य सिफारिशों का एक प्रशंसापत्र लिखना या देना

7- vfèkdkj dk n#i;ksx

(i) एक पुलिस अधिकारी अधिकार का दुरुपयोग करता हुआ माना जाएगा यदि वहः

(क) बिना आवश्यकता और पर्याप्त कारण के गिरफ्तारी करता है, या

(ख) किसी भी कैदी या अन्य व्यक्ति की ओर किसी भी अनावश्यक हिंसा का उपयोग करता है, या

(ग) जनता के किसी भी सदस्य के लिए असभ्य है।

(ii) किसी भी पुलिस अधिकारी को उपरोक्त के रूप में अधिकार का दुरूपयोग नहीं करना चाहिए।

8- LokLF; dh mis{kk

किसी भी पुलिस अधिकारी को अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, या बीमारी के कारण कर्तव्य से अनुपस्थित होने पर, कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए की कर्तव्य पर लौटने में बाधा हो।

9- vuqfpr vkj eSyh iks'kkd

किसी भी पुलिस अधिकारी को कर्तव्य पर, या कर्तव्य के दौरान, लेकिन सार्वजनिक स्थान पर वर्दी पहने हुए, अनुचित रूप से तैयार या मैली पोशाक या अव्यवस्थित नहीं होना चाहिए।

10- u'kk@'kjkc

किसी भी पुलिस अधिकारी को ड्यूटी के समय नशे की स्थिति में नहीं होना चाहिए जो उसे कर्तव्यों के लिए अनुपयुक्त बनाता है।

11- vuq'kklukRed vijkèk ds fy, lgk;d

किसी भी पुलिस अधिकारी को अनुशासनात्मक अपराध के लिए सहायक नहीं होना चाहिए या जानबूझकर अनुशासन के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए सहायक नहीं बनना चाहिए।

12- cy dh ,drk dk uqdlku

कोई पुलिस अधिकारी ऐसी भूल–चूक नहीं करेगा जो पुलिस बल में भेदभाव करने या उत्पन्न करने की संभावना बनाता है या ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिसमें कि पुलिस की निष्पक्ष और प्रभावी छवि पर कोई दाग लगे।

13- jk"Vª fojksèkh vkpj.k

कोई पुलिस अधिकारी ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो देश की सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करता है या कम करता है या देश के प्रतिष्ठा को कम करने की संभावना उत्पन्न करता है।

2.7 Hkrê

किसी भी संगठन की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है इसकी जनशक्ति। अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में संगठन की सफलता अंततः कर्मियों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है जो इसमें कार्यरत हैं। यह सभी संगठनों के लिए सच है, लेकिन पुलिस जैसे संगठन में अधिक है, जहां सेवा की शर्तें और नौकरी की आवश्यकताएं बेहद सटीक और विशिष्ट हैं।

भारत में पुलिस, जनशक्ति के सबसे बड़े नियोक्ता में से एक है। 1 जनवरी 2016 को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस बलों की स्वीकृत संख्या लगभग 24.64 लाख थी, जबकि उस तारीख को सात सीएपीएफ (असम राइफल्स, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी, और एसएसबी) की संयुक्त स्वीकृत संख्या थी 10. 78 लाख , राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस की कुल स्वीकृत शक्ति और केंद्र के तहत सशस्त्र पुलिस बल लगभग 3.6 मिलियन है। जनशक्ति का यह विशाल भंडार समाज के लिए बहुत अच्छा कर सकता है अगर उनकी भर्ती, प्रशिक्षण, नेतृत्व और उपयोग अच्छी तरह से किया जाता है।

राज्य पुलिस की सीधी भर्ती आम तौर पर तीन स्तरों पर की जाती है– कांस्टेबल, सब–इंस्पेक्टर और पुलिस उपायुक्त। सहायक पुलिस अधीक्षक के स्तर पर आईपीएस की भर्ती की जाती है। जबकि पहले तीन रैंकों की भर्ती राज्य स्तर पर की जाती है, आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय स्तर पर भर्ती किया जाता है।

यहां तक कि एक ही राज्य में, किसी विशेष रैंक की भर्ती के लिए निर्धारित आवश्यकताओं में भिन्नताएं हैं। कभी–कभी, सिविल पुलिस में किसी विशेष रैंक की भर्ती के मानकों को सशस्त्र पुलिस के लिए निर्धारित मानक से अलग रखते हैं। महिला उम्मीदवारों की भर्ती के लिए निर्धारित मानक पुरुष उम्मीदवारों के लिए निर्धारित मानक से स्पष्ट रूप से अलग हैं। सभी राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए नियम कम कठिन हैं। पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित लोगों के लिए लम्बाई में छूट उपलब्ध है।

सभी राज्यों में अनुसूचित जातियों, पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जनजातियों जैसे विभिन्न श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए पदों का आरक्षण भी है। कुछ राज्य स्वतंत्रता सेनानियों, पूर्व सैनिकों, होम गार्ड, खिलाड़ियों और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए रिक्तियों का एक निश्चित प्रतिशत भी आरक्षित करते हैं।

निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गई है की सिविल पुलिस के लिए सामान्य श्रेणी पुरुष उम्मीदवारों की भर्ती के लिए पात्रता और चयन की शर्तें हैं।

2.7.1 dkLVscy dh Hkrê

सबसे निचली रैंक कांस्टेबल है, इस रैंक की पूरी सीधी भर्ती की जाती है। जहां तक अन्य रैंकों का संबंध है, रिक्तियों को प्रत्यक्ष भर्ती, पदोन्नति और स्थानांतरण से भरा जाता है। सबसे बड़ी भर्ती कांस्टेबल के स्तर पर होती है। इस रैंक की भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता / मानकों के बारे में डेटा और चयन के लिए प्रक्रिया निम्नलिखित तालिका में संक्षेप में दी गई है:

rkfydk 13% dkLVcy Hkrê dh fy, jkT;okj vko';drk,a

jkT;	vk;q	f'k{kk	'kkjhfjd fLFkfr		Hkrê dh çfØ;k	p;u lfefr
	lky e		mpkÂ	lhuk		
असम	18-25	HSLC/Cl 10	162.56	80-85 cm	PM; PET & WT	DSC
आंध्र प्रदेश		10+2	167.6	86.3-91.3	PM;PET &WT	SPRB
अरुणाचंल		Class X	5'5"	31-33"		DSC
बिहार	18-23	10+2	165 cm	81-86 cm	WT &PET	DSC
छत्तीसगढ़	18-28	10+2	168 cm	81-86 cm	PET & WT	DSC
गोवा	18-22	Hig. Sec.	168 cm	80-85 cm	PET; WT& Interview	DSC
गुजरात	18-28	12th+Comp. Knowledge			PET & WT	
हरियाणा	18-25	12 class	5'7"	33-34.5"	PM;PET;WT	H P R Board
हिमाचल प्रदेश	18-23	10+2	5' 6"	31-32"	PM;PET,WT& Pers. Test	D R B
जम्मू और कश्मीर	18-23	Matric	5' 6"	33- 33.5"	-------	----------
झारखण्ड						
कर्नाटक	19-25	12thstan-dard	168 cms		PM; PET; WT ------	DSC
केरल	18-25	SSLC	167 cms	81-86 cms	PM;PET;WT	K P S C
मध्य प्रदेश	18-25	10th class	168 cms	81-86	WT & then PET	MPPEB
महाराष्ट्र	18-25	XII th Stan-dard	165 cms	79-84 cms	PET: WT; Interview	
मनिपुर	18-23	Matric	5'.3"	31-33"	PM; PET; WT; Interview.	Class III Rect. Board
मेधालय	18-21	HSLC	162 cms	76-81 cms	PM. PET;WT;Pers. Test	DSC
मिजोरम		High School				
नागालैंड	18-30	Class VIII	5' 5"	78-83 cms	PET; WT	D RB
ओडीशा	18-23	Hih. Secy.	168 cms	79-84 cms	PM; WT	D S B
पंजाब	18-22	10+2	5'7"	33-34.5	PM; PET; WT & Interview	Rect. Board
राजस्थान	18-23	10th	168 cms	81-86 cms	WT;PM;PET	D R B
सिक्किम	18-22	10th	5'3"	32-34"	P M; PET; WT	D R B
तमिलनाडू	18-24	10th	168 cms	81-86 cms`	WT; PET	T U S RB
त्रिपुरा	18-22	8th class	167.64 cms	74-78 cms	PM; PET; WT; Interview.	D S C
उत्तर प्रदेश	18-22	12th class	168 cms	79-84 cms	PM ;WT; PET	UP P R & P Board
उत्तराखण्ड	18-22	High School	165 cms	78.8-83.8 cms	PM.;PET;WT; Interview	D RB
पश्चिम बंगाल	18-27	Madhyamik Exam.	167 cms	78-83 cms	PM.; PET; WT; Interview	W.B. P RB
दिल्ली	18-21	10+2	170 cms	81-85 cms	PM; PET' WT; Interview	DSB

Abbreviations:
cm-centimetres (सी.एम.–सेंटीमीटर)
PM-Physical measurements (पी.एम.–फिज़ीकल मेज़रमेंट)
PET-Physical efficiency/ endurance test (पी.ई.टी.–फिज़ीकल ऐफिशिएंसी/एंड्यूरेंस टेस्ट)
WT-Written test (डब्ल्यू.टी.–रिटन टैस्ट)
Pers. test-Personality test (पर्स टैस्ट–पर्सनेलिटी टेस्ट)
DSC/DRB-District Selection Committee/ District Recruitment Board (डी.एस.सी./डी.आर.बी.–डिस्ट्रिक्ट सलेक्शन कमेटी/डिस्ट्रिक्ट रिकरूटमेंट बोर्ड)
SPRB-State Police Recruitment Board (एस.पी.आर.बी.–स्टेट पुलिस रिकरूटमेंट बोर्ड)
HPRB-Haryana Police Recruitment Board (एच.पी.आर.बी.– हरियाणा पुलिस रिकरूटमेंट बोर्ड)
KPSC-Kerala Public Service Commission (के.पी.एस.सी.–केरेला पब्लिक सर्विस कमीशन)
MPPEB-Madhya Pradesh Professional Examination Board (एम.पी.पी.ई.बी.–मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड)
TUSRB-Tamil Nadu Uniformed Services Recruitment Board (टी.यू.एस.आर.बी.–तमिलनरडु यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज़ रिकरूटमेंट बोर्ड)
UPPR&PB-Uttar Pradesh Police Recruitment & Promotion Board (यू.पी.पी. एण्ड पी.बी.–उत्तर प्रदेश पुलिस रिकरूटमेंट एण्ड प्रमोशन बोर्ड)
WBPRB-West Bengal Police Recruitment Board (डब्ल्यू.बी.पी.आर.बी.–वेस्ट बेंगाल पुलिस रिकरूटमेंट बोर्ड)

अधिकांश राज्यों ने न्यूनतम माध्यमिक (कक्षा 12) को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के रूप में निर्धारित किया है, हालांकि कुछ राज्यों में, न्यूनतम कक्षा 10 या कक्षा 8 भी है। गुजरात जैसे राज्यों में कक्षा 12 योग्यता के अलावा, कॉन्स्टेबलों के पास कंप्यूटर पर काम करने की योग्यता की भी आवश्यकता है।

एनपीसी की सलाह है कि एक कॉन्स्टेबल की भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 17 वर्ष और अधिकतम 21 वर्ष होनी चाहिए। अधिकांश राज्यों में न्यूनतम आयु अब 18 वर्ष है और सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 21 से 30 वर्ष तक है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को पांच साल तक की छूट दी जाती है।

भर्ती के लिए निर्धारित भौतिक मानकों में भिन्नताएं हैं। कॉन्स्टेबल के लिए, विभिन्न राज्यों में निर्धारित न्यूनतम ऊंचाई सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 162 सेमी से 168 सेमी तक होती है, जिसमें पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों के व्यक्तियों के लिए 2 सेमी की छूट होती है। अधिकांश राज्यों ने न्यूनतम मानक के रूप में 168 सेमी अपनाया गया है।

डिफ्लेटेड छाती माप 76 से 86.3 सेमी तक भिन्न होता है। अधिकांश राज्यों में विस्तारित मानक 5 सेमी है। अधिकांश राज्यों में 81 सेमी डिफलेटेड और 86 सेमी विस्तारित मानक स्वीकार किये जाते हैं।

उम्मीदवारों की पहली बार जांच की जाती है और जो लोग आयु और शारीरिक माप की निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करते हैं उनकी शारीरिक सहनशक्ति परीक्षण किया जाता है ताकि उनकी सहनशक्ति और ताकत का आकलन किया जा सके। कुछ राज्यों में, वे राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता परीक्षण के एक–सितारा मानक के अधीन हैं। सभी राज्यों ने 1500– या 1600 मीटर दौड़ जैसी क्रियाओं के आधार पर अपने भौतिक दक्षता परीक्षण तैयार किए हैं; 100– या 500 मीटर की दौड़, शॉट पुट, पुश अप, लंबी कूद और उच्च कूद। दूरी / समय मानकों को निर्धारित किया जाता है और जो योग्य हैं वे लिखित परीक्षा के लिए आगे जाते हैं। चयन अंततः उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर किया जाता है।

कॉन्सटेबल की भर्ती आमतौर पर जिला / बटालियन आधार पर की जाती है। ज्यादातर मामलों में, यह जिला चयन बोर्ड द्वारा जिला एसपी या सशस्त्र पुलिस

बटालियन के कमांडेंट की अध्यक्षता में किया जाता है। केरल में, राज्य लोक सेवा आयोग भी कॉन्स्टेबल के लिए भर्ती अभ्यास में शामिल है। कुछ राज्यों ने कॉन्स्टेबल समेत पुलिस विभाग में भर्ती के संचालन या पर्यवेक्षण के लिए पेशेवर निकाय स्थापित किए हैं। आंध्र प्रदेश राज्य पुलिस भर्ती बोर्ड, हरियाणा पुलिस भर्ती बोर्ड, मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड, तमिलनाडु यूनिफार्म सेवा भर्ती बोर्ड, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और संवर्धन बोर्ड और पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड कुछ उदाहरण हैं।

2.7.2 ifyl d lc&bLiDVjk dh HkrÊ

पुलिस उपक्रम में सब–इंस्पेक्टर सबसे महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं में से एक है। यह अनिवार्य रूप से दो कारणों से है। एक, इस रैंक के अधिकारी पर ज्यादातर मामलों में एक पुलिस स्टेशन का प्रभार होता है। दो, इस स्तर पर महत्वपूर्ण मामलों का सबसे अधिक जांच कार्य किया जाता है।

पुलिस के सब–इंस्पेक्टर पद की भर्ती के लिए निर्धारित पात्रता और अन्य शर्तों को संक्षेप में सारांशित किया गया है।

rkfydk 14% lc&bLiDVj d in dh HkrÊ d fy, jkT;okj vko';drk,

jkT;	vk;q	f'k{kk	'kkjhfjd fLFkfr		HkrÊ dh çfØ;k	p;u lfefr
	lky e		mpkÃ	lhuk		
आंध्र प्रदेश		स्नातक	167.6 cms	86.3-91.3	पीएम पीटी डव्ल्यूटी	State Police Rect. Board
असम	20-24	स्नातक	5’ 3”	78.5-83.5	डव्ल्यूटी और पीइटी	चयन समिति
अरुणाचंल प्रदेश	20-25	स्नातक	165 cms	79-84 cms	पीएम पीटी डव्ल्यूटी, साक्षात्कार	-------------
बिहार	21-37	स्नातक	165 cm	81-86 cm	पीइटी और डव्ल्यूटी	बिहार कर्मचारी चयन समिति
छत्तीसगण	18-28	स्नातक	168 cms	81-86	डव्ल्यूटी, पीइटी, साक्षात्कार	चयन समिति
गोवा	20-25	स्नातक	171 cms	80-85	पीएम पीटी डव्ल्यूटी, साक्षात्कार	--------
गुजरात	21-30	स्नातक और संगणक	165	84-89	पीइटी और डव्ल्यूटी, साक्षात्कार	जीपीएससी
हरियाणा	22-28	स्नातक	5’8”	---	पीएम, पीइटी, डब्ल्यू	एचपीआरबी
हिमाचल प्रदेश	-----	स्नातक	------	-------------	पीएम, ,डब्ल्यू, पीइटी	एचपी पुलिस रेजी. समिति
जम्मू और कश्मीर	18-25	स्नातक	5’6”	33”-33.5”	पीएम, पीइटी, डब्ल्यू, टेस्ट	चयन समिती
झारखण्ड	18-28	स्नातक			पीएम पीटी डव्ल्यूटी, साक्षात्कार	

कर्नाटक	21-26	स्नातक	168 cms	81-85 cms	पीएम पीटी डव्ल्यूटी, साक्षात्कार	राज्य कर्मचारी सेवा समिति
केरल	20-30	स्नातक	167 cms	81-86 cms	पीएम डव्ल्यूटी, पीटी	केपीएससी
एमपी	18-28	स्नातक	167.5 cms	81-86	पीएम डव्ल्यूटी, पीइटी साक्षात्कार	एमपीपीइबी
महाराष्ट्र	19-28	स्नातक	167.6 cms	81-86	डव्ल्यूटी, पीइटी साक्षात्कार	एमपीएससी
मनिपुर	18-25	स्नातक	5' 3"	31-33"	पीएम पीटी डव्ल्यूटी, साक्षात्कार	चयन समिति
मेधालय	20-27	स्नातक	162 cms	76-81	पीएम, पीइटी, डव्ल्यूटी, साक्षात्कार	केन्द्रीय चयन समिति
मिजोरम	------	----------	--------	----------	----------	----------
नागालैंड						
ओडिसा	20-25	स्नातक	168	79-84	प्रारम्भिक, डव्ल्यूटी, पीइटी, मुख्य डव्ल्यूटी, साक्षात्कार	ओडिसा कर्मचारी चयन समिति
पंजाब	18-25	स्नातक	5' 7"	33-34"	पीएम, पीइटी, डव्ल्यूटी, साक्षात्कार	चयन समिति
राजस्थान	20-25	स्नातक	168 cms	81-86 cms	डव्ल्यूटी, पीइटी	राजस्थान कर्मचारी चयन समिति
सिक्किम	18-25	स्नातक	5' 3"	32-34"	प्रारम्भिक, डव्ल्यूटी, पीइटी, मुख्य डव्ल्यूटी, साक्षात्कार	सिक्किम कर्मचारी चयन समिति
तमिलनाडू	20-28	स्नातक	168 cms	81-86 cms	डव्ल्यूटी, पीइटी	टीयूएसआरबी
त्रिपुरा	21-27	स्नातक	167.64 cms	78.74-83.82 cms	पीएम, पीइटी(वन स्टार स्टैन्डर्ड) डव्ल्यूटी, निजी टेस्ट	टीपीएससी
यूपी	18-25	स्नातक	168 cms	79-84 cms	पीइटी ,डव्ल्यूटी, साक्षात्कार	यूपीपीआर और पीबी
उत्तराखण्ड	21-27	स्नातक	167.7 cms	78.8-83.8 cms	पीएम, पीइटी , डव्ल्यूटी	--------
पश्चिम बंगाल	20-27	स्नातक	167 cms	79-84 cms	डव्ल्यूटी, साक्षात्कार	डव्ल्यू.बी. पी आरबी

सब–इंस्पेक्टरों की भर्ती से संबंधित तीन मुख्य बिंदु हैं जिन पर जोर देने की आवश्यकता है। सबसे पहले, यह केंद्रीय रूप से किया जाता है, जबकि कॉन्सटेबल्स की भर्ती इकाई या जिला आधारित होती है। दूसरा, ज्यादातर राज्यों में, उप–निरीक्षकों को राज्य लोक सेवा आयोग या ऐसी भर्ती के लिए स्थापित इसी तरह के निकाय की देखरेख में भर्ती किया जाता है, जो कि जिला चयन बोर्ड द्वारा की जाने वाली कॉन्स्टेबल की भर्ती के विपरीत होती है, जिसे जिला चयन बोर्ड द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में किया जाता है। तीसरा, सभी राज्यों में, उप–निरीक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता

स्नातक है। जबकि भौतिक माप और धीरज परीक्षण मानक लगभग एक जैसे हैं, उच्च शैक्षणिक मानकों पर महत्वपूर्ण जोर दिया गया है।

यह इस पोस्ट से जुड़े उच्च जिम्मेदारियों के कारण समझा जा सकता है। सब–इंस्पेक्टरों के लिए निर्धारित लिखित परीक्षा आम तौर पर निबंध लेखन, सामान्य ज्ञान, अंकगणित, वर्तमान मामलों और इतिहास में उम्मीदवारों की जांच करती है। कुछ राज्यों में, उम्मीदवारों को स्क्रीन करने के लिए प्रारंभिक आब्जेक्टिव लिखित परीक्षा आयोजित की जाती है। ज्यादातर राज्यों में, लिखित परीक्षा के बाद एक साक्षात्कार किया जाता है।

2.7.3 ifyl d mi vèkh{kd dh Hkrê

उप पुलिस अधीक्षक का पद राज्य पुलिस सेवा से संबंधित है। इस रैंक की भर्ती राज्य सरकारों द्वारा तैयार नियमों द्वारा की जाती है। हमने असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु के पांच राज्य शासकों द्वारा बनाए गए नियमों का अध्ययन किया है।

मामूली अंतर को छोड़कर, अलग–अलग राज्यों में नियम लगभग सामान ही हैं। वे भर्ती के दो तरीकों को प्रयोग करते हैं – प्रतिस्पर्धी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती या इंस्पेक्टर के पद से पदोन्नति। ज्यादातर राज्यों में, 50ः रिक्तियों को सीधी भर्ती से और 50ः पदोन्नति द्वारा भर जाती है। गुजरात जैसे कुछ राज्य क्रमशः सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए रिक्तियों को 1ः 2 के अनुपात में विभाजित करते हैं।

सीधी भर्ती के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री है। सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा में भिन्नता है। उदाहरण के लिए, असम में 21–25 साल है,

गुजरात में 21–28 साल, मध्य प्रदेश में 20–25 साल, ओडिशा में 21–32 साल और तमिलनाडु में 21–30 वर्ष। निर्धारित न्यूनतम लम्बाई 165 सेमी और 168 सेमी के बीच है और छाती माप के लिए अधिकांश राज्यों ने 81–85 सेमी माप को निर्धारित किया है।

राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती की जाती है। कई राज्यों में, उम्मीदवारों को छांटने के लिए एक प्रारंभिक परीक्षण आयोजित की जाती है। केवल वे लोग जो प्रारंभिक परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं उन्हें अंतिम परीक्षा के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी जाती है। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार में बुलाया जाता है। आयोग प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता के क्रम में उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करता है और इसे सरकार को भेजता है।

पदोन्नति द्वारा भर्ती उन्ही इंस्पेक्टर की होती है जिनका कार्यकाल 5 से 8 वर्ष के बीच में है, इसका चयन एक कमिटी द्वारा किया जाता है जिसका अध्यक्ष राज्य लोक सेवा संघ का अध्यक्ष या सदस्य होता है और होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और आईजीपी सदस्य होते हैं । उपयुक्त अधिकारियों की सूची सरकार द्वारा चरित्र रोल, व्यक्तिगत फाइलों और अन्य प्रासंगिक विवरणों के साथ आयोग को भेजी जाती है। उन अधिकारियों के नाम जिन्हें आयोग पदोन्नति के लिए उपयुक्त मानता है, सरकार को वापस कर दिया जाता है।

2.7.4 Hkkjrh; ifyl lsok ¼vkÃih,l½ dh Hkrê

भारतीय पुलिस सेवा की नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति, दोनों तरीकों से की जाती है। नियुक्तियों के दो तिहाई सीधी भर्ती द्वारा किए जाते हैं जबकि एक तिहाई राज्य पुलिस सेवा कैडर के अधिकारियों के पदोन्नति के माध्यम से किया जाता है।

निम्नलिखित नियम और विनियम भारतीय पुलिस सेवा में भर्ती को नियंत्रित करते हैं:

1. भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, 1954
2. भारतीय पुलिस सेवा (प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा नियुक्ति) विनियमन, 1955
3. भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955
4. भारतीय पुलिस सेवा (विशेष भर्ती) विनियम, 1957

भारतीय पुलिस सेवा के लिए सीधी भर्ती अखिल भारतीय और समूह ए केंद्रीय सेवाओं के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त परीक्षा के आधार पर की जाती है। उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए और वर्ष के अगस्त के पहले दिन 21 से 30 वर्ष की उम्र के बीच होना चाहिए जिसमें परीक्षा आयोजित की जाती है। एससी / एसटी / ओबीसी उम्मीदवारों और पूर्व सेवा– सैनिकों को ऊपरी आयु सीमा के लिए 3 से 5 साल की छूट दी जाती है।

भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री है।

सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित लम्बाई पुरुषों के लिए 165 सेमी और महिलाओं के लिए 150 सेमी है। एससी / एसटी / ओबीसी के उम्मीदवारों को लम्बाई में पांच सेमी छूट की अनुमति है। पुरुष उम्मीदवारों के लिए निर्धारित छाती माप 84 सेमी (डीफलेटिड) और 89 सेमी (विस्तारित) हैं।

सीधे भर्ती उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा तीन चरणों में किया जाता है। पहला प्रारंभिक परीक्षण है, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को छाँटा जाता है। जो लोग अर्हता प्राप्त करते हैं वे मुख्य परीक्षा में शामिल होते हैं, जो दूसरे चरण का परीक्षण है। तीसरे चरण में, सफल उम्मीदवारों को एक साक्षात्कार के दौरान व्यक्तित्व परीक्षण के माध्यम से रखा जाता है। मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर एक अंतिम सूची तैयार की जाती है।

पदोन्नति द्वारा आईपीएस को नियुक्ति अलग–अलग नियमों द्वारा शासित होती है। भारतीय पुलिस सेवा (प्रोमोशन द्वारा नियुक्ति) विनियमन, 1955 के अनुसार, अध्यक्ष या संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य की अध्यक्षता में एक समिति और मुख्य सचिव, गृह सचिव, राज्य सरकार के पुलिस महानिदेशक और भारत सरकार के दो उम्मीदवार (संयुक्त सचिव के पद से नीचे नहीं) समिति के सदस्य हैं जो सामान्य रूप से हर साल मिलते हैं और राज्य पुलिस सेवा के सदस्यों की एक सूची तैयार करते हैं जिन्हें सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त माना जाता है।

नियमों के अनुसार, समिति राज्य पुलिस सेवा के उन सदस्यों पर विचार नहीं करती है, जिन्होंने वर्ष के पहले दिन 54 वर्ष की आयु प्राप्त की है जिसके लिए चयन सूची तैयार की गई है।

चयन समिति पात्र अधिकारियों को उनके सेवा रिकॉर्ड के समग्र सापेक्ष मूल्यांकन के आधार पर "उत्कृष्ट", "बहुत अच्छी", "अच्छी" या "अनुपयुक्त" के रूप में वर्गीकृत करती है। सिफारिशें इस आकलन के आधार पर की जाती हैं और सूची सभी सरकारी अभिलेखों के साथ राज्य सरकार द्वारा कमीशन को भेजी जाती है। चयन सूची आखिरकार कमीशन द्वारा तैयार की जाती है। सेवा के लिए नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा क्रमशः राज्य पुलिस सेवा के सदस्यों के नाम चयन सूची में दिखाई देते है।

2.8 ifyl çf'k{k.k

सभी राज्यों ने सीधे भर्ती सब–इंस्पेक्टर और पुलिस उपायुक्त और उनके कांस्टेबुलरी के लिए प्रशिक्षण स्कूलों को प्रशिक्षण देने के लिए अपने स्वयं के पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज या अकादमियों की स्थापना की है।

अधिकांश केंद्रीय पुलिस संगठनों ने अपने स्वयं के प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं, जो उनके अधिकारियों के लिए बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करते हैं और उनके लिए और दूसरों के लिए रिफ्रेशर और विशेष पाठ्यक्रम भी प्रदान करते हैं। 1 जनवरी 2014 को देश में 325 पुलिस प्रशिक्षण संस्थान थे। इनमें से 225 राज्यों और केंद्र के 100 थे।

पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं:

1. नई भर्ती के लिए बुनियादी परिचय स्तर पाठ्यक्रम
2. पदोन्नत होने वाले लोगों के लिए प्री–प्रोमोशन इन–सर्विस कोर्स
3. रिफ्रेशर पाठ्यक्रम
4. विशिष्ट पाठ्यक्रम।

पुलिस कर्मियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है, जिन्होंने अपना मूल परिचय पाठ्यक्रम कर लिया है।

2.8.1 dkLVcy dk çf'k{k.k

राज्यों में कांस्टेबल के लिए बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम नौ महीने से एक वर्ष तक है। भर्ती विषयों में इनडोर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जैसेः आधुनिक भारत में पुलिस भूमिका; संगठन और प्रशासन; कानून, अपराध रोकथाम, कानून और व्यवस्था का रखरखाव; पुलिस कर्तव्य; आचार संहिता और व्यवहार; पुलिस–जनसंपर्क; मानवाधिकार; आदि। आउटडोर प्रशिक्षण देने पर काफी जोर दिया जाता हैः शारीरिक प्रशिक्षण; ड्रिल; हथियारों और विस्फोटकों का प्रबंधन; क्षेत्र कला और रणनीति; प्राथमिक चिकित्सा; दंगा नियंत्रण; यातायात नियंत्रण; निहत्थे मुकाबला; आदि बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान पढ़ाया जाता है।

बीपीआरडी द्वारा डिजाइन किए गए मॉडल पुलिस मैनुअल ने सुझाव दिया है कि सभी राज्यों में एक अतिरिक्त व्यावहारिक प्रशिक्षण मॉड्यूल पेश किया जाना चाहिए।[54] इसकी अवधि छह महीने होनी चाहिए। पहला महीना पुलिस स्टेशन के नियमित कर्तव्य सीखने के लिए, अगले दो महीने निवारक कार्य, चौथे महीने में जांच के बुनियादी कदम, और पांचवें और छठे महीने में शहरी पुलिस स्टेशन से जुड़कर वहां की पुलिसिंग समस्याओं के बारे में जानकारी लेनी चाहिए।

2.8.2 lc&bLiDVjk dk çf'k{k.k

राज्यों के पुलिस प्रशिक्षण कॉलेजों में सीधे भर्ती वाले सब–इंस्पेक्टरों का प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है। मूल पाठ्यक्रम की अवधि आम तौर पर 12 महीने होती है। पुलिस प्रशिक्षण पर गोरे कमेटी द्वारा सुझाए गए पाठ्यक्रम को अधिकांश राज्यों द्वारा अपनाया गया था। कुछ मामूली बदलावों को छोड़कर, बुनियादी पाठ्यक्रम के दौरान सिखाए गए विषयों में शामिल हैं: आधुनिक भारत और पुलिस की भूमिका; पुलिस का संगठन और प्रशासन; नेतृत्व और पर्यवेक्षण; मानव व्यवहार, पुलिस दृष्टिकोण, पुलिस छवि और पुलिस सार्वजनिक संबंध; कानून; अपराध–विज्ञान; पुलिस विज्ञान जिसमें अपराध की रोकथाम, अपराध जांच अनौपचारिक फोरेंसिक दवा और विज्ञान शामिल है; शांति का रखरखाव; यातायात नियंत्रण; सुरक्षा; और विदेशियों से संबंधित मामले। बाहरी विषयों में शारीरिक प्रशिक्षण शामिल है; ड्रिल; हथियार प्रशिक्षण; भीड़ पर नियंत्रण; ऑटोमोबाइल और ड्राइविंग के रखरखाव और तंत्र; आर/टी उपकरण का संचालन; निर्बाध मुकाबला और क्षेत्र कला और रणनीति।

सब–इंस्पेक्टर, प्रशिक्षण कॉलेज से बाहर निकलने के बाद, वे अलग–अलग रैंकों के पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों में व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए विभिन्न पुलिस इकाइयों से जुड़ते हैं। विभिन्न राज्यों में इसके लिए अवधि और प्रारूप में विविधताएं हैं। गोरे कमेटी ने बारह महीने के व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया था, जिसे बीपीआरडी द्वारा मॉडल मैनुअल.[55] में अनुशंसित किया गया था। इस व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपराध निवारण और जांच कार्य और भीड़ नियंत्रण विधियों को जानने के लिए ग्रामीण और शहरी पुलिस स्टेशनों में कार्य दिया जाता है । न्यायालय का काम जानने के लिए उन्हें अभियोजन शाखा और अंतर–जिला और अंतर–राज्य अपराध और अपराधियों से निपटने के तरीके के बारे में जानने के लिए जिला अपराध शाखा में भी लगाया जाता है। व्यावहारिक प्रशिक्षण में एक गहन अपराध वाले शहर के पुलिस स्टेशन में एक अतिरिक्त जांच अधिकारी के रूप में दो महीने के लिए एक पोस्टिंग शामिल है। इस व्यावहारिक प्रशिक्षण में एक महीने जिला एसपी के कार्यालय में उसके रीडर की तरह भेजा जाता है जिससे जिला पुलिस मुख्यालय का कार्य सीखा जा सके और उसके बाद एक महीना सशस्त्र पुलिस बटालियन के साथ संलग्न किया जाता है जिससे सशस्त्र अधिकारियों का कार्य भी सिखाया जा सके।

54 बीपीआरडी, मॉडल पुलिस मैनुअल, वॉल्यूम III, 2010, पीपी 87–88
55 बीपीआरडी, मॉडल पुलिस मैनुअल, वॉल्यूम III, 2010, पीपी 93–94

पुलिस के उप अधीक्षक के लिए बुनियादी पाठ्यक्रम में शामिल विषय लगभग समान है, कुछ विषयों पर अधिक जोर दिया जाता है और प्रबंधन और नेतृत्व के विकास पर महत्व दिया जाता है।

2.8.3 vkÃih, l vfèkdkfj;ksa dk çf'k{k.k

उत्तराखंड के मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में अन्य अखिल भारतीय और ग्रुप ए सेंट्रल सर्विसेज के अधिकारियों के साथ एक आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम करने के बाद हैदराबाद में आईपीएस में भर्ती करने वाले अधिकारियों को हैदराबाद में सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एनपीए) में प्रशिक्षित किया जाता है। आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का उद्देश्य संवैधानिक, आर्थिक और सामाजिक ढांचे को समझना है जिसमें अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवा अधिकारी कार्य करते हैं और उन्हें प्रशासन के बुनियादी सिद्धांतों, सरकारी मशीनरी आदि के कामकाज का अंदाज़ा देते हैं

इसके बाद एनपीए.[56] में 46 सप्ताह के बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसमें 3 सप्ताह के एक अध्ययन सह सांस्कृतिक दौरे और संसद अध्ययन और प्रशिक्षण ब्यूरो, सीआरपीएफ और सेना के लिए प्रत्येक 1 सप्ताह के प्रशिक्षण शामिल हैं। इसके बाद उन्हें 28 सप्ताह के राज्य / जिला व्यावहारिक प्रशिक्षण करने की आवश्यकता होती है, फिर वे छः हफ्तों के प्रशिक्षण के चरण II के लिए अकादमी में लौटते हैं, जिसमें विदेशी प्रशिक्षण के दो सप्ताह शामिल होते हैं, जिसके दौरान वे अंतरराष्ट्रीय पुलिस के प्रावधानों से अवगत होते हैं।

इनडोर प्रशिक्षण में आधुनिक भारत और पुलिस की भूमिका जैसे सामान्य प्रशासनिक स्थापना और पुलिस संगठन; प्रबंधन अवधारणा और तकनीकें; मानव व्यवहार और पुलिस दृष्टिकोण; कानून; अपराध; पुलिस साइंस; मानचित्र पढ़ना और योजना ड्राइंग; प्राथमिक चिकित्सा और एम्बुलेंस ड्रिल; मोटर परिवहन; तारारहित संपर्क; भाषाएं और ट्यूटोरियल विषय शामिल हैं। आउटडोर प्रशिक्षण में शारीरिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (जिसमें योग आसन, रॉक क्लाइंबिंग, बाधा पाठ्यक्रम, तैराकी, स्कूबा डाइविंग, नदी राफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग इत्यादि शामिल हैं); ड्रिल; हथियार प्रशिक्षण; भीड़ पर नियंत्रण; अश्वारोहण; निहत्थे मुकाबला; फील्ड कला और रणनीति; खेल और ड्राइविंग शामिल है। जंगल युद्ध में प्रशिक्षण और आतंकवाद से निपटने में, बाएं विंग चरमपंथ और हिंसा के अन्य रूप के संबंध में भी प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं।

आईपीएस अधिकारियों के लिए बेसिक ट्रेनिंग कोर्स के अलावा, अकादमी पुलिस अधीक्षक, उप महानिरीक्षक, महानिरीक्षक और भारतीय पुलिस सेवा के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस के पद के अधिकारियों के लिए अनिवार्य मध्य कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है। विदेश में दो हफ्तों सहित छह सप्ताह की अवधि का पहला कार्यक्रम जूनियर प्रशासनिक ग्रेड में पुलिस अधीक्षकों के पदोन्नति के लिए है। यह उन अधिकारियों के लिए है जो सेवा के सातवें से नौवें वर्ष में हैं। अगला चरण, उसी अवधि के (विदेश में दो सप्ताह के साथ), उप महानिरीक्षक से पुलिस महानिरीक्षक

56 यहां दिए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण 66 आरआर (2013 बैच) है

की पदोन्नति के लिए है और सेवा के चौदहवें से सोलहवें वर्ष में अधिकारियों द्वारा किया जाना है। 4 सप्ताह की अवधि (विदेश में दो सप्ताह के साथ) का अंतिम चरण सेवा के चौबीस से छत्तीस वर्ष पूरा करने वाले अधिकारियों के लिए है और 28 साल की सेवा पूरी होने पर वार्षिक वृद्धि का लाभ उठाने के लिए किया जाता है।

देश में विभिन्न पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षकों के पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण; राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों के लिए आईपीएस प्रेरण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम; अकादमी द्वारा पुलिस अधिकारियों के सभी स्तरों के लिए पेशेवर विषयों पर लघु विशेष विषयगत पाठ्यक्रम, सेमिनार और कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं।

अकादमी वरिष्ठ अधिकारियों के लिए रिफ्रेशर पाठ्यक्रम आयोजित करती है। 2014 के दौरान, 26 इन–सर्विस ट्रेनिंग कोर्स (राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर 7 सेमिनार सहित), वन्य जीवन अपराध का पता लगाने, सामुदायिक पुलिस, फोरेंसिक विज्ञान में नवाचार, महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच, साइबर अपराध जांच और मानवाधिकार और पुलिस का आयोजन किया गया। इनमें विभिन्न पुलिस संगठनों के 843 वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

2.8.4 çh&çek'ku dk l

अगले उच्च रैंक को पदोन्नति के लिए निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करना निचले रैंकों के लिए अनिवार्य है। ऐसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को प्री–प्रमोशन कोर्स कहा जाता है। इसका लक्ष्य है अगले उच्च रैंक के कर्तव्यों के लिए अधिकारियों को लैस करना है। ऐसे पाठ्यक्रमों की पाठ्यक्रम सामग्री रैंक से रैंक और कभी–कभी राज्य से राज्य में भी भिन्न होती है।

पुलिस प्रशिक्षण पर गोर कमेटी के मुताबिक, हेड कांस्टेबल को पदोन्नति के लिए इच्छुक कॉन्स्टेबल को जांच, संबंधित कानून, फोरेंसिक विज्ञान और पुलिस कार्य के निवारक पहलुओं की प्रक्रियाओं और तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। ऐसे प्री–प्रमोशन कोर्स की अवधि छह महीने होनी चाहिए। इसी प्रकार, सब–इंस्पेक्टर बनने के लिए सहायक उप–निरीक्षक बनने के लिए सहायक उप–निरीक्षक और छः से आठ सप्ताह के पाठ्यक्रम के लिए तीन महीने का कोर्स आयोजित किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में ज़ोर पर्यवेक्षण और नेतृत्व, रोकथाम और अपराध की जांच और कानून और व्यवस्था के रखरखाव पर होना चाहिए।

2.8.5 fjÝ'kj@fof'k"V ikBîØe

उपरोक्त के अलावा, मौजूदा पुलिस कर्मियों के पेशेवर कौशल को तेज करने और उनके दृष्टिकोण में आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए रिफ्रेशर पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। अवधि या इस तरह के पाठ्यक्रमों की सामग्री के बारे में कोई मानक प्रारूप नहीं है, जो अलग–अलग रैंकों के पुलिस कर्मियों के कौशल और दृष्टिकोण को पुनः पेश करने के लिए आयोजित किए जाते हैं।

विभिन्न विषयों पर आयोजित विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, पुलिस के साथ–साथ प्रबंधन, लोक प्रशासन और व्यवहार विज्ञान सहित अन्य प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित किए जाते हैं।

विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों द्वारा सम्मिलिति किए गए कुछ विषय हैं:

- अपराध जांच कौशल
- वैज्ञानिक जांच की उन्नत तकनीकें
- वीआईपी सुरक्षा
- विद्रोह / आतंकवाद से निपटना
- बम / विस्फोटक का पता लगाने और निपटान
- कम्प्यूटर अनुप्रयोग
- प्रबंधन / लोक प्रशासन
- फोरेंसिक विज्ञान
- सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी
- विशेष अपराधों से निपटना, जैसे कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ
- लिंग संवेदनशीलता
- दवाएं / नशीले पदार्थ
- प्रशिक्षको का प्रशिक्षण
- मानवाधिकार
- रेडियो वायरलेस
- यातायात नियंत्रण
- कमांडो प्रशिक्षण
- बुद्धि
- रॉक क्लाइंबिंग / पर्वतारोहण
- साइबर अपराध और उनकी जांच
- फील्ड शिल्प / रणनीति।

2.8.6 dN dæh; ifyl çf'k{k.k lLFkku

सभी केंद्रीय पुलिस संगठनों के पास अपने स्वयं के कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए मुख्य रूप से स्थापित पुलिस प्रशिक्षण संस्थान होते हैं, हालांकि वे राज्य पुलिस कर्मियों के लिए विशेष रूप से अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करते हैं। हालांकि, कुछ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा मुख्य रूप से राज्य पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए स्थापित किया गया है।

इनमें से सबसे प्रमुख केन्द्रीय जासूस प्रशिक्षण स्कूल (सीडीटीएस) पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम कर रहे हैं। वर्तमान में, कोलकाता,

हैदराबाद, चंडीगढ़, गाजियाबाद और जयपुर में स्थित पांच ऐसे स्कूल हैं। सीडीटीएस कोलकाता 1956 में स्थापित किया गया था, सीडीटीएस हैदराबाद, 1964 में, सीडीटीएस चंडीगढ़, 1975 में और अन्य दो 2012 में स्थापित किए गए थे।

ये स्कूल देश के सहायक उप–निरीक्षक के पद से लेकर डिप्टी सुपरिटेंडेंट तक को जांच प्रशिक्षण द्वारा देश की जाँच प्रक्रिया में सुधार लाना चाहते हैं। पड़ोसी विदेशी देशों के पुलिस अधिकारी पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए इन संस्थानों में आते हैं।

भोपाल में बीपीआर और डी के तहत 2013 में एक केंद्रीय एकेडमी ऑफ पुलिस ट्रेनिंग (सीएपीटी) की स्थापना राज्य के उप पुलिस अधीक्षक और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एडिशनल पुलिस अधीक्षक के पद के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए भोपाल में हुई थी। राज्य पुलिस अकादमियों के संकाय के लिए प्रशिक्षकों के पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण करना भी इस संस्थान के जनादेश का हिस्सा है। अकादमी की अध्यक्षता पुलिस महानिरीक्षक के पद के एक अधिकारी द्वारा की जाती है।

भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत एक और महत्वपूर्ण प्रशिक्षण संस्थान उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी (एनईपीए) है, जिसे 1978 में शिलांग के पास स्थापित किया गया था। यह देश में एकमात्र क्षेत्रीय पुलिस प्रशिक्षण संस्थान है, जो बुनियादी पाठ्यक्रम देश के आठ उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए भर्ती पुलिस उपायुक्त और पुलिस के सब–इंस्पेक्टरों के लिए आयोजित करता है । यह सभी राज्यों के पुलिस अधिकारियों के लिए सेवा पाठ्यक्रम, सेमिनार और कार्यशालाओं का भी आयोजन करता है।

बीपीआरडी के प्रशिक्षण निदेशालय देश में पुलिस और गैर–पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित सभी रैंकों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के लिए लंबवत बातचीत पाठ्यक्रम प्रायोजित करता है। 2014 के दौरान इस तरह के पाठ्यक्रमों के लिए चुने गए कुछ विषय में पारस्परिक प्रभावशीलता और नेतृत्व अनुभव, संचार और प्रस्तुति कौशल, प्रबंधकीय नेतृत्व और संघर्ष समाधान, नेतृत्व और परिवर्तन प्रबंधन, भावनात्मक खुफिया, ज्ञान प्रबंधन इत्यादि थे। ऐसे अधिकांश पाठ्यक्रम कम अवधि के होते हैं।

विदेशी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए हर साल वरिष्ठ पुलिस अधिकारी विदेशों में भेजे जाते हैं।

2.8.7 ifyl çf'k{k.k ij 0;;

राज्य सरकारें पुलिस प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं दे पाई हैं। कुल पुलिस व्यय को पुलिस प्रशिक्षण पर किए गए व्यय 1990–91 से 1999 –2000 के दौरान 1.09 प्रतिशत से लेकर1.41 प्रतिशत था। पिछले आठ वर्षों के दौरान स्थिति में काफी सुधार नहीं हुआ है, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में देखा जा सकता हैः

rkfydk 15 & 2009 &10 l 2016&2017 d nkjku dy ifyl 0;; d çfr'kr d :i e ifyl çf'k{k.k ij 0;; [57]

(करोड़ में)

o"k	i.k 0;; ¼djkM e½	çf'k{k.k [kpZ	i.k 0;; çfr'kr e
2009-10	41307.66	481.37	1.17
2010-11	49,576.27	708.56	1.43
2011-12	55,747.00	911.70	1.64
2012-13	58,028.05	937.61	1.62
2013-14	63,146.04	1118.23	1.77
2014-15	74,257.66	1,086.11	1.46
2015-16	83,514.21	835.49	1.00
2016-17	90,662.94	935.15	1.03

2.9 jkT;k vkj dæ 'kkflr çn'kk e ifyl 0;;

2.9.1 ifyl ij jkT; d ctV vkj 0;;

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य सरकारों के कुल बजटीय व्यय और उनकी पुलिस बलों पर खर्च किए गए पैसे के बारे में जानकारी नीचे दी गई है:[58]

rkfydk 16& o"k 2016&17 d fy, ifyl ij dy jkT; ctV vkj 0;;

(करोड़ में)

Øekd	jkT;@l?k 'kkflr çn'k	dy ctV jkT; dk	dy ctV ifyl dk	çfr'kr e¼ ifyl dk dy ctV½
1.	आंध्र प्रदेश	1,35,689.00	3,968.77	2.92%
2.	अरुणाचंल	7,617.00	510.54	6.70%
3.	असम	78,253.36	3,953.58	5.05%
4.	बिहार	1,44,696.00	5,803.36	4.01%
5.	छत्तीसगढ़	74,102.74	3,170.38	4.28%
6.	गोवा	NA	440.43	NA
7.	गुजरात	1,39,139.00	3,364.54	2.42%
8.	हरियाणा	1,13,266.31	3,838.40	3.39%
9.	हिमाचल प्रदेश	35,695.98	802.93	2.25%
10	जम्मू और कश्मीर	79,472.00	4,842.65	6.09%
11.	झारखण्ड	63,502.00	3,251.53	5.12%
12	कर्नाटक	1,63,419.00	3,979.05	2.43%

57 बीपीआर और डी द्वारा प्रकाशित विभिन्न वर्षों के लिए पुलिस संगठनों की रिपोर्ट परएनुअल डेटा से निकाली गई जानकारी
58 1 जनवरी 2017 को भारत में पुलिस संगठनों पर डेटा, प 96

13.	केरल	1,21,259.99	3,185.79	2.63%
14.	मध्य प्रदेश	1,73,668.45	5,568.50	3.21 %
15.	महाराष्ट्र	2,70,763.93	11,951.92	4.41%
16.	मनिपुर	9,709.03	1,159.03	11.94%
17.	मेधालय	NA	66.26	NA
18.	मिजोरम	8,218.65	515.77	6.28%
19.	नागालैंड	NA	1,103.53	NA
20.	ओडीशा	2,50,075.72	2,799.59	1.12%
21.	पंजाब	86,386.96	5,396.78	6.25%
22.	राजस्थान	1,74,840.00	4,506.11	2.58%
23.	सिक्किम	5,884.43	305.18	5.19%
24.	तमिलनाडू	1,79,552.05	5,484.28	3.05%
25.	तेलंगाना	NA	2,383.04	NA
26.	त्रिपुरा	15,246.52	1,080.92	7.09%
27.	उत्तर प्रदेश	NA	15,232.20	NA
28.	उत्तराखण्ड	40,422.20	1,485.44	3.67%
29.	पश्चिम बंगाल	1,60,044.59	6,376.15	3.98%
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप	4,553.74	285.21	6.26%
31.	चंडीगड़	3,596.10	379.09	10.54%
32.	दादरा और नागर हवेली	1,105.29	25.45	2.30%
33.	दमन और दीव	1,591.42	21.42	1.35%
34.	दिल्ली	NA	5,913.74	NA
35.	लक्षद्वीप	1,254.85	28.16	2.24%
36.	पुडूचेरी	6500.00	199.70	3.07%
	vf[ky Hkkjr	**25,49,526.31**	**1,13,379.42**	**4.45%**

चूंकि सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए डेटा उपलब्ध नहीं है, इसलिए राज्य बजट के प्रतिशत के रूप में पुलिस बजट का अनुमान केवल 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए किया गया है। यह आंकड़ा बताता है कि पुलिस विभागों को राज्य सरकारों से उपलब्ध संसाधनों का काफी छोटा अनुपात मिलता है। 2016–17 में पुलिस और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस के लिए औसत बजट आवंटन कुल बजट का केवल 4.44: था। यह असम, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में है, जिनमें से कुछ विद्रोह की समस्या से लड़ रहे हैं, कि पुलिस पर औसत व्यय उनके बजट का 5: से अधिक हो गया है। केंद्र शासित प्रदेशों में, चंडीगढ़ पुलिस पर व्यय अपने बजट का 11: से अधिक है।

2.9.2 ifyl 0;; e okf"kd of)

हालांकि पुलिस को कुल बजट का एक छोटा सा हिस्सा मिलता है, फिर भी राज्य पुलिस बल पर किए गए व्यय हर साल बढ़े हैं। अलग–अलग वर्षों के दौरान किए गए राज्य पुलिस व्यय के बारे में जानकारी नीचे दी गई है:

rkfydk 17& 2015&16 l jkT;ksa vkj l?k 'kkflr çn'kksa e ifyl cy ij 0;; 0;; ^å[59]

(Rs. In Crores)

o"kZ	jkT; ljdkjksa dk ifyl ij 0;;
2001-02	16,004.06
2002-03	16912.67
2003-04	18,044.22
2004-05	19,915.88
2005-06	21,070.60
2006-07	22,716.79
2007-08	26,269.09
2008-09	31,748.30
2009-10	41,307.66
2010-11	49,576. 27
2011-12	55,747.00
2012-13	58,028.05
2013-14	63,146.04
2014-15	74,257.66
2015-16	83,514.21
2016-17	90,662.94

2001–02 में 16 हजार करोड़ रुपये, पुलिस पर खर्चथा, 2016–17में रु 90 हजार करोड़ हो गया था। इस प्रकार पिछले 16 वर्षों (2001–02 से 2016–17) के दौरान, विभिन्न राज्यों में पुलिस बलों पर किए गए कुल व्यय में 466.50:की वृद्धि दर्ज की गई। यह देश में पुलिस पर कुल व्यय को प्रतिबिंबित नहीं करता है, क्योंकि इसके पुलिस संगठनों पर केंद्र सरकार के व्यय को यहां नहीं लिया गया है।[60] 2016–2017 के दौरान अकेले अपने सात सशस्त्र पुलिस बल61पर केंद्र सरकार द्वारा खर्च वास्तविक व्यय रु 51,040.00 करोड़ था। इस प्रकार भले ही अन्य केंद्रीय पुलिस संगठनों को ध्यान में रखा न जाए, 2016–17 के दौरान पुलिस पर कुल व्यय रु 141,702.94 करोड़ था।

59 बीपीआर और डी द्वारा प्रकाशित विभिन्न वर्षों के लिए पुलिस संगठनों की रिपोर्ट परएनुअल डेटा से निकाली गई जानकारी
60 1 जनवरी 2017 को भारत में पुलिस संगठनों पर डेटा, प 96

3 Hkkjr e Q,jfl d lkbl bLVhVî'kl

3.1 egRoi.k ,frgkfl d LFky

आजादी से पहले देश में कोई पूर्ण फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला मौजूद नहीं थी। ब्रिटिश शासन के दौरान अधिकांश फोरेंसिक काम आगरा, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, फिंगर प्रिंट ब्यूरो, भारत सरकार के लिए सेरोलॉजिस्ट, विस्फोटक के मुख्य निरीक्षक, भारत सरकार के केमिकल परीक्षकों की प्रयोगशालाओं में प्रश्नित दस्तावेजों के सरकारी परीक्षक और सीआईडी शाखाओं के वैज्ञानिक अनुभाग द्वारा किए जाते थे।

पहला रसायन परीक्षक प्रयोगशाला 1849 में स्वास्थ्य विभाग के तहत मद्रास प्रेसिडेंसी में स्थापित की गई थी। बाद में, कलकत्ता (1853), आगरा (1864) और बॉम्बे (1870) में इसी तरह की प्रयोगशालाएं स्थापित की गईं। 1898 में नागपुर में विस्फोटक के एक मुख्य निरीक्षक की नियुक्ति के साथ एक विस्फोटक विभाग अस्तित्व में आया था। फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण विकास 1897 में कलकत्ता में फिंगर प्रिंट ब्यूरो का निर्माण था, जो कि अपनी तरह का दुनिया का पहला ब्यूरो था। 1910 में कलकत्ता में भारत सरकार के लिए इंपीरियल सेरोलॉजिस्ट के तहत एक केंद्रीय सेरोलॉजिस्ट प्रयोगशाला स्थापित की गई थी

1930, एक शस्त्र विशेषज्ञ नियुक्त किया गया था और आग्नेयास्त्रों की जांच से निपटने के लिए कलकत्ता पुलिस के तहत एक छोटी बैलिस्टिक प्रयोगशाला बनाई गई थी।

3.2 jkT;k e Qkjfl d foKku ç;kx'kkyk,

आजादी के बाद, राज्य सरकारों ने पूर्ण रूप से फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना की आवश्यकता को महसूस किया और अब लगभग सभी बड़े राज्यों में फॉरेंसिक प्रोयोगशालाएँ मौजूद है। वर्तमान में, 30 फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में काम कर रही हैं।

ज्यादातर राज्यों में, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं राज्य पुलिस बल के प्रमुख के अधीन होती हैं। कुछ (गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल) में, वे राज्य सरकार के गृह विभाग के अधीन काम करते हैं।

कुछ राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं ने क्षेत्रीय, जिला और मोबाईल प्रयोगशालाएं भी स्थापित की हैं। वर्तमान में, राज्य फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज (एसएफएसएल) के अलावा, 50 क्षेत्रीय फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज (आरएफएसएल) और 713 जिला मोबाइल फोरेंसिक यूनिट्स (डीएमएफयू) हैं।

एक औसत राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का कार्य विभिन्न डिवीजनों या शाखाओं जैसे कि बैलिस्टिक, जीवविज्ञान, रसायन शास्त्र, दस्तावेज, विस्फोटक, भौतिकी, फोटोग्राफी, सेरोलॉजी और विष विज्ञान में बांटा गया है।

3.3 dæ d rgr Qkjfld foKku ç;kx'kkyk,

केंद्र सरकार ने फोरेंसिक विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए अपने संस्थान स्थापित किए हैं। गृह मंत्रालय के तहत फोरेंसिक साइंस सर्विसेज (डीएफएसएस) निदेशालय देश में फोरेंसिक विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए एक नोडल एजेंसी है। यह देश में फोरेंसिक सेवाओं के लिए गुणवत्ता और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं और नीतियों को तैयार करता है।

डीएफएसएस कोलकाता, हैदराबाद, चंडीगढ़, भोपाल, पुणे और गुवाहाटी में स्थित छह केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का प्रबंधन करता है।

अपराधों की जांच के लिए वैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए 1965 में दिल्ली में निदेशक, सीबीआईएल के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत दिल्ली में एक सातवीं केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) की स्थापना की गई थी। यह देश में सबसे व्यापक और पूरी तरह सुसज्जित प्रयोगशालाओं में से एक है।

डीएफएसएस शिमला, कोलकाता और चंडीगढ़ में स्थित प्रश्नित दस्तावेज़ों के सरकारी परीक्षक के तीन कार्यालयों को भी प्रशासित करता है।

4 ifyÇlx e dæ dh Hkfedk

4.1 loèkkfud çkoèkku

हालांकि भारत के संविधान में कहा गया है कि "पुलिस" और "सार्वजनिक आदेश" राज्य के विषय हैं, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण पुलिस कार्य के कई क्षेत्रों को इंगित करता है जिसमें केंद्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। संविधान सिविल पावर की सहायता के लिए; खुफिया ब्यूरो और केंद्रीय जांच ब्यूरो को बनाए रखने के लिए; पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए, अनुसंधान को बढ़ावा देने और जांच में वैज्ञानिक या तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए संस्थानों की स्थापना और अपराध में कमी; और भारतीय पुलिस सेवा की भर्ती और प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार पर संघ की सशस्त्र बलों को तैनात करने की ज़िम्मेदारी देता है, जिसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को शामिल किया जाता है।[61]

समवर्ती सूची में आपराधिक कानून और आपराधिक प्रक्रिया आंकड़े, जो केंद्र सरकार को आपराधिक मामलों से निपटने के साथ–साथ प्रक्रियात्मक कानूनों को लागू करने या संशोधित करने के लिए सशक्त बनाता है[62] केंद्र राज्य पुलिस बल के सदस्यों की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का उनकी सहमति के साथ विस्तार कर सकता है।[63]

संविधान में एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह है की "राज्य के बाहरी आक्रामकता और आंतरिक अशांति के खिलाफ हर राज्य की रक्षा संघ का कर्तव्य है और यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक राज्य की सरकार इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलती है।"[64]यदि राज्य में संवैधानिक मशीनरी का खंडन होता है तो केंद्र सरकार राज्य सरकार के सभी कार्यों को ले सकती है[65]

इन संवैधानिक प्रावधानों के अलावा, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को अपनी पुलिस बलों के आधुनिकीकरण करने के लिए पर्याप्त अनुदान प्रदान करती है।

4.2 x`g e=ky; dh Hkfedk

गृह मंत्रालय (एमएचए) के माध्यम से केंद्र सरकार पुलिस के संबंध में निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करती है:[66]

1. भारतीय पुलिस सेवा की भर्ती और प्रबंधन
2. खुफिया ब्यूरो, केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य केंद्रीय पुलिस संगठनों का संचालन

---

61 भारत का संविधान, सातवीं अनुसूची, सूची 1, प्रवेश संख्या 2, 8, 65 और 70

62 भारत का संविधान, सातवीं अनुसूची, सूची प्प, प्रवेश संख्या 1 और 2

63 भारत का संविधान, सातवीं अनुसूची, सूची 1, प्रवेश संख्या 80

64 भारत का संविधान, अनुच्छेद 355

65 इबिड, अनुच्छेद 356

66 राष्ट्रीय पुलिस आयोग, सातवीं रिपोर्ट, मई 1981, प 68

3. नागरिक शक्ति की सहायता के लिए केंद्रीय सशस्त्र और अर्धसैनिक बलों को तैयार, संधारण (मेटेंनेन्स) और तैनात करती है।
4. देश में पुलिस बलों को संचार का स्वतंत्र चैनल प्रदान करने के लिए पुलिस वायरलेस के समन्वय निदेशालय को बनाए रखना
5. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को बनाए रखना, जो राष्ट्रीय स्तर के अपराध से संबंधित डेटा को एकत्रित और प्रसारित करने के लिए ज़िम्मेदार है; पुलिस रिकॉर्ड के लिए अपराध रिकॉर्ड और कंप्यूटरीकरणऔर कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का उपयोग
6. पुलिस अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव और जांच के लिए वैज्ञानिक सहायता प्रदान करना
7. देश में एक समान आपराधिक न्याय प्रणाली के कामकाज के लिए कानूनों को लागू करना
8. विभिन्न राज्य पुलिस संगठनों की गतिविधियों को समन्वयित करना
9. अपराध, कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा मामलों से निपटने में राज्य सरकारों को सलाह और सहायता प्रदान करना
10. राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

इसके अलावा, एमएचए केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस बलों पर प्रशासनिक नियंत्रण का प्रयोग करता है।

4.3 Hkkjrh; ifyl lsok

स्वतंत्रतातोपरान्त, देश को दो अखिल भारतीय सेवाओं – भारतीय सिविल सेवा (आईसीएस) और भारतीय पुलिस (आईपी) विरासत में मिले। इनका नाम क्रमशः भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के रूप में रखा गया। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत गठित किए गए थे और कानून उन्हें नियंत्रित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

31 दिसंबर, 2017 को आईपीएस अधिकारियों की अधिकृत ताकत 4940 थी।[67] आईपीएस के लिए चुने गए अधिकारियों की संख्या रिक्तियों के आधार पर साल–दर–साल भिन्न होती है। अधिकारी केंद्र में और साथ ही राज्यों में देश में पुलिस बलों को उच्च स्तर का नेतृत्व प्रदान करते हैं।

आईपीएस कैडर को गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मंत्रालय सेवा से संबंधित सभी फैसले लेता है, जिसमें इसकी ताकत, प्रशिक्षण, कैडर आवंटन, पुष्टि, पैनल, प्रतिनियुक्ति, वेतन और भत्ते, अनुशासनात्मक मामलों आदि शामिल हैं। सेवा राज्य के कार्यकर्ताओं में आयोजित की जाती है। केंद्र सरकार के लिए कोई अलग कैडर नहीं है, भले ही आईपीएस अधिकारी केंद्र सरकार की सेवा भी करते हैं। वे राज्य के कैडरों में बने केंद्रीय रिजर्व से केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर आते हैं।

आईपीएस में चुने गए अधिकारी पुलिस के सहायक अधीक्षक के रूप में शामिल होते हैं और भारत सरकार द्वारा विभिन्न राज्य के कैडरों को आवंटित किए जाते हैं। राज्यों

67 गृह मंत्रालय, वार्षिक रिपोर्ट, 2017–18, प 107

में आईपीएस अधिकारियों के पोस्टिंग, स्थानान्तरण, पदोन्नति इत्यादि से संबंधित सभी मामलों को राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले अधिकारियों के संबंध में समान प्रशासनिक नियंत्रण का उपयोग किया जाता है। एक आईपीएस अधिकारी को केवल केंद्र सरकार द्वारा ही सेवा से हटाया या खारिज किया जा सकता है।

4.4 dsæh; ifyl lxBu ¼lhihvks½

केंद्र सरकार ने केंद्रीय पुलिस संगठनों (सीपीओ) के रूप में जाने वाले कई पुलिस संगठनों की स्थापना की है। केंद्र सरकार के तहत काम कर रहे सीपीओ को व्यापक रूप से दो समूहों में विभाजित किया जा सकता है। एक सशस्त्र पुलिस संगठन है, जिसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ), असम राइफल्स (एआर), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), इंडो जैसे जाना जाता है। भारत–तिब्बती सीमा पुलिस (आईटीबीपी), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) और सशक्त सीमा बल (एसएसबी)। उन्हें गृह मंत्रालय के "पुलिस" बजट से बाहर निकाला जाता है और इसके प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य किया जाता है।

दूसरे समूह में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (बीपीआरडी), केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), पुलिस समन्वय निदेशालय (डीसीपीडब्ल्यू), खुफिया ब्यूरो (आईबी), राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) और राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान और फोरेंसिक विज्ञान (एनआईसीएफएस)। इसके अलावा, पुलिस प्रशिक्षण संस्थान भी हैं, जैसे राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एनपीए) और उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी (एनईपीए), जिन पर चर्चा की गई है।

वित्त मंत्रालय के तहत कुछ खुफिया और जांच एजेंसियां भी पुलिस कार्य करते हैं। वे खुफिया खबर एकत्र करने और सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर, विदेशी मुद्रा, मनी लॉन्डरिंग और नशीले पदार्थों की तस्करी से संबंधित आर्थिक अपराधों की जांच का कार्य करता हैं। इनमें से कुछ केन्द्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो, राजस्व खुफिया महानिदेशालय, प्रवर्तन निदेशालय, वित्तीय खुफिया इकाई, विरोधी उत्पीड़न महानिदेशालय, आयकर (निदेशालय) के महानिदेशालय, नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो इत्यादि हैं। इसी प्रकार, वहां कुछ खुफिया संगठन भी हैं, जैसे कि राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (एनटीआरओ), अनुसंधान और विश्लेषण विंग (आरएडब्ल्यू), एविएशन रीसर्च सेंटर ऑफ रॉ, जो कैबिनेट सचिवालय के तहत काम करता है। कैबिनेट सचिवालय के तहत एक और संगठन विशेष संरक्षण समूह है, जो प्रधान मंत्री और उनके परिवार के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करता है। एक रेलवे सुरक्षा बल है जो रेल मंत्रालय के नियंत्रण में कार्य करता है। हम इस अध्ययन से उन सभी संगठनों को छोड़ने का प्रस्ताव रखते है जो गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत नहीं आते हैं।

4.4.1 dsæh; l'kL= ifyl cy ¼lh,iQ½

सीएपीएफ में, एआर, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी सीमा सुरक्षा बल हैं। हालांकि एआरए, एमएचए के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करता है, लेकिन इसका परिचालन नियंत्रण रक्षा मंत्रालय के पास रहता है। एनएसजी विशेष संचालन के लिए प्रशिक्षित कमांडो बल है। सीआईएसएफ औद्योगिक उपक्रमों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों

को सुरक्षा प्रदान करता है। कानून और व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और प्रतिद्वंद्विता के रखरखाव से संबंधित मामलों में सीआरपीएफ को नागरिक शक्ति की सहायता के लिए तैनात किया गया है।

ऐसी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का एक संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

4.4.1.1 vle jkbQYl

असम राइफल्स (एआर) सभी सीएपीएफ का सबसे पुराना है। यह एक छोटी इकाई के रूप में स्थापित किया गया था, असम और उसके पड़ोसी क्षेत्रों में ब्रिटिश बस्तियों और चाय एस्टेट की रक्षा के लिए, 1835 में 750 पुरुषों को कैचर लेवी के नाम से जाना जाता है। इसका नाम बदलकर 1891 में कैचर लेवी फ्रंटियर पुलिस किया गया था, 1913 में असम सैन्य पुलिस के रूप में और 1917 में असम राइफल्स के रूप में।

आजादी से पहले, सेना ने उस पुलिस बल के प्रमुख के नियंत्रण में असम पुलिस का एक हिस्सा बनाया था। आजादी के बाद, इसे असम पुलिस से हटा दिया गया था और उसके बाद से हमेशा सेना अधिकारियों की अध्यक्षता में है। वर्तमान में, इसका नेतृत्व एक महानिदेशक करते हैं, जो सेना के लेफ्टिनेंट जनरल हैं। यद्यपि संगठन के अपने अधिकारियों का एक कैडर है, लेकिन सेना से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों द्वारा सबसे वरिष्ठ पदों को भरा जाता है।

बल वर्तमान में असम राइफल्स अधिनियम, 1941 द्वारा शासित है। इसका मुख्यालय मेघालय में शिलांग में है। एक निदेशालय जनरल मुख्यालय के अलावा, बल में 3 इंस्पेक्टरेट जनरल मुख्यालय, 12 क्षेत्र मुख्यालय, 46 बटालियन, एक प्रशिक्षण केंद्र, कुछ प्रशासनिक इकाइयां हैं, जिनकी कुल स्वीकृत शक्ति 63,747 कर्मियों की है।[68]

इस चार्टर के कर्तव्य निम्नलिखित हैं:

- अंतरराष्ट्रीय सीमा के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की सुरक्षा बनाए रखना जो 1,631 किलोमीटर से अधिक फैला हुआ है;
- कानून और व्यवस्था बनाए रखने में उत्तर पूर्व में राज्यों की सहायता करना, जब आवश्यक हो; तथा
- उत्तर पूर्व के राज्यों में काउंटर विद्रोह उपायों को लेना।

डीजी, असम राइफल्स

असम राइफल्स कोंटीजेंट ड्यूटी पर

68 इबिड, पी 127

4.4.1.2 lhek lqj{kk cy

1965 के भारत–पाक युद्ध से पहले, भारत–पाक सीमा पर सुरक्षा बनाए रखना संबंधित राज्यों की सशस्त्र पुलिस बलों की ज़िम्मेदारी थी। युद्ध ने भारत सरकार को भारत–पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक विशेष बल स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की और 1 दिसंबर 1965 को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की स्थापना की। सभी पच्चीस राज्य सशस्त्र भारत–पाक सीमा पर तैनात पुलिस बटालियनों को इस बल में विलय कर दिया गया था।

तब से बल का काफी विस्तार हुआ है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष पुलिस महानिदेशक है। मुख्यालय विभिन्न निदेशकों में विभाजित है, प्रशासन, कर्मियों, प्रावधान, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी, संचालन, खुफिया, प्रशिक्षण, खाते, कानून इत्यादि जैसे मामलों से निपटने के लिए।

इसके क्षेत्र के गठन में विशेष निदेशालय जनरल, पूर्वी कमान और इसी तरह के निदेशालय जनरल, वेस्टर्न कमांड, 13 फ्रंटियर और 46 क्षेत्र मुख्यालय और 186 बटालियन शामिल हैं। 5 प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान, 11 सहायक प्रशिक्षण केंद्र और 3 मामूली प्रशिक्षण संस्थान हैं। इसके अलावा, सिग्नल रेजिमेंट्स, आर्टिलरी रेजिमेंट्स, एयर विंग और वॉटर विंग भी हैं। 31 दिसंबर 2017 को बल की कुल स्वीकृत शक्ति 2,56,701 थी।[69] इसकी परिचालन जिम्मेदारी पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा के 6,386.36 किमी से अधिक फैली हुई है। इसे सेना के परिचालन नियंत्रण के तहत जम्मू–कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर भी तैनात किया जाता है।

बल बीएसएफ अधिनियम द्वारा शासित है, जिसे 1968 में संसद द्वारा पारित किया गया था और 1 मार्च 1969 को प्रभावी हुआ था। अधिनियम के तहत बीएसएफ नियम 1969 में बनाए गए थे।

बीएसएफ को शांति और युद्ध के समय के कार्यों को सौंपा गया है।[70]

1- 'kkfr le; dk;%

1. सीमा पार अपराधों को रोकने के लिए, भारत के क्षेत्र से अनधिकृत प्रवेश या निकास नियंत्रण
2. तस्करी संबंधित अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए
3. सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देना
4. सार्वजनिक आदेश बनाए रखने में नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए।

2- ;q) le; dk;%

- जब तक मुख्य हमला नहीं होता तब तक कम खतरे वाले क्षेत्रों में डटे रहना
- दुश्मन कमांडो और पैरा–सैनिक छापे के खिलाफ महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की रक्षा के लिए

69 इबिड, पी 131

70 http%@@bsf-nic-in@en@introduction1-html

- सशस्त्र बलों की समग्र योजना के भीतर दुश्मन की अर्धसैनिक या अनियमित ताकतों के खिलाफ सीमित आक्रामक कार्रवाई
- छापे सहित खुफिया जानकारी से जुड़े विशेष कार्यों को निष्पादित करना
- सेना के नियंत्रण में प्रशासित दुश्मन क्षेत्र में कानून और व्यवस्था का रखरखाव
- निर्दिष्ट क्षेत्रों में घुसपैठ कर्तव्य
- एस्कॉर्ट्स का प्रावधान
- युद्ध के कैदियों की रक्षा।

ch,l,Q d s lLFkkid egkfun'kd LoxÊ; Jh d s ,Q #Lreth

jktLFkku lhek ij x'r djus oky s ch,l,Q d s ÅV

ch,l,Q dh efgyk dkaLVscy

4.4.1.3 dæh; vk|kfxd lj{kk cy

सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (सीआईएसएफ) की स्थापना "औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968) के एक अधिनियम द्वारा की गई थी ताकि" बेहतर सुरक्षा और कुछ औद्योगिक उपक्रमों की सुरक्षा "प्रदान की जा सके।[71] यह 10 मार्च 196 9 को लागू हुआ। इस अधिनियम ने सेना को एक घड़ी और वार्ड संगठन के रूप में देखा। मार्च 1983में सीआईएसएफ को संघ की एक सशस्त्र सेना बनाने के लिए संशोधित किया गया था।

इस अधिनियम ने सेना को एक वाच और वार्ड संगठन के रूप में देखा। मार्च 1983 में सीआईएसएफ को संघ की एक सशस्त्र बल बनाने के लिए संशोधित किया गया था। इसे 1989 में और 1999 में फिर से संशोधित किया गया था। 1999 संशोधन में, केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित औद्योगिक संगठनों में सीआईएसएफ को तैनात किया गया, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्यमों के लिए सीआईएसएफ द्वारा परामर्श सेवा और केंद्र सरकार द्वारा सौंपे गए किसी अन्य कर्तव्य के लिए तैनात किया जा सके।[72]

31 दिसंबर 2017 को सीआईएसएफ की 1,50,810 कर्मियों की स्वीकृत शक्ति थी।[73] वर्तमान में, बल 339 इकाइयों को सुरक्षा कवर प्रदान करता है, जिसमें 59 घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और 101 औद्योगिक उपक्रमों को अग्नि सुरक्षा कवर शामिल है। यह प्रमुख महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, जैसे परमाणु ऊर्जा संयंत्र, अंतरिक्ष प्रतिष्ठान, रक्षा उत्पादन इकाइयों, खानों, तेल रिफाइनरियों, समुद्री बंदरगाहों, इस्पात संयंत्रों, हवाई अड्डों, बिजली संयंत्रों, सरकारी भवनों, विरासत स्मारकों और महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह देश[74] में 159 मेट्रो स्टेशनों को सुरक्षा प्रदान करता है और जब आवश्यक हो, आंतरिक सुरक्षा और चुनाव ड्यूटी पर भी तैनात किया जाता है।

फोर्स की अध्यक्षता महानिदेशक पद के अधिकारी द्वारा की जाती है, जिसे एडिशनल महानिदेशक कहा जाता है, साथ ही दो इंस्पेक्टर जनरल और मुख्यालय के अन्य अधिकारियों द्वारा सहायता दी जाती है। मुख्यालय में प्रतिष्ठान, प्रेरण और योजना, प्रशिक्षण, प्रावधान, संचालन, कर्मियों आदि के मामलों से निपटने के लिए विभिन्न निदेशालय हैं। ये निदेशालय इंस्पेक्टर जनरल/डेप्युटी इंस्पेक्टर जनरल के पद के अधिकारी के अधीन हैं।

क्षेत्र की स्थापना पांच सेक्टर[75] में विभाजित है – हवाई अड्डे क्षेत्र मुख्यालय, उत्तर क्षेत्र, उत्तर पूर्व क्षेत्र, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र। हवाई अड्डे क्षेत्र मुख्यालय को एक एडिशनल महानिदेशक द्वारा आदेश दिया जाता है, जिसे एक महानिरीक्षक, एक उप निरीक्षक जनरल और कुछ अन्य अधिकारियों द्वारा सहायता दी जाती है। अन्य चार क्षेत्रों में से प्रत्येक का नेतृत्व इंस्पेक्टर जनरल द्वारा किया जाता है, जो अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सहायता प्राप्त करता है। एक क्षेत्र में फील्ड इकाइयों की देखरेख के लिए स्थापित एक या अधिक जोन होते हैं। एक जोन की अध्यक्षता डीआईजी द्वारा की

71 केंद्रीय औद्योगिक बल अधिनियम, 1968 के लिए प्रस्तावना

72 सेंट्रल पुलिस ऑर्गनाइजेशन, पार्ट ५, सहयोगी प्रकाशक प्राइवेट लिमिटेड, 2005, पृष्ठ 75

73 गृह मंत्रालय, वार्षिक रिपोर्ट, 2017–18, पी 133

74 इबिड, पी 134

75 http%@@www-cisf-gov-in@directory@force&head&quarters@ü

जाती है।[76] घटकों या सरकारी प्रतिष्ठानों की अध्यक्षता इकाई की ताकत के आधार पर डीआईजी/कमांडेंट/उप कमांडेंट/सहायक कमांडेंट/इंस्पेक्टर द्वारा की जाती है।[77]

संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम उनकी सुरक्षा के लिए तैनात सीआईएसएफ कर्मियों के खर्च का भुगतान करते हैं।

4.4.1.4 dæh; fjto ifyl cy

यह बल 1939 में क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में बढ़ाया गया था और मध्य भारत के तत्कालीन रियासतों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपयोग किया गया था। आजादी के बाद, सेना ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को दोबारा नामित किया। इसे 1949 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस अधिनियम के पारित होने के साथ सांविधिक दर्जा दिया गया था।

आजादी के समय, बल में 1,038 कर्मियों की कुल ताकत के साथ एक बटालियन शामिल था।[78] तब से, सेना बढ़ी है और 31 दिसंबर 2017 को इसकी कुल ताकत 3,19,501 थी। इसके अलावा, 2018–19 तक 4 बटालियनों को बढ़ाया जाना है।[79]

फोर्स का नेतृत्व पुलिस महानिदेशक के पद के आईपीएस अधिकारी करते हैं, जिन्हें पुलिस के तीन एडिशनल निदेशक जनरल, पुलिस महानिरीक्षक, एक वित्तीय सलाहकार और निदेशक (चिकित्सा) द्वारा सहायता दी जाती है। मुख्यालय में सात निदेशालयों में से प्रत्येक प्रशासन, कार्मिक, प्रशिक्षण, संचालन, प्रावधान, खुफिया, प्रतिष्ठान का नेतृत्व इंस्पेक्टर जनरल आईजी (प्रतिष्ठान) द्वारा किया जाता है और साथ ही वह संचार और कार्यों की देखभाल करता है।

वर्तमान में, बल में 242 बटालियन, 43 समूह केंद्र, 20 प्रशिक्षण संस्थान, 7 शस्त्र कार्यशालाएं और 3 केंद्रीय हथियार स्टोर हैं। इस क्षेत्र में इसके पर्यवेक्षी संरचनाओं में तीन विशेष क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें प्रत्येक डीजी, एक एडिशनल डीजी जोन, 21 आईजी सेक्टर, दो आईजी ओपीएस सेक्टर, 39 रेंज और 17 ओपीएस रेंज शामिल हैं।[80]

फोर्स को खण्डों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक का नेतृत्व आईजी द्वारा किया जाता है। खंड के तहत समूह केंद्र हैं। प्रत्येक समूह केंद्र/ग्रुप सेंटर से पांच से सात बटालियन जुड़े हुए हैं। ग्रुप सेंटर का प्रमुख डिप्टी आईजी है। खंड और समूह केंद्र देश के विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं ताकि आपात स्थिति से निपटने के लिए सेना को किसी भी स्थान या समय पर तेजी से एकत्रित करके तैनात किया जा सके।

फोर्स का गठन करने वाली 242 बटालियनों में महिला बटालियन, रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) और कोबरा (सीओ–बीआरए) कमांडो प्रत्येक के 10 बटालियन शामिल हैं। सीआरपीएफ एकमात्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जिसमें 6 महिला बटालियन और 15 आरएएफ बटालियनों प्रत्येक में 96 महिलाओं के 01 दल हैं। जबकि आरएएफ मुख्य रूप से सांप्रदायिक दंगों से निपटने के लिए बनाया गया है, चरमपंथियों और विद्रोहियों से लड़ने के लिए, गुरिल्ला / जंगल युद्ध संचालन के लिए कोबरा बनाया गया है।

---

76 केंद्रीय पुलिस संगठन, भाग 1, सहयोगी प्रकाशक प्राइवेट लिमिटेड, 2005, पृष्ठ 88
77 इबिड, पी 90
78 गृह मंत्रालय, वार्षिक रिपोर्ट, 2014–2015, पी 3 9 इबिड, पी 3 9
79 गृह मंत्रालय, वार्षिक रिपोर्ट, 2017–2018, पी 135
80 इबिड

एक सीआरपीएफ महिला बटालियन अधिकारी

सीआरपीएफ प्रशिक्षण के दौरान महिला कैडेट

ड्यूटी पर आरएएफ यूनिट

सीआरपीएफ अधिनियम और नियमों के अनुसार, सेना नागरिक शक्ति की सहायता में कार्य करती है। राज्य और संघ शासित प्रदेशों की कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करना इसकी मुख्य भूमिका है। दंगों से निपटने के अलावा, पिछले कुछ सालों में विद्रोह विरोधी और आतंकवाद विरोधी अभियान, वीआईपी सुरक्षा, विमानन सुरक्षा, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा, चुनाव कर्तव्यों, गार्ड कर्तव्यों, सेना काफिले संरक्षण कर्तव्यों आदि पर भी तैनात किया गया है।

4.4.1.5 Hkkjr&frCcrh lhek iqfyl

1962 में चीनी आक्रामकता के चलते आईटीबीपी को चार बटालियनों की मामूली ताकत के साथ शुरू किया गया था। इसे मूल रूप से आपूर्ति, संचार और बुद्धि के संदर्भ में "गुरिल्ला सह खुफिया सह युद्ध बल" के रूप में माना जाता था। समय के साथ, इसकी ताकत में वृद्धि की गई है और यह एक पारंपरिक सीमा सुरक्षा बल बन गया है। यह भारत चीन बॉर्डर की 3,844 कि.मी. विस्तृत सीमा की 176 चौकियों के माध्यम से रक्षा करता है, जो हिमालय में 9000 फीट से लेकर 18,750 फीट की ऊंचाई पर स्थित हैं ।

यह बल मूल रूप से सीआरपीएफ अधिनियम, 1949 के तहत स्थापित किया गया था। अब यह एक अलग कानून – भारत–तिब्बती सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 द्वारा शासित है। इस अधिनियम के तहत, नियम 1994 में बनाए गए थे:

इस बल की मुख्य भूमिका है:

- सीमाओं पर सतर्कता बनाए रखें, सीमा उल्लंघन का पता लगाएं और रोकें, स्थानीय जनसंख्या के बीच सुरक्षा की भावना को बढ़ावा दें;
- अवैध प्रवास, ट्रांस–सीमा तस्करी और अपराधों की जांच करें;
- संवेदनशील प्रतिष्ठानों, बैंकों और संरक्षित व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करना; तथा
- अशांति की स्थिति में किसी भी क्षेत्र में नियंत्रण स्थापित करें।

जबकि आईटीबीपी की प्राथमिक भूमिका भारत–तिब्बती सीमा पर पुलिसिंग है, यह आंतरिक सुरक्षा कर्तव्यों पर भी तैनात है।

फोर्स की अध्यक्षता महानिदेशक के द्वारा की जाती है, जिसे एडिशनल महानिदेशक द्व ारा सहायता दी जाती है। मुख्यालय में चार निदेशालय हैं – प्रावधान, संचालन, कार्मिक और कार्य और कल्याण, प्रत्येक का नेतृत्व आईजी द्वारा किया जाता है। क्षेत्र की स्थापना फ्रंटियर, सेक्टर और बटालियनों में बांटी गई है। 5 फ्रंटियर हैं, प्रत्येक आईजी के तहत, 15 सेक्टर, प्रत्येक डीआईजी और 56 सर्विस बटालियन द्वारा कमांडकिया जाता है। इसके अलावा, 4 विशिष्ट बटालियन, 2 आपदा प्रबंधन बटालियन और 14 प्रशिक्षण केंद्र हैं, 31 दिसंबर 2017 को सेना की कुल ताकत 89,433 थी।[81]

,d vkÃVhchih vfèkdkjh lyke y: jgk g

81 इबिड, पी 137

4.4.1.6 jk"Vªh; lqj{kk xkMZ

1984 में 'ब्लू स्टार' ऑपरेशन के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार आतंकवाद की समस्या से निपटने है, जैसे कि बंधक बनाने, विमानों का अपहरण, अपहरण आदि। यह विशेष रूप से विशिष्ट स्थितियों से निपटने के लिए सुसज्जित और प्रशिक्षित और केवल असाधारण स्थितियों में उपयोग किया जाता है। इसके कमांडो को उच्च जोखिम वाले कार्यों को संभालने में प्रशिक्षित किया जाता है जैसे कि काउंटर–हाइजैकिंग और काउंटर विद्रोह अभियान। इसमें दो मुख्य घटक हैं: विशेष कार्य समूह (एसएजी) जिसमें सेना के कर्मियों और विशेष रेंजर्स समूह (एसआरजी) शामिल हैं, जिसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/राज्य पुलिस बलों से लिए गए कर्मी शामिल होते हैं।

बल को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम, 1986 और अगस्त 1987 अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा नियंत्रित किया गया है। इस अधिनियम ने औपचारिक रूप से एनएसजी को संघ की सशस्त्र सेना के रूप में घोषित किया।

2009 में, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता में एनएसजी के चार क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए गए ताकि संकट की स्थिति में इसकी तेजी से तैनाती को सक्षम बनाया जा सके।

एनएसजी राष्ट्रीय बम सेंटर डाटा रखता है, जो देश में सभी बमबारी घटनाओं पर नज़र रखता है तथा रिकॉर्ड करके विश्लेषण करता है।

फोर्स की अध्यक्षता एक महानिदेशक द्वारा की जाती है, जिसे चार आईजी स्तर के अधिकारियों द्वारा सहायता दी जाती है। खुफिया, संचालन, प्रशिक्षण, संचार, प्रशासन और इंजीनियरिंग जैसे विभिन्न कार्यों की देखभाल करने के लिए डीआईजी हैं। एनएसजी के पास स्वयं का कोई कैडर नहीं है और मुख्य रूप से सेना और सीएपीएफ से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों और सिपाहियों द्वारा तैयार किया जाता है, हालांकि डीजी भारतीय पुलिस सेवा से है। 1.1.2017 को इसकी कुल स्वीकृत शक्ति 10,844 थी और वास्तविक ताकत 9,795 थी। (एडिशनल फूटनोट, बीपीआरडी, पज 79 – 1 जनवरी 2017 को भारत में पुलिस संगठनों पर डेटा, पृष्ठ 79)[82]

4.4.1.7 l'kL= lhek cy

सशत्र सीमा बल विशेष सेवा ब्यूरो से निकला है , जिसे 1962 में भारत–चीन विवाद के चलते सीमा की आबादी का मनोबल और क्षमता बढ़ाने और विचलन, घुसपैठ और तबाही के खतरों के खिलाफ 1963 में स्थापित किया गया था। यह 2001 में सीमा सुरक्षा बल बन गया और इसका नाम बदलकर सशत्र सीमा बाल रखा गया। इसे भारत–नेपाल सीमा पर तैनात किया गया है जिसमें 1,715 किमी और भारत–भूटान सीमा 699 किमी है।[83]

इसकी भूमिका इस प्रकार है:–

- सीमा क्षेत्र में रहने वाले लोगों में सुरक्षा कि भावना पैदा करने,
- भारत के सीमा क्षेत्र सीमा पार से अपराध को रोकना तथा तस्करी तथा,
- अन्य गैर क़ानूनी गतिवधियों को रोकना

82 1 जनवरी 2017 को भारत में पुलिस संगठनों पर डेटा, पृष्ठ। 76।

83 इबिड, प 177

फोर्स के पास डीजी के पद के अधिकारी के रूप में एक प्रमुख होता है, जिसे एडिशनल डीजी द्वारा सहायता दी जाती है । मुख्यालयों में पांच मुख्य शाखाएं हैं– संचालन, खुफिया और संचार; कार्मिक और प्रशिक्षण; प्रशासन, प्रावधान; और चिकित्सा। आईजी रैंक का एक अधिकारी इन शाखाओं में से प्रत्येक का नेतृत्व करता है। फील्ड प्रतिष्ठान छह फ्रंटियर, 18 सेक्टर और 69 बटालियनों में बांटा गया है।[85] 1.1.2017 को एसएसबी की कुल स्वीकृत शक्ति 1,87,498 थी और वास्तविक ताकत 80,215 थी।[85]

4.4.1.8 lh,ih,Q dh of)

केंद्र सरकार द्वारा सालाना प्रकाशित आंकड़ों के मुताबिक, 1 जनवरी, 2017 को 24.64 लाख राज्य पुलिस बलों की कुल स्वीकृत शक्ति में से सशस्त्र पुलिस बलों की संख्या 4.75 लाख थी।[86] ऊपर चर्चा की गई सात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की संयुक्त स्वीकृत शक्ति उस तिथि पर 11.54 लाख थी.[87] अगर अन्य केंद्रीय पुलिस संगठनों को ध्यान में नहीं रखा जाता है, तो देश में सशस्त्र पुलिस 1 जनवरी, 2017 को 16.29 लाख तक बढ़ी, देश में कुल पुलिस शक्ति के 45.03ः से थोड़ा अधिक है।

पिछले कुछ दशकों के दौरान सशस्त्र पुलिस ने देश में स्थापना और विस्तार के कारण असाधारण वृद्धि दर्ज की है। आजादी से पहले, असम राइफल्स (एआर) और क्राउन रिजर्व पुलिस (सीआरपी) – केवल दो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल मौजूद थे। वर्तमान में, केवल गृह मंत्रालय के तहत ही सात हैं। एनएसजी के अलावा, अन्य छह सीएपीएफ ने समय की अवधि में विशाल और तेजी से विस्तार देखा है।[88] यह आंकड़े नीचे दिखाए गए हैः

rkfydk 18% lh,ih,Q dh tu'kfä e of)

o"k	,vkj	ch,l,Q	lhvkÃ,l,Q	lhvkjih,Q	vkÃVhchih	,u,l th	,l,lch	dy
2000	52,275	1,82,874	88,322	1,67,367	30,356	7,357	31,750	5,60,301
2005	60,365	2,08,442	94,265	2,48,690	36,324	---------	31,543	---------
2006	65,185	2,08,937	93,521	2,48,689	36,375	---------	47,147	---------
2007	67,266	2,09,361	94,289	2,60,751	36,495	7,314	55,351	7,30,827
2008	65,185	2,10,244	1,03,872	2,60,873	50,326	7,314	55,351	7,53,165
2009	65,187	2,10,271	1,10,349	2,63,598	57,475	7,314	55,397	7,69,591
2010	65,389	2,19,560	1,22,268	2,75,675	57,439	9,506	55,353	8,05,190
2011	65,375	2,28,737	1,28,471	2,85,630	57,709	9,506	64,730	8,40,158
2012	66,412	2,40,532	1,30,156	2,90,752,	70,523	9,507	78,702	8,88,584
2013	66,412	2,43,161	1,33,628	2,96,752	77,022	9,507	83,409	9,09,891
2014	65,819	2,46,963	1,38,557	2,98,597	84,003	9,508	88,458	9,31,905
2015	66,412	2,52,059	1,41,342	3,03,535	88,958	10,384	91,129	9,53,819
2016	66,411	2,56,831	1,42,250	3,08,862	89,430	10,384	94,065	9,68,233
2017	65,411	2,57,365	144,418	3,22,066	89,912	10,844	1,87,498	10,78,514

1 जनवरी, 2000 को, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कुल संयुक्त ताकत केवल 5,60,301 थी। 1.1.2017 तक यही ताकत 10,78,514 की चौंकाने वाली बड़ी संख्या तक

84 गृह मंत्रालय, वार्षिक रिपोर्ट, 2017–18, पृष्ठ 143

85 1 जनवरी 2017 को भारत में पुलिस संगठनों पर डेटा, पृष्ठ 79 इबिड

86 1 जनवरी 2016 को भारत में पुलिस संगठनों पर डेटा, पृष्ठ 41

87 इबिड, प 79

88 बीपीआर और डी द्वारा प्रकाशित विभिन्न वर्षों के लिए भारत में पुलिस संगठनों पर डेटा से लिया गया

पहुंच गई थी। इस अवधि के दौरान, सीआरपीएफ की ताकत 1.67 से बढ़कर 3.22 लाख हो गई; बीएसएफ 1.82 से 2.57 लाख तक; सीआईएसएफ 0.88 से 1.44 लाख, एसएसबी 31.7 से 1.87 लाख तक; आईटीबीपी 30,356 से 89, 912 हजार और एआर 52,275 से 66,411 हजार तक पहुँच गई थी।

4.4.1.9 lh,ih,Q e efgyk,

पिछले कुछ सालों के दौरान, कई महिलाएं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में शामिल हो गई हैं। सीएपीएफ में महिलाओं की वर्तमान ताकत निम्नानुसार है:

rkfydk 19 & 01 01-17 dk lh,ih,Q e efgykvk dh rkdr[89]

lhih,e,Q	okLrfod cy	efgyk cy	çfr'kr
एआर	64,972	571	0.86
बीएसएफ	252,984	4,187	1.63
सीआरपीएफ	132,091	6,646	4.60
आईटीबीपी	296,404	6,699	2.08
एनएसजी	83,462	1,635	1.82
एसएसबी	80,215	2,257	1.20
कुल	10,67,670	21,995	2.06

4.4.1.10 lh,ih,Q ij 0;;

अपने सशस्त्र पुलिस बलों पर केंद्र सरकार का व्यय तेजी से बढ़ रहा है। यह जानकारी निम्न तालिका में दी गई है:

rkfydk 20% 2003&2004 l 2017&2018 rd ¼31-12-2017 rd½ lh,ih,Q ij okLrfod 0;;[90]

(Rs. In Crores)

o"k	,vkj	ch,l,Q	lhvkÃ ,l,Q	lhvkj ih,Q	vkÃVhchih	,u,l th	,l,lch	dy
2003-04	929.15	2970.24	982.19	2087.78	468.32	113.81	315.92	7867.41
2004-05	1005.64	2635.76	1061.24	2516.96	552.72	128.00	381.84	8282.16
2005-06	1314.17	3560.45	1134.07	3228.03	576.25	14028	381.97	10335.22
2006-07	1478.29	3398.85	1225.59	3642.40	707.99	151.19	779.92	11384.23
2007-08	1541.81	3879.00	1376.23	3911.69	1000.73	163.90	943.70	12817.06
2008-09	2016.27	5398.50	2169.28	5557.82	1433.24	210.52	1241.63	18027.26
2009-10	1599.02	4472.66	1978.88	5262.33	1134.05	231.70	801.31	15479.95
2010-11	2814.79	7366.87	2780.44	8128.10	1862.35	491.77	1630.36	25074.68
2011-12	3207.91	8741.67	3382.72	9662.89	2208.09	578.59	2073.08	29854.95
2012-13	3359.83	9772.55	3967.95	11040.13	2917.85	541.77	2765.16	34365.24
2013-14	3651.21	10904.74	4401.49	11903,70	3346.94	536.70	2979.16	37723.94
2014-15	3802.23	12515.40	5037.52	13308.95	3686.84	573.46	3399.64	42288.04
2015-16	3804.59	12597.42	5045.52	13475.23	3669.35	581.49	3606.26	42779.86
2016-17	4917.44	15574.77	7013.85	17328.26	5086.73	835.58	4619.46	55376.09
2017-18	4066.84	13796.11	6182.74	15812.32	4596.89	778.97	4220.78	49454.65

89 1 जनवरी 2017 को भारत में पुलिस संगठनों पर डेटा, प 79 और प 155

90 एमएचए, वार्षिक रिपोर्ट 2017–2018, प 149

2003–04 में, केंद्र सरकार ने सीएपीएफ पर केवल 7,867.41 करोड़ रुपये खर्च किए थे,2017–18 में यह व्यय 628.60: बढ़कर 49454.65 करोड़ रुपये हो गया था।

4.4.1.11 Hkkjrh; fjtoZ cVkfy;uksa dh LFkkiuk

भारत रिजर्व बटालियन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस की स्थापना का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन फिर भी उसकी यहां पर चर्चा की जा रही है क्योंकि उन्हें राज्य सरकारों को सशस्त्र पुलिस की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करने के लिए गठित किया जाता है।

केंद्र द्वारा कानून व्यवस्था में गड़बड़ी से निपटने और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों पर निर्भरता को कम करने के लिए राज्यों कि क्षमता को और बढ़ने के लिए केंद्र द्वारा 1971 में भारत रिजर्व बटालियनों को गठित की एक योजना शुरू की गई थी।

इस योजना ने राज्यों को सशस्त्र पुलिस बटालियन बनाने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की।

बटालियन को गठित करने की केवल प्रारंभिक लागत के आधार पर राज्यों को प्रतिपूर्ति की गई थी क्योंकि 50: अनुदान सहायता और 50: दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण।

हाल ही में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए प्रत्येक 4 आईआर बटालियनों को गठित करते समय, वित्तीय मानदंडों में संशोधन किया गया। एक आईआर बटालियन गठित करने की मानक लागत 34.92 करोड़ रुपये है। इस राशि का 75: भारत सरकार द्वारा अनुदान सहायता के रूप में राज्यों को प्रतिपूर्ति की जानी है, जबकि 25: राज्य सरकारों द्वारा दिया जाना है। इसके अलावा, भारत सरकार बुनियादी ढांचे की लागत की 50: प्रतिपूर्ति करेगी।[91]

चूंकि आईआर बटालियन भारत रिजर्व का हिस्सा है, इसलिए केंद्र सरकार का इस पर पहला अधिकार है और इसे कहीं और आवश्यकताओं के मामले में तैनात किया जा सकता है। ऐसे मामले में, इसका आवर्ती व्यय इसकी सेवा लेने वाले राज्य सरकार वहन किया जाता है।

अभी तक 175 स्वीकृत भारतीय रिजर्व बटालियनों में से 144 को कार्यरत किया गया है।[92]

4.4.2 vU; dæh; ifyl lxBu

4.4.2.1 ifyl vuqla/kku vkj fodkl C;jks

अगस्त 1970 में गृह मंत्रालय में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआर और डी) की स्थापना की, इसका मुख्य कारण था बदलते हुए समाज में पुलिस समस्याओं के त्वरित और व्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा देना तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास कर पुलिस कार्यो में तेजी से उपयोग करना है। पिछले कुछ वर्षों में, बीपीआरडी को देश में पुलिस बलों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं की निगरानी और उस प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए उपाय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह राज्यों को उनकी पुलिस बलों और सुधार प्रशासन के आधुनिकीकरण में सहायता करता है। हाल ही में, बीपीआरडी को राष्ट्रीय पुलिस मिशन के काम के समन्वय और नियंत्रण की ज़िम्मेदारी

91 गृह मंत्रालय, वार्षिक रिपोर्ट, 2017–18, पी 153

92 इबिड

सौंपी गई थी, जो परियोजनाओं के विकास के लिए, पुलिस तकनीकों का हर क्षेत्र में तीव्र गति से विकास करने के लिए आवश्यक है”[93]

ब्यूरो पुलिस को सामयिक हित के विषयों पर अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस आयोजित करता है। पुलिस समस्याओं में सामाजिक विज्ञान के छात्रों के बीच अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, यह पीएचडी काम के लिए स्नातकोत्तर छात्रों को सालाना 12 फैलोशिप पुरस्कार देता है। फैलोशिप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पैटर्न पर संचालित की जाती हैं। ब्यूरो पुलिस के हित के कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशन प्रस्तुत करता है। एक भारत में डेटा ऑन पुलिस संगठन नामक वार्षिक प्रकाशन है, जो राज्य पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के बारे में व्यापक और उपयोगी सांख्यिकीय जानकारी प्रदान करता है। दूसरा त्रैमासिक प्रकाशन है, द इंडियन पुलिस जर्नल (आईपीजे), जो पुलिस अधिकारियों और सामाजिक वैज्ञानिकों से देश में पुलिस बलों के हित और महत्व के विभिन्न विषयों पर लेख प्रकाशित करता है। हिंदी में एक ऐसा ही प्रकाशन– पुलिस विज्ञान कहा जाता है जिसे हर तिमाही में भी प्रकाशित किया जाता है।

वर्तमान में, बीपीआरडी में निम्नलिखित छह डिवीजन हैं:

1. अनुसंधान और सुधार प्रशासन।
2. आधुनिकीकरण और विकास।
3. प्रशिक्षण
4. राष्ट्रीय पुलिस मिशन
5. विशेष इकाइयां
6. प्रशासन

संगठन के पास एक प्रमुख महानिदेशक है जो आईजीपी के पद के अधिकारियों के समूह और एडिशनल महानिदेशक द्वारा समर्थित है, जिनमें से प्रत्येक छह डिवीजनों में से एक का नेतृत्व कर रहा है।

4.4.2.2 dæh; tkp C;jk

केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को 1941 में द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान मूल रूप से भारत सरकार के युद्ध और आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों से जुड़े रिश्वत और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (एसपीई) के रूप में स्थापित किया गया था। एसपीई की भूमिका धीरे–धीरे बढ़ाई गई और 1963 तक, भारतीय दंड संहिता, भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम और 16 अन्य केंद्रीय कृत्यों के विभिन्न वर्गों के तहत अपराधों की जांच करने के लिए अधिकृत किया गया।

1963 में, भारत सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना की।[94]

वर्तमान में, सीबीआई में नौ डिवीजन शामिल हैं:

(1) भ्रष्टाचार निरोधी प्रभाग

(2) आर्थिक अपराध प्रभाग

---

93 http%@@bprd-nic-in@

94 यह 1 अप्रैल 1963 की संकल्प सं 4/31/61–टी भारत सरकार द्वारा गठित किया गया था

(3) विशेष अपराध प्रभाग

(4) कानूनी प्रभाग

(5) समन्वय प्रभाग

(6) प्रशासन प्रभाग

(7) नीति और संगठन प्रभाग

(8) तकनीकी प्रभाग

(9) केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला।

पहले तीन डिवीजन जांच कार्य करते हैं। भ्रष्टाचार निरोधी प्रभाग मुख्य रूप से भ्रष्टाचार अधिनियम, 1988, आईपीसी और अन्य विशेष कानूनों के तहत भ्रष्टाचार के मामलों को देखता है। आर्थिक अपराध प्रभाग बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी सार्वजनिक निधियों का दुरुपयोग, ट्रस्ट का आपराधिक उल्लंघन, नकली मुद्रा, विदेशी मुद्रा का उल्लंघन और सीमा शुल्क कानून, नशीले पदार्थों और नशीली दवाओं की तस्करी, हथियारों की तस्करी, सांस्कृतिक संपत्ति की चोरी, अपमिश्रण, चोरबाज़ारी, आदि के मामलों की जांच करता है। विशेष अपराध विभाग आतंकवाद, हत्या, हत्या का प्रयास, बलात्कार, दंगों, जासूसी, अपहरण, हथियारों की तस्करी, अवैध आप्रवासन, डकैती, लूट, महिलाओं के खिलाफ अपराध, संगठित अपराधों से संबंधित अपराधों आदि की जांच करता है ।

कानूनी प्रभाग सहायक जांचकर्ताओं को सलाह देता है और अदालतों में मामलों के अभियोजन पक्ष का आयोजन करता है। समन्वय प्रभाग अंतरराज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय विध्वंस के अपराधों पर जानकारी एकत्रित करता है और प्रसारित करता है, सम्मेलन आयोजित करता है। सीबीआई बुलेटिन प्रकाशित करता है, इंटरपोल के साथ संपर्क बनाए रखता है जिसके माध्यम से जांच में यदि विदेशी सहायता की आवश्यकता हो तो उसकी सहायता ली जा सके और सीबीआई की प्रशिक्षण अकादमी की देखभाल होती है।

सीबीआई की फील्ड स्थापना जोन्स में विभाजित है। प्रत्येक जोन का नेतृत्व आईजीपी के पद के अधिकारी द्वारा की जाती है। पूरे देश में दस जोन हैं। इसके अलावा, अखिल भारतीय अधिकार क्षेत्र के साथ कुछ केंद्रीय जांच क्षेत्र दिल्ली में स्थित हैं। ज़ोन में प्रत्येक शाखा को आमतौर पर एसपी के पद के अधिकारी द्वारा देखा जाता है। शाखाओं के काम की निगरानी करने के लिए, क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक होते हैं।

जांच की सीबीआई की कानूनी शक्तियां दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, 1946 (डीएसपीई अधिनियम) से ली गई हैं। संगठन डीएसपीई अधिनियम की धारा 3 के तहत केवल केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए अपराधों की जांच कर सकता है।[95] अधिनियम अधिकारियों को वे सभी शक्तियों, कर्तव्य, विशेषाधिकार और देनदारियां प्रदान करता है जो शक्तियां क्षेत्र के पुलिस अधिकारी के पास हैं।[96]

संगठन राज्य की सरकार की सहमति के बगैर राज्य के किसी भी क्षेत्र में अपनी शक्तियों और क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। सीबीआई के पास राज्य में अपराध जांच

95 दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, 1946, धारा 2 (2), 5 (2) और 3

96 इबिड, धारा 6

कार्य करने का मूल क्षेत्राधिकार नहीं है। अगर राज्य सरकार सीबीआई को आमंत्रित नहीं करती है तो सीबीआई वहां जाँच नहीं कर सकती है, ऐसे में वहां जाँच की अनुमति प्राप्त करने का एकमात्र तरीका यह है की जब उच्चतम या कुछ उच्च न्यायालय ऐसा करने का आदेश दे । अदालतों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान के तहत अपने दायित्व और कर्तव्यों के आधार पर यह शक्ति मिली हुई है।

सीबीआइ संगठन के प्रमुख को निदेशक कहा जाता है। वह किसी राज्य कैडर से प्रतिनियुक्ति पर एक आईपीएस अधिकारी होता है। उन्हें विशेष निदेशक और एडिशनल निदेशक और कई संयुक्त निदेशकों के पद के अधिकारियों द्वारा सहायता दी जाती है।

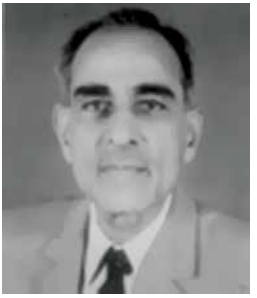

LoxÊ; Jh Mh ih dkgyh] lhchvkÃ d lLFkkid fun'kd

चित्र का स्रोतः *http%@@cbi-nic-in@history-php*

हालांकि सीबीआई लंबे समय से अस्तित्व में है, फिर भी यह पुरानी दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, 1946 द्वारा शासित है। इस अधिनियम की धारा 4 (1) केंद्र सरकार को संगठन पर अधीक्षण की शक्ति प्रदान करता है। कार्मिक, लोक शिकायतें और पेंशन मंत्रालय का कार्मिक विभाग अधीक्षण करता है। हालांकि, केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 आयोग में अधीक्षण निहित करता है, लेकिन केवल भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत अपराधों की जांच के संबंध में। इस प्रकार सीबीआई पर दोहरी नियंत्रण प्रणाली है – भ्रष्टाचार के मामलों में केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा उपयोग किया जाता है और दूसरा अन्य कार्य के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा।

4.4.2.3 leUo; fun'kky;] ifyl ok;jyl

एक स्वतंत्र और भरोसेमंद पुलिस दूरसंचार प्रणाली की आवश्यकता भारत सरकार ने 1946 में ही महसूस की थी जब गृह मंत्रालय के तहत वायरलेस इंस्पेक्टरेट की स्थापना की गई थी। बाद में 1950 में इस इंस्पेक्टरेट को समन्वय निदेशालय, पुलिस वायरलेस (डीसीपीडब्ल्यू) का नाम दिया गया।

संगठन का नेतृत्व निदेशक द्वारा होता है, जिसे एडिशनल निदेशक (मुख्यालय) और एडिशनल निदेशक (संचालन) द्वारा सहायता दी जाती है। उनमें से प्रत्येक के पास जिम्मेदार क्षेत्रों की देखभाल के लिए दो संयुक्त निदेशकों और उप–सहायक निदेशकों के पद के अन्य अधिकारी भी होते हैं।[96]

संगठन पूरे देश में पुलिस टेली–संचार नेटवर्क की स्थापना के समन्वय के लिए ज़िम्मेदार है। यह प्रमुख पुलिस दूरसंचार संगठन है, जो अपने अंतरराज्यीय पुलिस वायरलेस स्टेशनों (आईएसपीडब्लू) और राष्ट्रीय राजधानी को महत्वपूर्ण संचार प्रदान करता है। यह कानून और व्यवस्था से संबंधित उभरते संदेश देने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सभी राजधानियों में अपने 31 स्टेशनों के माध्यम से आईएसपीडब्लू नेटवर्क संचालित करता है।

डीसीपीडब्ल्यू देश में पुलिस दूरसंचार से संबंधित मामलों और देश में पुलिस बलों में शामिल होने के लिए संचार उपकरणों के लिए तकनीकी विनिर्देशों को निर्धारित करने के लिए गृह मंत्रालय के लिए एक सलाहकार निकाय है।

निदेशालय राज्य पुलिस संगठनों को सिफर दस्तावेज प्रदान करता है और सरकार के वर्गीकृत संदेशों को सिफर कवर प्रदान करता है।

यह राज्य और केंद्रीय पुलिस दूरसंचार संगठनों को अपने केन्द्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से बुनियादी और उन्नत प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।

4.4.2.4 vklpuk C;jk

आसूचना ब्यूरो (आईबी) दुनिया की सबसे पुरानी आसूचना एजेंसी है। इसे 23 दिसंबर 1887 को "भारत में गुप्त और राजनीतिक आसूचना के संग्रह" के लिए लंदन में भारत के विदेश सचिव के आदेश से केन्द्रीय विशेष शाखा के रूप में स्थापित किया गया था। यह 127 साल से अधिक पुराना है। 1902–03 के भारतीय पुलिस आयोग के की सिफारिश के बाद, संगठन का नाम बदलकर केंद्रीय आपराधिक आसूचना विभाग रखा गया। धीरे–धीरे, संगठन के सुरक्षा कार्यों ने आपराधिक काम के संबंध में अपनी जिम्मेदारियों को खत्म कर दिया। इसलिए 1918 में "आपराधिक" शब्द को इसके नाम से हटा दिया गया था। इसके वर्तमान नाम आसूचना ब्यूरो को 1920 में अपनाया गया था।

संगठन का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय श्री टी जी संजीव पिल्लई थे, जिन्हें 12 अप्रैल 1947 को निदेशक आईबी नियुक्त किया गया था और वे इस पद पर 14 जुलाई, 1950 तक रहे। उनके उत्तराधिकारी श्री बी एन मलिक थे। स्वतंत्रता के बाद आईबी के प्रमुख के रूप में उनका सबसे लंबा कार्यकाल था और वह आमतौर पर स्वतंत्र भारत में "इंटेलिजेंस के पिता" के रूप में पहचाने जाने लगे। वह 15 जुलाई 1950 से 9 अक्टूबर 1964 तक इस पद पर बने रहे।

आईबी का मुख्य कार्य संवेदनशील भूमि और समुद्र सीमाओं पर सतर्कता बनाए रखने के साथ–साथ राजनीतिक विध्वंस, जासूसी, प्रारंभिक विद्रोह, विद्रोह, आतंकवाद और सुरक्षा संबंधी समस्याओं के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। इसे संबंधित अधिकारियों को समय पर खुफिया जानकारी प्रसारित करना और देश और उसके संस्थानों की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरों का सामना करने के लिए रणनीतियों को अपनाना होता था।

आजादी के बाद काफी समय के लिए, आईबी केंद्र में एकमात्र संगठन था जिसके पास पुलिस विशेषज्ञता थी और इसलिए उसे केवल एक खुफिया संग्रह एजेंसी के रूप में काम करने के साथ साथ पुलिस मामलों पर भारत सरकार के सलाहकार निकाय के रूप में भी काम करने की आवश्यकता थी।

बाद में केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो और बीपीआरएंडडी जैसे केन्द्रीय पुलिस संगठनों की स्थापना के बाद पुलिस से संबंधित इसके अधिकतर कार्य इन संगठनों को हस्तांतरित कर दिए गए। फिर भी आसूचना ब्यूरो, अब भी पुलिस के समक्ष आ रही समस्याओं पर चर्चा करने और उसका समाधान सुझाने के लिए देश के पुलिस बल के प्रमुखों की वार्षिक बैठक आयोजित करता है।

आसूचना ब्यूरो का दायित्व विदेशी खुफिया जानकारी इक्ट्ठा करना भी था। वर्ष 1969 में आसूचना ब्यूरो से रिसर्च एंड एनलाइसिंग विंग (रॉ) बनाया गया और उसे यह जिम्मेदारी सौंपी गयी।

4.4.2.5 jk"Vh; vijkèk fjd,M~l C;jk

निम्नलिखित चार इकाइयों के विलय के माध्यम से 1986 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉड्र्स ब्यूरो (एनसीआरबी) का गठन किया गया थाः

1. पुलिस कंप्यूटर्स का समन्वय निदेशालय
2. सीबीआई का अपराध रिकॉड्र्स अनुभाग
3. सीबीआई का केंद्रीय फिंगर प्रिंट ब्यूरो
4. बीपीआर और डी का सांख्यिकीय खंड

संगठन की अध्यक्षता एक महानिदेशक द्वारा की जाती है, आईजी रैंक के दो संयुक्त निदेशकों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जो विभिन्न शाखाओं का नेतृत्व करता है। एक सांख्यिकीय, प्रशासन, प्रशिक्षण और अपराध रिकॉड्र्स शाखाओं की देखभाल करता है। दूसरा अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (सीसीटीएनएस) शाखा, केंद्रीय फिंगर प्रिंट ब्यूरो शाखा (सीएफपीबी) और डाटा सेंटर क्रियाकलाप (डीसीटी) शाखा का प्रभारी है।

एनसीआरबी के मुख्य कार्य हैंः

I) अपराध और अपराधियों पर जानकारी के एक समाशोधन गृह के रूप में कार्य करता है
II) अंतर–राज्य और अंतरराष्ट्रीय अपराध और अपराधियों पर जानकारी का संग्रह, समन्वय और प्रसार
III) अपराध आंकड़े एकत्रित, संकलित और प्रकाशित करता है
IV) राज्यों में अपराध रिकॉड्र्स ब्यूरो को विकसित और संशोधित
V) पुलिस संगठनों के लिए कंप्यूटर आधारित सिस्टम विकसित करना और कम्प्यूटरीकरण के लिए उनके डेटा प्रोसेसिंग और प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करना
VI) उंगली प्रिंट रिकॉर्ड के भंडार के रूप में कार्य करना

एनसीआरबी ने देश भर में जिला अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो और राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो में 762 सर्वर–आधारित कंप्यूटर सिस्टम स्थापित किए हैं। इसने अपराध और अपराधियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने और प्रसारित करने के लिए सिस्टम तैयार किए हैं। अपराध और आपराधिक सूचना प्रणाली (सीसीआईएस), जिसे 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में और केंद्रीय स्तर पर लागू किया जा रहा है, इंटरनेट के माध्यम से कहीं भी अपराध और आपराधिक जानकारी उपलब्ध कराती है। यह न केवल जांच कार्यों में बल्कि अन्य पुलिस गतिविधियों में भी पुलिस अधिकारियों के लिए उपयोगी साबित होती है।

अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (सीसीटीएनएस) एक पहल है, जिसके पूरी तरह कार्यान्वित होने के बाद पुलिस स्टेशन स्तर पर और पुलिस स्टेशनों, राज्य मुख्यालयों और केंद्र के बीच डेटा संग्रह, भंडारण, पुनर्प्राप्ति, विश्लेषण, हस्तांतरण और साझा करना सुलभ हो जाएगा। यह अपराधों की तेजी से और अधिक सटीक जांच और अपराधियों की पहचान, विभिन्न इकाइयों के बीच जानकारी तेजी से साझा करना; और नागरिकों द्वारा शिकायतों की आसान फाइलिंग के लिए जांच अधिकारी को उपकरण, प्रौद्योगिकिय और सूचना प्रदान करेगा।

एनसीआरबी की पोर्ट्रेट बिल्डिंग सिस्टम (पीबीएस) प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी व्यक्तियों के चित्रों की तैयारी करके पुलिस एजेंसियों के जांच अधिकारी की सहायता करती है।

एनसीआरबी के केंद्रीय फिंगर प्रिंट ब्यूरो (सीएफपीबी) ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अपराधियों के फिंगरप्रिंट का डेटाबेस बनाए रखा है जो मामलों को हल करने में मदद करता है।

एनसीआरबी ने चोरी के वाहन की स्थिति के बारे में आम जनता को जानकारी प्रदान करने के लिए नई दिल्ली में अपने मुख्यालय में मोटर वाहन सत्यापन काउंटर भी स्थापित किया है। काउंटर पुराने वाहन की संभावित खरीदार में यह जानने के लिए मदद करता है कि वाहन चोरी का तो नहीं है या किसी अपराध में शामिल तो नहीं है।

हर साल, एनसीआरबी तीन महत्वपूर्ण प्रकाशन प्रकाशित करता है– (i) भारत में अपराध (ii) भारत में जेल सांख्यिकी और (iii) भारत में दुर्घटनाग्रस्त मौत और आत्महत्या।

भारत में अपराध इस देश में अपराध पर अपनी तरह का सबसे व्यापक और आधिकारिक प्रकाशन है। प्रकाशन में भारतीय दंड संहिता और स्थानीय और विशेष कानूनों के महत्वपूर्ण शीर्षों के तहत विभिन्न राज्यों और यूनियन टेरीटरीज़ में अपराध की घटनाओं गिरफ्तारी और रिहाई दरों को इंगित करने वाली पुलिस और अदालतों द्वारा इसका निपटान; इन कानूनों के तहत गिरफ्तार और रिहा किए गए व्यक्तियों की संख्या; हिंसक अपराधों की घटनाएं; महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध; किशोर अपराध की घटनाएं; संपत्ति चोरी और बरामद; आर्थिक अपराध; साइबर अपराध; पुलिस फायरिंग और हताहत; कर्तव्य के दौरान मारे गए और घायल हो गए पुलिसकर्मी; अभिरक्षा में अपराध; पुलिस कर्मियों के खिलाफ शिकायतें; और पुलिस की संख्या और व्यय पर डेटा शामिल है।

भारत में जेल आंकड़े जेलों, कैदियों और जेल बुनियादी ढांचे के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।

दुर्घटना में मौत और आत्महत्या, दुर्घटनाओं और आत्महत्या के कारण मौतों के बारे में जानकारी देती है।

4.4.2.6 ykd uk;d t ;çdk'k ukjk;.k jk"Vªh; foKku lLFkku vkj Qkjafl d foKku

लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान और फोरेंसिक साइंस (एनआईसीएफएस) मूल रूप से बीपीआर और डी के हिस्से के रूप में 1973 में भारत सरकार द्वारा क्रिमिनोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस के केंद्रीय संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। इसे बीपीआरडी से हटा दिया गया था और 1976 में गृह मंत्रालय में

एक स्वतंत्र संगठन की स्थिति दी गई थी। इसकी स्थिति 1991 में राष्ट्रीय संस्थान के रूप में अपग्रेड की गई थी, और 2003 में इसका नाम लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर रखा गया था।

एनआईसीएफएस का चार्टर 25 सितंबर 1976 के भारत सरकार के संकल्प में परिभाषित किया गया था। इसकी भूमिका अपराध विज्ञान और फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में जानकारी में वृद्धि; पुलिस, न्यायपालिका और सुधार सेवाओं में अधिकारियों के लिए सेवा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना; और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के लिए अपराध विज्ञान और फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में एक संदर्भ निकाय के रूप में कार्य करना है। संगठन के प्रयास और संसाधन आपराधिक न्याय प्रणाली के कार्यकर्ताओं के लिए सेवा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने पर केंद्रित हैं। संस्थान गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के साथ संबद्धता में अपराध विज्ञान और फोरेंसिक विज्ञान में एमए/एमएससी पाठ्यक्रम भी प्रदान करता है।

संस्थान के निदेशक –आईपीएस से प्रतिनियुक्ति पर एक पुलिस अधिकारी होते हैं। डीई के पद के एक अधिकारी आईजी प्रशासनिक और अन्य काम में उनकी सहायता करता है। इसमें दो संकाय हैं: अपराध विज्ञान और फोरेंसिक विज्ञान। अपराध विज्ञान संकाय का नेतृत्व एक प्रोफेसर द्वारा किया जाता है, जो अपराध विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और कानून विभागों के काम की देखरेख करता है। फोरेंसिक साइंसेज के संकाय के प्रमुख संस्थान के एडिशनल निदेशक होते हैं। इस संकाय में छह डिवीजन शामिल हैं – बैलिस्टिक, जीवविज्ञान, दस्तावेज, रसायन शास्त्र, भौतिकी और फोटोग्राफी, प्रत्येक का नेतृत्व सहायक निदेशक के पद के अधिकारी करते है। इसके अलावा, जूनियर वैज्ञानिक सहायक, प्रयोगशाला सहायक और परिचर भी हैं।

4.4.2.7 jk"Vªh; tkap ,tsalh

मुंबई पर 26/11 के आतंकवादी हमले के बाद, भारत सरकार ने महसूस किया कि आतंकवाद से कई मोर्चों पर लड़ने की आवश्यकता है और एक सुस्थापित राष्ट्रीय एजेंसी आतंकवाद से लड़ने के लिए राज्य पुलिस बलों की तुलना में यह काम अधिक तेज़ी और कुशलतापूर्वक कर सकता है। तदनुसार सरकार ने 31 दिसंबर 2008 को एनआईए की स्थापना की राष्ट्रीय एजेंसी की अध्यक्षता एक महानिदेशक पुलिस द्वारा की जाती है, जिसे एक विशेष महानिदेशक और अपर महानिदेशक द्वारा सहायता दी जाती है। इसके अलावा, पुलिस महानिरीक्षक के पद के चार अधिकारी हैं, जिनमें से एक प्रशासन और प्रशिक्षण की देखभाल करता है।

फील्ड प्रतिष्ठान में हैदराबाद, गुवाहाटी, कोच्चि, लखनऊ और मुंबई में स्थित पांच शाखा कार्यालय शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक एक डीआईजी की अध्यक्षता में है। इन शाखाओं को जांच इकाइयों में विभाजित किया गया है, जिसका नेतृत्व पुलिस अधीक्षक के पद के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। कानूनी कार्य की देखभाल एक उप कानूनी सलाहकार द्वारा की जाती है, जिसे एक वरिष्ठ और अन्य सरकारी अभियोजकों द्वारा सहायता दी जाती है।

सरकार ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किए गए अपराधों के परीक्षण के लिए विशेष अदालतों को अधिसूचित किया है।

इसके कुछ कार्य हैं:

- जांच के नवीनतम वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके अधिसूचित अपराधों की जांच;
- तेजी से और प्रभावी परीक्षण सुनिश्चित करना;
- आतंकवादी अपराधों की जांच में अन्य जांच एजेंसियों की सहायता करना;
- आतंक संबंधी मामलों पर व्यापक डेटा बेस बनाना और इस डेटा को राज्य पुलिस बलों और अन्य एजेंसियों के साथ साझा करना; तथा
- नियमित रूप से मौजूदा कानूनों की पर्याप्तता का मूल्यांकन करना और आवश्यक परिवर्तनों का सुझाव देना।

एनआईए अधिनियम केंद्र सरकार में एजेंसी के अधीक्षण को निहित करता है।[97] अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को अधिसूचित अपराध के बारे में सूचित करने की आवश्यकता है।[98] केंद्र सरकार को यह तय करना है कि यह अधिसूचित अपराध है या नहीं, दूसरी बात यह है कि क्या यह एक उचित मामला है एजेंसी द्वारा जांच के लिए।[99] अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार एजेंसी को इस अपराध की जाँच के सौंपने के बाद, इस मामले की जाँच में आगे नहीं बढ़ सकती ।[100]

4.4.2.8 ljnkj oYyHkHkkÃ iVy jk"Vh; ifyl vdkneh

भारत के पहले उप प्रधान मंत्री (1947–1950) सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम पर राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एनपीए) नामित देश में प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण संस्थान है। एनपीए भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षित करता है। यह वर्तमान में हैदराबाद में स्थित है। इससे पहले, इसे सेंट्रल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज (सीपीटीसी) कहा जाता था और राजस्थान में माउंट आबू में स्थित था।

अकादमी के मिशन वक्तव्य के मुताबिकः "अकादमी का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय पुलिस के लिए नेतृत्व को तैयार करना है, जो सेना को साहस, ईमानदारी, समर्पण और लोगों की सेवा की मजबूत भावना के साथ नेतृत्व करेंगे।"[101]

एनपीए की प्रशिक्षण गतिविधियों पर 'आईपीएस अधिकारियों का प्रशिक्षण "(2.7.3) के अंतर्गत पहले ही चर्चा की जा चुकी है

अकादमी की अध्यक्षता पुलिस महानिरीक्षक के पद के आईपीएस अधिकारी द्वारा की जाती है और पुलिस महानिरीक्षक के पद के दो संयुक्त निदेशक, पुलिस के डीआईजी के पद के सात उप निदेशक और 13 सहायक निदेशकों द्वारा उनकी सहायता की जाती है। संकाय की स्वीकृत शक्ति में प्रबंधन में प्रोफेसर, व्यवहार विज्ञान में एक रीडर,

---

97 राष्ट्रीय जांच अधिनियम, 2008, धारा 4 (1)

98 अधिनियम की अनुसूची में दिए गए अपराधों की सूची में परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के तहत अपराध शामिल हैं; गैरकानूनी क्रियाकलाप रोकथाम अधिनियम, 1967; एंटी–हाइजैकिंग एक्ट, 1982; नागरिक उड्डयन अधिनियम, 1986 की सुरक्षा के खिलाफ गैरकानूनी अधिनियमों का दमन; सार्क सम्मेलन (आतंकवाद का दमन) अधिनियम, 1993; महाद्वीपीय शेल्फ अधिनियम, 2002 पर समुद्री नेविगेशन और फिक्स्ड प्लेटफॉर्म की सुरक्षा के खिलाफ गैरकानूनी अधिनियमों का समर्थन; मास विनाश और उनके वितरण प्रणाली के हथियार (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005; और अध्याय टप के अनुभाग 121 से 130 के तहत अपराध और भारतीय दंड संहिता की धारा 48 9–ए से 48 9–ई के तहत अपराध।

99 राष्ट्रीय जांच अधिनियम, 2008, धारा 6 (1) से (3)

100 इबिड, धारा 6 (6)

101 http%@@www-svpnpa-gov-in@/

शिक्षण पद्धति में एक रीडर, दो चिकित्सा अधिकारी, एक जूनियर वैज्ञानिक अधिकारी, एक हिंदी प्रशिक्षक, एक फोटोग्राफ और एक मुख्य ड्रिल प्रशिक्षक भी शामिल है। कुल स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या 692 है।[102]

केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक अकादमी बोर्ड और वरिष्ठ सिविल और पुलिस अधिकारी और प्रतिष्ठित सामाजिक वैज्ञानिक और शिक्षाविद सदस्य शामिल हैं, जो समय–समय पर अकादमी में आयोजित विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण पद्धति की समीक्षा करते हैं। बोर्ड एनपीए के काम और समस्याओं की देखरेख करता है।

102 *http://www.svpnpa.gov.in/about-us/organization*

5 ifyl vkèkfudhdj.k ;kstuk

गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने 1969–70 में अपनी पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की। आरंभ में इसे दस वर्षों की अवधि के लिए पेश किया गया था, लेकिन यह अभी भी लागू है और स्थापित होने के बाद से इसमें कई बदलाव हुए हैं।

5.1 ;kstuk dk mís';

इस योजना का उद्देश्य राज्य पुलिस बलों को अपने प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे को मजबूत करके और आवश्यक गतिशीलता, आधुनिक हथियार, फोरेंसिक विज्ञान सहायक उपकरण, संचार उपकरण, डेटा प्रोसेसिंग मशीनों और इमारतों के साथ उन्हें आधुनिक बनाना है। इसके दो उद्देश्य हैः कानून और व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा मोर्चे पर नई उभरती चुनौतियों को पूरा करने में राज्य पुलिस बलों की प्रभावशीलता में सुधार करना और इस तरह की स्थितियों के दौरान सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों पर उनकी निर्भरता को कम करना।

5.2 lf{kIr bfrgkl

जब योजना 1969–70 में पेश की गई थी, केंद्र सरकार द्वारा दी गई सहायता का पैटर्न 75ः ऋण और 25ः अनुदान था। 1973–74 में, यह छठी वित्त आयोग की सिफारिशों पर 50ः अनुदान सहायता और 50ः ऋण में बदल दिया गया था।

योजना के पहले चरण में, 1969–70 से 1977–78 तक राज्य सरकारों को 43.84 करोड़ रूपये जारी किए गए जो अपराध रिकॉर्ड के लिए डेटा प्रोसेसिंग मशीन खरीदने ; फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिए उपकरण, फिंगरप्रिंट ब्यूरोज़, पूछताछ दस्तावेजों की जांच के लिए केंद्र और जांच के लिए वैज्ञानिक सहायक उपकरण; पुलिस के लिए वायरलेस उपकरण; पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उपकरण; और पुलिस गतिशीलता में वृद्धि के लिए वाहन खरीदने के लिए था।[103]

राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने सिफारिश की कि इस योजना को 1978–79 से दस साल की अवधि के लिए बढ़ाया जाए और जिसमें धन आवंटन में पर्याप्त वृद्धि होगी।[102] भारत सरकार ने 1989–90 तक इस योजना पर रु 100 करोड़ रुपये की राशि इस चरण के दौरान लगाई। राज्यों को 89.29 करोड़ रूपए जारी किए गए थे।

इस योजना का तीसरा चरण भी शुरू किया गया जो 1991 से 2001 तक चला। इसमें व्यय की राशि में वृद्धि की गई और 1991–1995 के 5 वर्ष की अवधि के दौरान 120

103 नैशनल पुलिस कमिशन, तीसरी रिपोर्ट, जनवरी 1980, पृ. 40
104 *Ibid, p 41*

करोड़ रुपए जारी किए गए। वर्ष 1996–97 में राशि में 50 करोड़ की वृद्धि की गई जिसे 1999–2000 में और बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए किया गया।

निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार राज्यों को धन आवंटित किया गया थाः

ekunaM	egRo
• राज्य की जनसंख्या	35%
• पुलिस की स्वीकृत संख्या	25%
• पुलिस स्टेशनों की संख्या	15%
• प्रति लाख आबादी अपराध	25%

इस चरण के दौरान आइटम वार आवंटन भी तय किया गया था। यह निम्नानुसार थाः

vkbVe	vkoaVu dsçfr'kr
पुलिस प्रशिक्षण – भवन और उपकरण	20
फोरेंसिक विज्ञान – भवन और उपकरण	20
हल्के हथियार/भीड़ नियंत्रण के लिए सहायक उपकरण/ यातायात नियंत्रण/वीवीआईपी सुरक्षा	20
नए वाहनों की खरीद	20
संचार	10
जांच/डेटा प्रसंस्करण/कार्यालय के लिए सहायता उपकरण	10

2001 में, सरकार ने वार्षिक आवंटन बढ़ाकर 2000–01 से 1000 करोड़ रूपए कर दिया था। 2005 में योजना की समीक्षा में, राज्यों को दो समूहों में वर्गीकृत किया गया थाः 'ए' और 'बी' जम्मू–कश्मीर और सभी आठ उत्तर पूर्वी राज्यों को श्रेणी 'ए' में शामिल किया गया था जिसमें उन्हें 100ः केंद्रीय सहायता की अनुमति दी और शेष 19 राज्यों को 'बी' श्रेणी में रखा गया, जिसने उन्हें 75ः सहायता की अनुमति दी। पांच राज्यों के लिए प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपये प्रति प्रभावित जिले की दर से, नौ राज्यों के 76 नक्सली प्रभावित जिलों में पुलिस बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक विशेष घटक पेश किया गया था। 2005–06 से इस योजना में भारत–नेपाल और भारत–भूटान सीमाओं पर स्थित 30 जिलों के लिए 5 साल की अवधि के लिए प्रति जिला प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपये का एक विशेष प्रावधान शामिल किया गया था। योजना के तहत मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और अहमदाबाद, सात शहरों को कवर करने वाली मेगा सिटी पॉलिसिंग (एमसीपी) की एक नई योजना 2005–06 में पेश की गई थी।

इस योजना के तहत विभिन्न राज्यों को 2000–01 से 2009 –10 तक कुल 10,086.83 करोड़ रुपये का फण्ड जारी किया गया।[105]

105 इस अनुच्छेद में पूरी जानकारी पुलिस बल आधुनिकीकरण (एमपीएफ) योजना पुस्तक से ली गई है, 9 नवंबर, 2010 को भारत सरकार के गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आधुनिकीकरण प्रभाग द्वारा तैयार किया गया।

भारत सरकार ने 2012–13 से 2016–17 तक पांच साल की अवधि के लिए इस योजना को आगे भी जारी रखा। गैर योजना शीर्ष के तहत 8628.43 करोड़ रूपए की धनराशि और योजना शीर्ष के तहत 3750.87 करोड़ की धन राशि आवंटित की।[106]

गैर योजना व्यय में अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और बेंगलुरु में मेगा सिटी पुलिसिंग[107] के लिए 432.90 करोड़ रुपये शामिल थे

राज्यों को अभी भी दो ही समूहों में बांटा गया है– 'ए' और 'बी', लेकिन वित्त पोषण पैटर्न में बदलाव देखा जा सकता है। जबकि समूह ए राज्यों को 90: केंद्रीय सहायता प्राप्त होती है तथा 10 : स्वयं देना होगा, समूह बी राज्य 60:40 (केंद्रः राज्य) के अनुपात में व्यय साझा करते हैं।

हाल ही में एक और बदलाव आया है। 2014–15 के संशोधित बजट अनुमान के मुताबिक, केंद्र ने लगभग 1,433 करोड़ रुपये योजना के लिए राज्यों को आवंटित किये हैं। एक और धनराशि 537.50 करोड़ रुपये गैर–योजना व्यय के रूप में दिया गया था।

5.3 deh@dfe;k

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने 2000 और 2007 के बीच की अवधि को कवर करने वाली योजना का "कार्य निष्पादन लेखा परीक्षा" की।[108] सीएजी के लेखापरीक्षा ने योजना के कामकाज और उसके प्रभाव में कई कमियों की पहचान की, इनमें से कुछ हैं:

- एमएचए को राज्यों द्वारा रिपोर्ट हमेशा समय पर नहीं भेजे जाते थे
- एमएचए द्वारा दी गई मंजूरी में देरी हुई थी
- वाहनों की संख्या में कुल कमी देखी गई
- कुछ राज्यों में पुलिस प्रतिक्रिया समय बहुत लंबा था
- अधिकांश राज्यों में इमारतों के निर्माण में काफी देरी हुई थी
- राज्यों में पुलिस बल पुराने हथियारों पर निर्भर है
- हथियार की कमी इसलिए थी क्योंकि ऑर्डनेंस कारखानों से खरीद बहुत धीमी थी
- खरीदे गए हथियारों को ज्यादातर जिला मुख्यालय में रखा गया था
- कुछ राज्यों में पुलिस दूरसंचार नेटवर्क सफलतापूर्वक स्थापित नहीं किए गए थे। दूसरों में, नेटवर्क केवल जिला स्तर तक कार्यात्मक था
- विभिन्न संचार उपकरणों की कमी देखी गई
- अधिकांश राज्यों में, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में पर्याप्त आधारभूत संरचना की कमी थी

---

106 प्रशिक्षण, फोरेंसिक प्रयोगशालाओं और पुलिस के लिए वाहनों, हथियारों और उपकरणों पर खर्च किए गए पैसे 'गैर–योजना' व्यय के घटक हैं, जबकि 'योजना' व्यय में पुलिस स्टेशनों और चौकी, पुलिस लाइनों, पुलिस आवास, प्रयोगशालाओं और प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे के निर्माण शामिल हैं (इमारतें)।

107 मेगा सिटी पुलिस व्यय दोनों तकनीकी और गैर तकनीकी घटक हैं। जबकि पूर्व में सीसीटीवी निगरानी, कमांड कंट्रोल सेंटर, डायल 100 सिस्टम, फ्यूजन सेंटर / डाटा सेंटर, राजमार्ग पेट्रोल कारें और एरियल निगरानी शामिल है। गैर तकनीकी उपकरणों में सामुदायिक पुलिसिंग, नम्र कौशल प्रशिक्षण , पुलिस पुरुष और महिलाओं में अनुवांशिक परिवर्तन

108 – पीआरएस ब्लॉग में उद्धृत पुलिस बल के आधुनिकीकरण पर निष्पादन लेखापरीक्षा/ऑडिट समीक्षा का सीएजी संग्रह।

- स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली की कमी, जांच कुछ राज्यों में मैन्युअल रूप से किया गया था।

5.4 lkjk'k

पुलिस आधुनिकीकरण योजना अब लगभग साढ़े चार दशकों से अस्तित्व में रही है। यद्यपि इस योजना के कारण निश्चित रूप से गतिशीलता, संचार और पुलिस को उपलब्ध कुछ अन्य सुविधाओं में सुधार हुआ है, यह योजना राज्य पुलिस बलों को व्यापक आधुनिक रूप देने में सफल नहीं हुई है। इसके कई कारण हैं। आवश्यकताएं बहुत बड़ी हैं और केंद्र सरकार पर्याप्त धनराशि नहीं दे पाई है। पुलिस बल के विस्तार के साथ मुद्रास्फीति के दबाव ने अनुदान में जो भी वृद्धि हुई है, उसके प्रभाव को भी कम कर दिया है। राज्य सरकारों ने अपने बजट से पर्याप्त धनराशि प्रदान नहीं की है। इस योजना के तहत जारी धन का उपयोग प्रभावी नहीं रहा है। इस योजना की निगरानी ने धन का उचित और कुशल उपयोग सुनिश्चित नहीं किया है।

6 vuqyXud

Q,e lwpuk

vkijkfèkd çfØ;k lafgrk dh èkkjk 154 ds rgr fjiksVZ fd, x, lKs; vijkèk dh çFke lwpuk fjiksVZ

पुलिस स्टेशन .... जिला ....

संख्या. .... घटना की तारिख और समय ....

1	रिपोर्ट की गई घटना की तारीख और समय	
2	जानकारी और शिकायतकर्ता का नाम और निवास	
3	अपराध का संक्षिप्त विवरण (धारा के साथ)	
4	घटनास्थल और पुलिस स्टेशन से घटना की दूरी और दिशा	
5	जाँच के लिए उठाए गए कदम, जानकारी रिकार्ड करने में देरी की व्याख्या	
6	पुलिस स्टेशन से प्रेषण की तिथि और समय	

हस्ताक्षर ....

पदनाम ....

lh,pvkjvkbZ dk;ZØe

सीआरआरआई का मानना है कि राष्ट्रमंडल और उसके सदस्य देशों को जवाबदेही और भागीदारी के लिए उच्च मानकों और कार्यात्मक तंत्र के लिए आयोजित किया जाना चाहिए। यह आवश्यक है यदि मानव अधिकार, वास्तविक लोकतंत्र और विकास लोगों के जीवन में वास्तविकता बनें। सीआरआरआई मानव अधिकारों पर रणनीतिक पहल और वकालत, न्याय तक पहुंच और जानकारी तक पहुंच के माध्यम से इस विश्वास को आगे बढाती है। यह अनुसंधान, प्रकाशन, कार्यशालाओं, सूचना प्रसार और वकालत के माध्यम से ऐसा करती है। इसमें तीन प्रमुख कार्यक्रम हैं:

1- U;k; rd igqp

पुलिस सुधारः बहुत से देशों में पुलिस को नागरिकों के अधिकारों के संरक्षक के बजाय राज्य के दमनकारी साधन के रूप में देखा जाता है, जिससे व्यापक अधिकारों का उल्लंघन और न्याय से इनकार किया जाता है। सीआरआईआई प्रणालीगत सुधार को बढ़ावा देती है ताकि पुलिस वर्तमान शासन के साधनों के बजाए कानून के शासन के समर्थकों के रूप में कार्य करे। भारत में, सीआरआई का कार्यक्रम पुलिस सुधार के लिए सार्वजनिक समर्थन को संगठित करना है। दक्षिण एशिया में, सीआरआरआई पुलिस सुधारों पर नागरिक समाज की भागीदारी को मजबूत करने के लिए काम करती है। पूर्वी अफ्रीका और घाना में, सीआरआरआई पुलिस उत्तरदायित्व के मुद्दों और राजनीतिक हस्तक्षेप की जांच कर रही है।

tsy lq/kkj%

सीआरआई का काम परंपरागत रूप से बंद प्रणाली की पारदर्शिता बढ़ाने और कदाचार को उजागर करने पर केंद्रित है। एक प्रमुख क्षेत्र कानूनी व्यवस्था की असफलताओं को उजागर करने पर केंद्रित है, जिसके परिणामस्वरूप भयानक, अतिसंवेदनशील और अनिश्चित रूप से लंबे पूर्व परीक्षण मुकदमे और जेल ओवरस्टेस होते हैं, और इसे कम करने के लिए हस्तक्षेप में कार्यरत हैं। एकाग्रता का एक और क्षेत्र है जेल निरीक्षण प्रणाली को पुनर्जीवित करने का उद्देश्य, जो पूरी तरह असफल रहा है। हमारा मानना है कि इन क्षेत्रों पर ध्यान देने से जेलों के प्रशासन में सुधार आएगा और साथ ही कुल न्याय के प्रशासन पर भी प्रभाव डालेगा।

2- lpuk rd igqp

सीआरआरआई को राष्ट्रमंडल में सूचना तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे मुख्य संगठनों में से एक माना जाता है। यह देशों को सूचना कानूनों का प्रभावी अधिकार को पारित और लागू करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह नियमित रूप से कानून के विकास में सहायता करता है और भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और घाना में सूचना अधिकार कानूनों और प्रथाओं को बढ़ावा देने में विशेष रूप से सफल रहा है। बाद में सीएचआरआई आरटीआई सिविल सोसाइटी गठबंधन का सचिव बना। सीआरआई नियमित रूप से नए कानून की आलोचना करता है और सरकारों और नागरिक समाज के ज्ञान में सर्वोत्तम प्रथाओं को लाने के लिए हस्तक्षेप करता है, शत्रुतापूर्ण वातावरण के साथ–साथ सांस्कृतिक रूप से विविध क्षेत्राधिकारों में काम करने का इसका अनुभव सीआरआरआई को जानकारी के अधिकार पर नए कानूनों को विकसित और लागू करने के इच्छुक देशों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि लाने की अनुमति देता है। घाना में, उदाहरण के लिए यह सूचना तक पहुंच के मूल्य के बारे में ज्ञान को बढ़ावा दे रहा है, जो कानून द्वारा गारंटीकृत है जबकि साथ ही एक प्रभावी और प्रगतिशील कानून की शुरूआत के लिए दबाव डाल रहा है।

3- vUrjk"Vªh; odkyr vkSj çkxkfeZx

सीआरआरआई मानव अधिकार दायित्वों के साथ राष्ट्रमंडल सदस्य राज्यों के अनुपालन और मानव अधिकारों के आस–पास के समर्थकों की निगरानी करता है, जहां ऐसे दायित्वों का उल्लंघन किया जाता है। सीआरआई रणनीतिक रूप से राष्ट्रमंडल मंत्रिस्तरीय कार्य समूह, संयुक्त राष्ट्र और मानव और लोक अधिकारों के अफ्रीकी आयोग समेत क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ संलग्न है। चल रही सामरिक पहलों में शामिल हैं: राष्ट्रमंडल के सुधार की वकालत और निगरानीय संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा में राष्ट्रमंडल देशों के मानवाधिकार वादों की समीक्षाय मानवाधिकार रक्षकों और नागरिक समाज की जगह की सुरक्षा के लिए वकालतय और राष्ट्रमंडल में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के प्रदर्शन की निगरानी करते हुए उनकी मजबूती के लिए वकालत।

पुलिस के राज्य की सबसे सदृष्य शाखा होने के बावजूद भारत में केंद्र व राज्यों में विभिन्न पुलिस बलों के आंतरिक ढांचे और संगठन के स्वरूप के बारे में जनता को बहुत कम ज्ञान है। पुलिस को किस तरह संगठित किया जाता है, कर्मचारियों से लैस, व्यवस्थिति, वित्तपोषित और संचालित किया जाता है या पुलिस संगठनों के आकार, कार्यक्षेत्र और अधिदेश के बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होती। यह किताब सूचना की इस रिक्तता को भरना चाहती है और राज्य तथा केंद्रीय पुलिस बलों, दोनों से सम्बंधित, पुलिस पदों की संरचना और दायित्व, आंतरिक वर्गीकरण, भर्ती, प्रशिक्षण, निरीक्षण और बजट जैसे सभी पहलुओं पर लोगों को विस्तृत जानकारी के व्यापक स्रोत उपलब्ध कराना चाहती है।

Commonwealth Human Rights Initiative
55A, Third Floor
Siddharth Chambers
Kalu Sarai, New Delhi 110 017, India
Tel: +91 11 4318 0200
Fax: +91 11 2686 4688
E-mail: info@humanrightsinitiative.org
Website: www.humanrightsinitiative.org